हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 2.00 बजे अपराह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

23.03.2026/1400/AT/ DC /01

अध्यक्षः प्रश्न काल आरंभ।

स्थगित प्रश्न संख्या-3137

श्री लोकेन्दर कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसमें नीति बनाने के बजाय कोई कानून लाने पर आगे विचार रखती है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भविष्य में कई प्रकार से सरकार विचार करती है और सोचती है। अगर कभी इस पर कोई नीति बनानी होगी तो उस पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष : विचार किया जा सकता है।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि अभी जो एस0एम0सी0 पर लोग नियुक्त हुए हैं। वह पहले टीचर अपॉइंटमेंट हुई है और अब उनको भी रेशनलाइज या ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे पांगी में जो लोग लगे हुए हैं और कुछ लड़के मेरे विधान सभा क्षेचुराह से भी हैं जो वहां पर जॉब कर रहे हैं। उनकी तनख्वाह मात्र सात, आठ, नौ, दस या बारह हजार है।

23.03.2026/1400/AT/DC/02

ऐसा ही अन्य विधान सभा क्षेत्रों में और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी हुआ है। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे कि जो एस0एम0सी0 पर लगे हुए लोग हैं वे डिस्टर्ब न हों क्योंकि वे पहले ही बहुत दूर जाकर सेवाएं दे रहे हैं। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री द्वारा ऐसी हिदायत दी जाएगी कि ऐसे लोग, जिनकी सैलरी पहले ही बहुत कम है और जहां टीचर नहीं हैं वह बात समझ में आती है लेकिन कई लोगों को ऐसे ही डिस्टर्ब किया गया है। तो क्या सरकार द्वारा उनके लिए कुछ किया जाएगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ट्रांसफर नीति से संबंधित प्रश्न था जो माननीय सदस्य ने पूछा है। इसकी जानकारी हमारे पास अभी नहीं है। जब आगे यह सवाल पूछा जाएगा तब हम इन्हें इसकी जानकारी दे देंगे।

अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अपॉइंटीज भी ट्रांसफर हो रहे हैं।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अनेक कर्मचारियों को ट्रांसफर करने की बजाय उन्हें डेपुटेशन पर भेजा गया है। और डेपुटेशन करने की वजह से स्थान तो खाली हैं पर उन्हें भरा नहीं जा सकता क्योंकि व्यक्ति डेपुटेशन पर गया है और तब तक पोस्ट खाली नहीं होती है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हैं जहां डॉक्टरों को डेप्यूट कर दिया गया है। अब वहां न कोई डॉक्टर आ रहे हैं और कोई डॉक्टर आ भी नहीं सकते हैं क्योंकि पोस्ट खाली नहीं है। तो क्या सरकार ऐसे मामलों में उन्हें ट्रांसफर करेगी या उनकी डेपुटेशन रद्द करेगी? क्या सरकार ऐसा करने का आश्वासन देगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह पूरा प्रश्न ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित था, लेकिन माननीय रणधीर जी ने जो पूछा है यह सवाल उससे अलग है। फिर भी, जो डेपुटेशन पर किये जाते है वह कई बार नीतिगत फैसला होता है जब कहीं अधिक आवश्यकता होती है लेकिन बहुत कम मामलों में डेपुटेशन किया जाता है। यदि इन्होंने जो कहा है अगर यह उसकी जानकारी देंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा।

Speaker : In case of urgency.

प्रश्न संख्या-3461 श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

23.03.2026/1405/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या : 3461

अध्यक्ष : श्री राकेश जम्वाल, अनुपस्थित।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मंत्री, विधायक और अधिकारियों के विदेशी दौरों को ले कर है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी सूचना होती है जिसको

एकत्रित करने के लिए समय लगता है। यह पिछले से भी पिछले सत्र का प्रश्न है और ऐसे कितने विदेशी दौरे हो गए कि सूचना एकत्रित की जा रही है? हमने विदेश दौरों के उद्देश्य पूछा, तो उद्देश्य तो पहले तय होता है, तभी विदेशी दौरा होता है? कौन-कौन मंत्री, विधायक और अधिकारी गए, उनके नाम भी पहले तय होते हैं तभी दौरे होते हैं और खर्चा कितना आता है, वह पहले एस्टिमेटिड होता है, बाद में पूरा आ जाता है। तो इसमें ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनकी सूचना अभी एकत्रित नहीं हुई है? अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इसी सत्र में इस प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें कई लोग निजी दौरे पर गए हैं, इन्होंने व्यक्तिगत नहीं पूछा था। जो कई विधायक निजी दौरे पर भी गए हैं, ये सारी सूचना एकत्रित की जाती है और दौरों का सिलसिला कंटीन्यूअस प्रोसैस है। **अभी इस सेशन में कुछ और भी जाएंगे तो यह सारी सूचना आपको आने वाले समय में एकत्रित करके दे दी जाएगी।**

23.03.2026/1405/केएस/डीसी/2

स्थगित प्रश्न संख्या : 3721

अध्यक्ष : श्री सतपाल सिंह सत्ती, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या : 3977

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ शिक्षा खण्ड के अंतर्गत राजकीय उच्च विद्यालय धनेश्वर बहुत ही दूर-दराज वाला क्षेत्र है। मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें कितने रिक्त पद हैं और उनको कब तक भर दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस स्कूल के बारे में बहन रीना कश्यप जी पूछ रही हैं उसमें स्वीकृत पद लगभग 11 हैं जिनमें से 6 पद टीचिंग/नॉन टीचिंग स्टाफ के रिक्त पड़े हैं।

क्योंकि हमारी टी0जी0टी0 के तीनों श्रेणियों के चाहे वह आर्ट्स की बात हो, मैडिकल या नॉन मैडिकल की बात हो, लगभग 1272 पदों की रिक्रूटमैंट का प्रोसैस चयन आयोग हमीरपुर में फाइनल स्टेज पर है जिसमें से टी0जी0टी0 मैडिकल और टी0जी0टी0 नॉन मैडिकल की काउंसलिंग भी हो चुकी है। मैं मुख्य मंत्री जी का और अपनी कैबिनेट के साथियों का भी आभारी हूं कि इस अवधि के दौरान, अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो डायरैक्ट रिक्रूटमैंट के माध्यम से लगभग साढ़े छः हजार से अधिक पद भरे गए हैं और लगभग साढ़े पांच हजार के आसपास पद चयन आयोग, हमीरपुर और पब्लिक सर्विस कमिशन में कैबिनेट के द्वारा भेजे जा चुके हैं। निश्चित रूप में यह काफी बड़ी संख्या है और **मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, रीना कश्यप जी हमारी धैण है, मेरे चुनाव क्षेत्र से सम्बन्ध रखती हैं तो प्राथमिकता के आधार पर आपके टी0जी0टी0 मैडिकल,टी0जी0टी0 नॉन मैडिकल और टी0जी0टी0 आर्ट्स के रिक्त पड़े पदों को भर दिया जाएगा।**

अगला प्रश्न श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी --

23.03.2026/1410/av/hk/1

प्रश्न संख्या : 3978

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था कि पूरे प्रदेश में खुले स्पा सेंटर्ज क्या कानूनी तौर पर चल रहे हैं या उनमें कुछ गैर कानूनी तरीके से भी चल रहे हैं? क्या इन स्पा सेंटर्ज को चलाने हेतु स्वास्थ्य विभाग एन्श्योर कर रहा है या आयुर्वेद विभाग एन्श्योर कर रहा है कि इनमें क्या एक्टिविटीज हो रही हैं? मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि पूरे कुल्लू जिला में केवल 17 स्पा सेंटर्ज हैं। परंतु हम अगर मनाली या कुल्लू की बात करें तो वहां पर हर गली-नुक्कड़ में स्पा सेंटर्ज खुले हुए हैं जबकि उनके पास स्पा सेंटर्ज से संबंधित कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हैं। इन स्पा सेंटर्ज में गैर कानूनी एक्टिविटीज चलने के कारण उनका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। माननीय मंत्री ने कुल्लू में केवल 17 स्पा सेंटर्ज बताए हैं तो मेरी जानकारी के अनुसार मनाली शहर में ही लगभग 170 स्पा

सेंटर्ज होंगे। इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो स्पा सेंटर्ज बिना रजिस्ट्रेशन के खोले गए हैं क्या उनके खिलाफ आने वाले समय में कोई कार्रवाई की जाएगी?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पा सेंटर्ज की रजिस्ट्रेशन के बारे में प्रश्न पूछा है और लेबर विभाग लेबर लॉज के अंतर्गत ही इनकी रजिस्ट्रेशन करता है। हमारा Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 है, हमारे विभाग का तो केवल शॉपिंग एस्टेब्लिशमैंट में किसी प्रकार के लेबर लॉज के उल्लंघन को देखना होता है। हमारा काम वहीं तक सीमित रहता है। हमने जैसे अपने लिखित उत्तर में कहा है कि केवल 61 लोगों ने ही स्पा सेंटर्ज के नाम से रजिस्ट्रेशन की है तो मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि बड़े-बड़े 3, 4 या 5 स्टार होटल्ज को हमारे से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। वे जब अपना होटल टूरिज्म से सैंक्शन करवाते हैं तो उसमें स्पा या दूसरे प्रोविजन्ज ऑलरेडी होते हैं। हमारे विभाग का काम केवल लेबर लॉज के उल्लंघन को देखना होता है। जिला कुल्लू में केवल 17 स्पा सेंटर्ज रजिस्टर्ड हैं जबकि माननीय सदस्य खुद कह रहे हैं कि मनाली शहर में ही 100 से ऊपर खुले हुए हैं। इसलिए बहुत सारे स्पा सेंटर्ज ऐसे हैं जिन्होंने लेबर लॉज में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। मुझे माननीय मुख्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग या आयुष विभाग जोकि मसाज इत्यादि देखता है;

23.03.2026/1410/av/hk/2

इन स्पा सेंटर्ज को रैगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि इनमें गैर कानूनी एक्टिविटीज न हों। अगर इनमें कहीं पर गैर कानूनी एक्टिविटीज हो रही हैं तो it is for the Police department to check. अगर किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमैंट में इस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही हैं तो it is for the Police department to check these things. माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि हम इसके लिए एस0ओ0पी0 बनाकर इसको रैगुलेट करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल डिपार्टमैंट्स इंवॉल्व्ड हैं। इसलिए एस0ओ0पी0 बनाकर इसको ठीक ढंग से रैगुलेट करेंगे ताकि इनका एक सिस्टम, स्टैंडर्ड व लैवल हो।

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि यह एस0ओ0पी0 कब तक लागू की जाएगी क्योंकि जिस प्रकार से मंत्री जी बता रहे हैं कि इस ट्रेड को स्वास्थ्य विभाग या आयुष विभाग देखेगा तो इन पर एक चैक भी रखा जाए। उसमें यह देखा जाए कि ये रजिस्टर्ड स्पा सेंटर्ज क्या-क्या सुविधाएं दे रहे हैं और उन सुविधाओं के अंतर्गत लोगों का किस प्रकार का उपचार होने वाला है?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे अभी कहा है कि it is will take some time. क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने उसमें जैसे सफाई, हैल्थ स्टैंडर्ड या हाईजिनिक इत्यादि it will be looked after by the Health department. अब इसमें आयुर्वेदा विभाग भी इंवॉल्व्ड होता है कि किस प्रकार का स्पा सेंटर है और उसमें हो रही एक्टिविटीज के क्या रेट होने चाहिए; ये सारी-की-सारी एस0ओ0पी0 I can assure you कि मल्टीपल डिपार्टमैंट्स की मीटिंग बुलाकर इनको रैगुलेट करेंगे। अगर स्पेसिफिकली आपको ऐसा लगता है कि किसी स्पा सेंटर में या किसी जगह पर इमोरल एक्टिविटीज हो रही हैं so you can report to the Police.

टी सी द्वारा जारी

23.03.2026/1415/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्या : 3979

श्री विनोद कुमार: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि नाचन विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत नौण में पांच सामुदायिक भवन बन रहे हैं और इन सभी को बनाने पर 21.90 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि ग्राम पंचायत नौण के वार्ड नंबर-। कोट के गलफेर में भी सामुदायिक भवन का काम चला है और इसका कार्य भी पूरा हो चुका है। इसके साथ ही बी0डी0ओ0 के पास इसके पेपर भी सबमिट करवा दिए गए हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इसकी अंतिम किस्त जल्दी दे दी जाए ताकि जो छोटा-मोटा काम उसका शेष रह गया है उसको पूरा किया जा सके।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह काफी विस्तृत दिया गया है। ये सामुदायिक भवन नौण की बात कर रहे हैं जिसके लिए 2 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी और उसमें से डेढ़ लाख रुपये व्यय कर दिए गए हैं। इसमें मु0 50,000 रुपये शेष रहते हैं। शायद आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि डिपार्टमेंट सामुदायिक भवन के लिए पैसे देता है लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए 15वां वित्तायोग, विधायक निधि, एस0डी0पी, एम0पी0 फण्ड या एम0एल0ए0 लैड से पैसा आता है और विभाग केवल एक्सीक्यूटिंग एजेंसी होती है। इसका कार्य बी0डी0ओ0 और ग्राम पंचायत देखती है। इसलिए विभाग इसमें कोई राशि नहीं डाल सकता है। जो इसकी शेष राशि रहती है **उसके संदर्भ में फाइनल बिलिंग करके बैलेंस पेमेंट करने के लिए संबंधित बी0डी0ओ0 को निर्देश कर दिए जाएंगे और वे स्वयं स्पॉट पर जाकर इसका निरीक्षण करेंगे ताकि आचार संहिता से पूर्व इसका कार्य कंप्लीट किया जा सके।**

23.03.2026/1415/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

प्रश्न संख्या : 3980

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ब्यास नदी और चक्की खड्ड पर बाढ़ को रोकने के लिए वहां पर विभाग द्वारा कोई प्रोटेक्शन वर्क की योजना है। पिछले कुछ सालों से लगातार पौंड डैम द्वारा जो एक्सेस वाटर ब्यास नदी में छोड़ा जाता है उसके कारण हमारे फतेहपुर और इंदौरा विधान सभा क्षेत्र को काफी नुकसान हो रहा है। इन दोनों जगह पर हमारा एयरपोर्ट और मिलिट्री हॉस्पिटल भी है। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं और वहां पर हर साल बाढ़ के कारण काफी नुकसान होता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक इन प्रस्तावित परियोजनाओं को पूर्ण कर दिया जाएगा क्योंकि ये दोनों परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है क्योंकि जब से जल जीवन मिशन आया है उसके बाद केन्द्र सरकार ने सारी प्रायॉरिटी उस मिशन में डाल दी है चाहे वह बाढ़ नियंत्रण का कार्यक्रम है या कोई अन्य कार्यक्रम है वे सारे बैक बर्नर पर चले गए हैं। उसके चलते छोंछ खड्ड की जो चैनलाइजेशन चल रही थी उसमें केंद्र सरकार

ने पैसा देना माना था लेकिन वर्ष 2019 में उसका भी पैसा रोक दिया गया। उसमें भी सिर्फ 26 करोड़ रुपये

एन0एस0 द्वारा ... जारी

23-3-2026/1420/एन0एस-वाई0के0-1

प्रश्न संख्या : 3980-----क्रमागत उप-मुख्य मंत्री -----जारी

राशि आई है और शेष राशि नहीं आई है। उसकी भी कोस्ट बढ़ कर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है। चैनलाइजेशन के प्रस्तावों के ऊपर काफी पैसा खर्च किया जाना है जब तक केंद्र की प्राथमिकता नहीं बदलती है तब तक इन्हें आगे बढ़ाना संभव नहीं है।

प्रश्न संख्या : 3981

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के 'ख' भाग में जानना चाहा था कि क्या सरकार महिलाओं को बस किराये में दी जा रही रियायत हेतु कार्ड इश्यू कर रही है और क्या इसे निःशुल्क करने का विचार रखती है? प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि इसके लिए अभी कोई आवेदन नहीं आया है। क्या इसमें सरकार अपनी तरफ से ऐसी मंशा रखती है कि इसको निःशुल्क किया जाएगा? दूसरा, इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है और यदि ऐसा नहीं है तो जो अंतिम तिथि तय की गई है उस समयावधि को खत्म करें ताकि जिसकी जब इच्छा हो वह इस कार्ड को बनवा सके। क्या सरकार कोई ऐसा प्रावधान करेगी?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए बस किराये में 50 प्रतिशत की छूट यथावत जारी है लेकिन कार्ड बनवाना अनिवार्य किया गया है। यह कार्ड इसलिए अनिवार्य किए जा रहे हैं क्योंकि दूसरे प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं वे भी बसों में ट्रैवल कर रहे हैं। यदि सबके पास ट्रांसपोर्ट का कार्ड हो तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इससे यह भी पता लग रहा है कि हमें प्रदेश सरकार से कितनी सब्सिडी लेनी है क्योंकि प्रदेश सरकार एच0आर0टी0सी0 को दो-तीन तरह से सब्सिडाइज करती है और हमें पैसा दिया

जाता है। हमसे सरकार का लगातार प्रश्न रहता है कि आपको किस चीज का पैसा दिया जाए? हमें कार्ड के माध्यम से पता लग रहा है कि कितने लोगों ने बस में रियायती ट्रैवल किया है और हमें उसका बिल बनाने में सहायता मिल रही है। जो लोग बार-बार ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें इस कार्ड के माध्यम से यह भी जानकारी मिल रही है कि लोगों ने कितनी बार ट्रैवल किया है। इसलिए यह एक बार

23-3-2026/1420/एन0एस-वाई0के0-2

200 रुपये देने की बात है और महिलाएं इस कार्ड को बनवा रही हैं तथा लगभग 2 लाख कार्ड बन चुके हैं। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा है कि क्या इसको एक्सटेंड करेंगे? मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह अभी नीतिगत फैसला है और इसके बारे में बोर्ड की मीटिंग में बात होगी लेकिन इतना जरूर है **कि हम सरकारी स्कूलों के बच्चों को रियायत देने के बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में हम शीघ्र ही फैसला करेंगे।**

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार की गारंटी थी कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। जब तक पूरे प्रदेश में यह लागू नहीं हो जाता तब तक उनकी यात्रा, उनके आधार कार्ड को देखते हुए क्या उनको निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 15 लाख रुपये देने की बात की थी तो क्या सारी धरती को शांत कर दिया जाए। ... (व्यवधान) श्री जय राम ठाकुर जी ठीक कह रहे हैं कि काला धन आया नहीं और लोग यहां का पैसा लेकर विदेशों में भाग गए। यह आपकी बात सही है।

अगला प्रश्न 3982-----आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

23.03.2026/1425/RKS/YK-1

प्रश्न संख्याः 3982

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, मैं उससे संतुष्ट हूं।

प्रश्न संख्या : 3983

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसमें बहुत सी जानकारियां उपलब्ध नहीं हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ उठाऊ पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य वर्ष 2010-12 से शुरू हुए थे परंतु ये कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुए हैं। आपने प्रश्न के उत्तर में वर्ष 2010-12 में शुरू हुई 3-4 उठाऊ पेयजल योजनाओं के बारे में बताया है कि इन स्कीमों का कार्य 90-95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। लेकिन मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि विधायक प्राथमिकता की ग्रेविटी योजना जो नोटी खड्ड से कटियाणा के लिए थी उसका न तो उद्घाटन हुआ है और न ही इस स्कीम का कार्य अभी तक पूर्ण हुआ है। इस स्कीम का जिक्र इस उत्तर में नहीं किया गया है। दूसरी, उठाऊ सिंचाई योजना नोटी खड्ड से तारापुर का जिक्र भी इस उत्तर में नहीं किया गया है। जनाहन बस्ती की पेयजल योजना का जिक्र भी इस प्रश्न में नहीं है। इन तीनों स्कीमों में न तो अभी तक पानी पहुंचा है और न ही इनका उद्घाटन हुआ है। ये स्कीमें अभी तक चालू नहीं की गई हैं। जैसे मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में जे0जे0एम0 के अंतर्गत 1.21 अरब रुपये का काम हुआ है लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में उठाऊ पेयजल योजना की एक भी स्कीम का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। वहां पर ट्रांसफार्मर और मशीनरी स्थापित हो चुकी हैं परंतु कुछ योजनाओं के थोड़े-थोड़े कार्य शेष रह गए हैं। अब गर्मी का मौसम आने वाला है। यदि आप इन योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान कर देते तो जिन स्कीमों का कार्य थोड़ा-थोड़ा शेष रह गया है, वे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जिन उठाऊ/सिंचाई पेयजल योजनाओं का कार्य 80-90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है उनके लिए क्या आप बजट का प्रावधान करेंगे ताकि इन स्कीमों का कार्य पूर्ण हो सके?

23.03.2026/1425/RKS/YK-2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में 1040 कार्य अवार्ड किए गए थे जिनमें से 783 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जिन कार्यों के रुके होने या प्रगति पर होने

की आप बात कर रहे हैं उनकी संख्या 257 है। इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए 34 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। जिन कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है उनकी लाइबिलिटीज 32 करोड़ रुपये की हैं। हमें कार्यों को पूर्ण करने के लिए 34 करोड़ रुपये तथा लाइबिलिटीज के लिए 34 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन के तहत आपके विधान सभा क्षेत्र के 6 कार्य 139 करोड़ रुपये के स्वीकृत हुए थे। हमारा जल जीवन मिशन का 1227 करोड़ रुपये रुका पड़ा है। परसों मैंने और मुख्य मंत्री जी ने डिजिटल माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी से इस विषय पर बात की थी। हमने उनसे इस राशि को जारी करने का आग्रह किया है। हमने इस संबंध में जो आवश्यकताएं थीं, उस एम0ओ0यू0 को साइन करके उन्हें भेज दिया है। **आप जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं उनके लिए राशि तो निर्धारित है लेकिन यह राशि जारी नहीं हो रही है। हमें जैसे ही राशि स्वीकृत होगी हम कार्य शुरू करवा देंगे।** माननीय मुख्य मंत्री जी के पास वित्त विभाग भी है, आप इस संबंध में मुख्य मंत्री जी से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। हमारे पास दो ही साधन हैं, या तो आप वित्त विभाग से इसके लिए राशि जारी करवाएंया या फिर केंद्र सरकार से हमें रूकी हुई राशि प्राप्त हो जाएं तभी हम ये कार्य करवा सकते हैं। हमारे विभाग के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम आपको 32 करोड़ रुपये की लाइबिलिटीज दे पाएं।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

23.03.2025/1430/बी.एस./ए.जी.-1

प्रश्न संख्याः 3983 क्रमांगत...उप-मुख्य मंत्री के बाद....

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, उप- मुख्य मंत्री महोदय से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि मेरी लिफ्टें जे0जे0एम0 से बारह की हैं और ये 10-15 साल से कंप्लीट नहीं हुई और इनका कार्य 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। ये नाबार्ड की है और शड्यूलकास्ट कंपोनेट प्लान की है। इन स्कीमों में बहुत काम हो गया और अब थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए।

ये जो लिफ्टें हैं ये कंप्लीट स्टेट फंड से होनी है या नाबार्ड से होनी है? और इन्हें कब तक कंपलीट करेंगे? यही मैं उप-मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

दूसरा, एक कुपवी में हिमकैड की स्कीम थी। उसमें दो करोड़ रुपये कुछ की सैंक्शन हुई थी। उसमें से एक करोड़ रिलीज कर दिया गया है परंतु वहां पर काम कुछ भी नहीं हुआ है। कुपवी के साथ जो गांव है उनके लिए सिंचाई के लिए ये स्कीम थी। मैं इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहता हूं।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके नाबार्ड के दो काम है जिनके लिए 9 करोड़ 76 लाख रुपये की जरूरत है और स्टेट हेड से एम0एल0ए0 कांस्टीट्यूएंसी को खुश करने के लिए काम शुरू करवा देते हैं। यह मुख्य मंत्री जी को पता है और नेता प्रतिपक्ष को भी पता है कि इसमें हर साल पैसा थोड़ा-थोड़ा आता है और ये काम कछुए की चाल से चलते हैं। इसलिए यह 10-12 साल तक लटके रहते हैं। अब हमें आपके एस0सी0डी0पी0 में 1 करोड़ 59 लाख रुपये की जरूरत है। हमने रिक्वेस्ट की है और हिमकैड में भी हमें 2 करोड़ 21 लाख 18 हजार रुपये की जरूरत है। यह भी हमने रिक्वेस्ट की है। हमारे पास जैसे ही पैसा आएगा, हम आपकी स्कीम कंप्लीट करना चाहेंगे। लेकिन यह स्टेट हेड्स में ये स्कीमें जितनी कम बने और नाबार्ड या केंद्र की मदद से पैसा आए तो अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर मेरा आपसे उल्टा से आग्रह है कि आप केंद्र में जो हमारा पैसा फसा है उसमें हमारा सहयोग करवाओ और किसी ढंग से यह आपका सारा काम एक मुश्त निकल जाएगा। अगर पैसा वहां से आता है तो हम तो चाहते हैं कि आपके काम भी निकल जाएं और हाउस के जितने मेंबर्स हैं उनके काम भी निकल जाए। ये 1227 करोड़ रुपये का काम हैं इनमें से आपके 600 करोड़ रुपये के काम हो चुके हैं और 600 करोड़ रुपये के काम ठेकेदारों ने रोकें हैं वे कहते हैं कि जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हमने कोई कान नहीं करने हैं। इसलिए ये स्कीमें अटकी पड़ी है।

23.03.2025/1430/बी.एस./ए.जी.-2

प्रश्न संख्याः 3984

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जाना चाहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणी के कितने पद रिक्त है? तो मैं बताना चाहूंगा कि उप मंडल आनी में 17 में से 8 पद रिक्त हैं और इसी तरह से उप मंडल निरमंड में 14 में से 6 पर रिक्त हैं और तहसील आनी में कुल 29 पदों में से 12 रिक्त हैं। इसी तरह से जो उप तहसील नीथर में 16 में से 10 पद रिक्त है।

प्रश्न के दूसरे भाग में इन्होंने जानना चाहा कि इनके पटवार वृत्त जालोड़ी में पटवारी नहीं है। यहां पटवारी के पास एडिशनल चार्ज है।

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब में सारी चीजें बता दी गई हैं कि मेरे आउटर सिराज आनी विधान सभा क्षेत्र में किस स्थिति में राजस्व विभाग हैं। निरमंड में मैं सिर्फ पटवारियों की बात करना चाहता हूं। क्योंकि सबसे ज्यादा काम राजस्व विभाग में पटवारियों से होता है और पूरे निरमंड में जो 32 पंचायतें हैं। जो हमारा बिल्कुल आगे झाखड़ी के सामने लास्ट सरगा, खरगा और कुशवा की पंचायतें हैं। वहां पर सिर्फ दो पटवारी हैं और नीथर में हमारे पास केवल एक ही पटवारी है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बाकी जो और पद है वह तो बाद की बातें हैं। परंतु जो आनी में मैं जलोड़ी की बात है कि रेगुलर तौर पर यहां कितने समय में पटवारी आ जाएंगे? क्योंकि निरमंड और नीथर में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं और यह काफी दूरदराज का क्षेत्र है। मैं चाहूंगा सर, कि मुझे टेंटेटिव सी डेट बता दी जाए ताकि लोगों तकलीफ दूर हो सके।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

23.03.2026/1435/DT/AG-1

प्रश्न संख्या 3984जारी...

राजस्व मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय,जहां तक पटवारियों के संबंध में प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है उसके संबंध में यही बताना चाहूंगा कि पूर्व सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में कोई नई भर्तियां इस पद पर नहीं की गई। पटवारी के पद पर सलैक्शन के उपरांत उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है फिर तैनाती प्रदान की जाती है। वर्तमान सरकार द्वारा

पटवारी के 600 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रेंनिग के बाद इन पटवारी को तैनाती दी जाएगी। इस बीच की प्रक्रिया में राजस्व संबंधित कार्य प्रभावित न हो इसलिए माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विभाग को अनुमति दी गई है कि जो भी पूर्व में रिटायर पटवारी इच्छुक हो उन्हें 40,000/- रुपये प्रतिमाह के मानदेय में रखते हुए रि-एम्पलॉयमेंट दी जाए।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि कानूनगों के पद पटवारी की पदोन्नति के द्वारा ही भरे जाते हैं। इन पदों को अलग से नहीं भरा जाता। जहां पर कानूनगों की कम हैं उन स्थानों पर भी पूर्व में सेवानिवृत हो चुके इच्छुक कनूनगों को रि-एम्पलॉयमेंट के द्वारा 50,000/- रुपये प्रतिमाह के मानदेय में भरने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से नायब-तहसीलदार व तहसीलदार के पदों को भी रि-एम्पलॉयमेंट के जरिए भरे जाने का प्रस्ताव है इसमें भी क्रमशः 60,000/- रुपये व 70,000/- रुपये प्रतिमहा देने का प्रावधान भी किया गया है। सरकार के द्वारा ये पद खाली होने के कारण लोगों के राजस्व संबंधित कार्य प्रभावित न हो इसलिए यह तरीका निकाला गया है। 7 पटवारी जो पहले किसी समय में चयनित हुए थे लेकिन जिला कैडर होने के कारण वह लाहौल-स्पिति में नहीं लग पाए, उनको भी दोबारा नियुक्ति देने की परमिशन मिल गई है। **उनमें से कुछ पटवारी आपके इलाके में भेज देंगे।**

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार जी आप को सारी जानकारी तो माननीय मंत्री महोदय द्वारा दे दी गई है। अगर आप के पास कोई रिटायर तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, कानूनगों या पटवारी का नाम है और वह पुनः कार्य करने के इच्छुक हैं तो आप मंत्री जी उसका नाम दे देना।

23.03.2026/1435/DT/AG-2

प्रश्न संख्या : 3985

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि, वैसे तो माननीय लोक निर्माण मंत्री भी भली-भांती जानते हैं कि सूंगरी-रोहडू व रामपुर की बाउंडरी पर है और टूरिज्म की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण जगह है वहां से मुरालडंडा का रास्ता भी जाता है। वहां पर जो टूरिज्म रेस्ट हाउस बनना था यह

जब रोहडू में चांसल और खड़ा पत्थर में गिरी का बना था तो उस समय का यह भी प्रस्तावति है। हो सकता है किन्ही कारणों से यह रेस्ट हाउस नहीं बन पाया हो, मुझे जो उत्तर प्राप्त हुआ उसमें लिखा गया हे कि इस भवन को डिसमेंटल करने का निर्णय लिया गया है। मेरा अनुरोध रहेगा कि इसे डिमेंटल करने के बाद क्या इसे दोबारा बनाया जाएगा; और यदि नहीं; तो इस भूमि का क्या प्रयोग होगा? मेरा अनुरोध रहेगा कि इस भूमि का इस प्रकार से उपयोग होना चाहिए कि वहां पर पर्यटन संबंधित गतिविधियां विकसित हों ताकि पर्यटकों के लिए एक अट्रेक्शन सेंटर बने। क्योंकि जिस रोड पर यह रेस्ट हाउस स्थापित है बहुत ही पुरानी रोड है।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न किया गया है यह प्रश्न वैसे तो पर्यटन विभाग से संबंधित है लेकिन जो इसका कार्य है वह लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया है लेकिन इसका पैसा मूल रूप से पर्यटन विभाग के द्वारा दिया गया हैा इस रेस्ट हाउस को डिसमेंटल करने का निर्णय सरकार और विभाग ने इसलिए लिया है क्योंकि It is in a dilapidated condition तो उसको पुनः बनाने पर आने वाले समय में प्रयास किया जायेगा। मैं सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यटन विभाग की ओर से इसमें बजट का प्रावधान किया जाए ताकि सुंगरी क्षेत्र जो हमारे रामपुर और रोहडू का एक एतिहासिक बॉर्डर है और ब्रिटिस काल से ही यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग रहा है इसलिए पर्यटन की दृष्टि से इसे विकसित करना बहुत ही महत्वूपूर्ण है। मैं इसी में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि सरकार को इस बात पर भी सोचना चाहिए कि जितने हमारे एतिहासिक, विशेषकर अंग्रेजों के समय के रेस्ट हाउसिज हैं जो उस समय की इंडो-तिब्बत सड़क थी, उसके ऊपर प्रत्येक डेढ़ मील के बाद रेस्ट हाउसिज बनाए जाते थे और उसका

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

23.03.2026/1440/ए.एस.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या-3985.....जारी लोक निर्माण मंत्री..... जारी

बहुत सारी किताबों में इसको मेंशन भी किया गया है। Rudyard Kipling ने भी अपनी किताबों में इसका अनेक बार जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने लिए पुराने रूट्स, चाहे वे पैदल चलने वाले हों या घुड़सवारी वाले हों, उनको यदि डवलप किया जाए और पर्यटन की दृष्टि से उन्हें सर्किट्स बनाया जाए, तो वे हमारे ग्रामीण पर्यटन को डवलप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण राजस्व जनरेट कर सकते हैं। **Because this will be an added attraction और जिस प्रकार से हमारा पर्यटन अधिकतर शहरी क्षेत्रों में सीमित है और पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए वहां पर कुछ इंसेंटिव्स या एडिड अट्रैक्शन्ज़ होनी चाहिएं। उस दृष्टि से यह मेरी सोच है और इसे हम आने वाले समय में करने का प्रयास करेंगे। हमारे जितने भी पुराने रूट्स हैं, चाहे वे अंग्रेजों के समय के हों या उससे भी पहले के हों, उनको पर्यटन की दृष्टि से डवलप करना चाहिए और वहां पर जितने भी पुराने रेस्ट हाऊसिस हैं, चाहे वे वन विभाग के हों या लोक निर्माण विभाग के हों, उनको भी पर्यटन की दृष्टि से एक सर्किट के रूप में डवलप करने की आवश्यकता है। इस पर आने वाले समय में विचार व कार्रवाई होनी चाहिए।**

23.03.2026/1440/ए.एस.-एन.जी./2

प्रश्न संख्या : 3986

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की गुणवत्ता, चाहे हैण्डपम्प का पानी हो या चाहे एल0डब्ल्यू0एस0एस0 की योजनाएं हैं, उनके द्वारा हमें जो पीने का पानी मिलता है, उसकी गुणवत्ता की जांच कब-कब की जाती है? मैंने अपने प्रश्न में भी पूछा है कि जब हैण्डपम्प लगता है या उसको खोद दिया जाता है तो उसके पानी की गुणवत्ता की जांच कब-कब होती है? इसके अलावा कुछ हैण्डपम्प दो-दो वर्षों से खराब पड़े हैं और जब उनको ठीक करते हैं तो क्या उसके बाद भी उनके पानी की गुणवत्ता की जांच होती है?

क्योंकि जब वह हैण्डपम्प ठीक किया जाता है तो उसमें से अलग रंग का पानी आता है। इसके अतिरिक्त हमारे जो वटर ट्रीटमैंट प्लांट्स हैं या जहां से हम पानी लिफ्ट करते हैं या जिस बैड से पानी को निकाला जाता है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि जंगलों के बीच में खुले पड़े हैं और उसमें बंदर व अन्य जानवर खेलते/नहाते रहते हैं। क्या प्रदेश सरकार ऐसे जल स्त्रोतों की प्रोपर फेंसिंग करने पर विचार करेगी?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के कंसर्न से सहमत हूं। अभी परसों माननीय मुख्य मंत्री ने बजट पेश किया है और उसमें पानी की प्यूरिफिकेशन के लिए 2000 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित की है। हिमाचल प्रदेश में पानी सही मिले, उसके लिए विभाग को एक प्रोजैक्ट बनाने के निर्देश दिए हैं और उसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक या अन्य एजेंसी से की जाएगी। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास कुल 72 लैब्स हैं और उनमें 60 लैब्स मान्यता प्राप्त हैं। ये सभी लैब्स पानी को चैक करती हैं। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इनके ध्यान में यदि कोई लोकेशन्ज़ हैं, जहां पर इन्हें लगता है कि यहां का पानी चैक करवाना चाहिए, वे हमें बता सकते हैं और जैसे ही माननीय सदस्य से सुझाव प्राप्त होंगे वैसे-वैसे हम उन जगहों के पानी की जांच अपनी लैब्स में करवा देंगे।

23.03.2026/1440/ए.एस.-एन.जी./3

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में लगभग 34 हैण्डपम्प लगे हैं। इसका मतलब यह है कि माननीय सदस्य के क्षेत्र में अभी हैण्डपम्प की जरूरत महसूस हो रही होगी। उस बारे में माननीय सदस्य की जो भी राय होगी, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं उप-मुख्य मंत्री महोदय से केवल इतना जानना चाहता हूं क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में या तो कोल डैम से पानी उठाया जाता है या फिर गोविन्द सागर से पानी उठाया जाता है। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि जैसे बरसात आती है

तो उनमें गाद व अन्य पार्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या विभाग द्वारा वहां के पानी को चैक किया जाता है? इसके अलावा क्या विभाग इसको चैक करने का कोई प्रावधान या सैट फार्मुला तय कर सकता है?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **this is suggestion for action और हम इस पर गौर कर लेंगे।**

अगला प्रश्न : श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

23.03.2026/1445/ए0एस0/ए0पी0/-01

प्रश्न संख्या : 3987

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना से संतुष्ट हूं।

Speaker: Shri Deep Raj ji, very good. Very rarely you are satisfied and the Minister should be congratulated you for this.

प्रश्न संख्या : 3988

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब से जल शक्ति विभाग में विश्राम गृहों की बुकिंग ऑनलाइन की गई हैं तब से 88 लाख 71 हजार रुपये का रेवन्यू एकत्रित किया गया है। इससे पहले मैंने लोक निर्माण विभाग से भी प्रश्न किया था और जब से उनमें बुकिंग ऑनलाइन हुई है तब से 3 करोड़ 85 लाख रुपये लोक निर्माण विभाग को रेवन्यू प्राप्त हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद सभी विभागों में लगभग 6 करोड़ 87 लाख रुपये तथा 3 करोड़ 85 लाख रुपये लोक निर्माण विभाग को रेवन्यू प्राप्त हुआ है। इस समय इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद 88 लाख रुपये इस प्रकार प्राप्त हुए हैं। इसी तरह वन विभाग से 1 करोड़ 20 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 6 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। जब से पी0डब्ल्यू0डी0, आई0पी0एच0

और वन विभाग के रेस्ट हाउस ऑनलाइन बुक किए गए हैं तब से यह आय सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही, मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि धर्मपुर क्षेत्र के अंतर्गत कई इंस्पेक्शन हट जैसे भंडार, बनारी, बनौटी, सकलाना, द्वाली, टुंगूहानी, मचियारा, चौरतु, रकलो आदि ऐसी हैं जिनसे शुन्य रेवेन्यू है और इसके साथ में यह भी देखा रहा हूं कि वहां पर बहुत से रेस्ट हाउस ऐसे हैं जिनमें लगभग शून्य रेवन्यू है। ऐसे में आने वाले समय में सरकार इनका किस प्रकार सदुपयोग करेगी और यह भी बताया जाए कि इन पर कितना खर्चा आ रहा है, स्पष्ट किया जाए। धर्मपुर के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न रेस्ट हाउस दिए गए हैं। भविष्य में जो पूरी तरह निष्क्रिय हैं या जिन पर बहुत कम गतिविधि है, क्या उन्हें किसी विभाग को उपयोग हेतु

23.03.2026/1445/ए0एस0/ए0पी0/-02

दिया जाएगा या आउटसोर्स किया जाएगा? इस पर मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का हस्तक्षेप चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह भी उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद लगभग 6 करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग तथा 1 करोड़ 20 लाख रुपये वन विभाग को प्राप्त हुए हैं। वास्तव में यही व्यवस्था परिवर्तन का उदाहरण है कि जो रेस्ट हाउस पहले खाली पड़े रहते थे, उनसे अब 6-7-8 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है। जब हम सभी वहां जाते हैं, तो लोक निर्माण विभाग के पास वही कर्मचारी हैं वे लगभग 1200 रुपये शुल्क लेकर सुविधा प्रदान करते हैं और ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से नियमित आय सुनिश्चित होती है, यह अच्छी बात है। जब एक वर्ष के भीतर लगभग 6.5 करोड़ रुपये की आय इन रेस्ट हाउस से प्राप्त हुई है, तो भविष्य में क्या आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति कर बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी?। साथ ही, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जलशक्ति विभाग के संदर्भ में भी जानना चाहता हूं कि जिन स्थानों पर खर्च अधिक है और रेस्ट हाउस निष्क्रिय खड़े हैं उन्हें भविष्य में किसी अन्य विभाग को सौंपा जाएगा या उनके उपयोग की क्या योजना है? मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक इंस्पेक्शन हट है जिसके बारे में पिछली विधान सभा सत्र में प्रश्न उठाया था और उसके लिए आपने धनराशि प्रदान की थी। उस इंस्पेक्शन हट का लगभग दस प्रतिशत कार्य शेष है। शाहपुर

विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एस0सी0/एस0टी0 मद से जो धनराशि थी, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछली बार लगभग 20 लाख रुपये जारी किए गए थे। अब कुछ कार्य शेष है तो क्या आने वाले समय में उसे भी पूर्ण करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जायेगी, मैं यह जानना चाहता हूं।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि रेस्ट हाउस का मैंडेट पी0डब्ल्यू0डी0 का है, जिसका उद्देश्य लोगों के रहने-ठहरने की व्यवस्था करना है। लेकिन पिछले कुछ समय से यह प्रचलन हो गया है कि जलशक्ति विभाग को भी इस दायरे में शामिल कर लिया है। जलशक्ति विभाग के अंतर्गत कुल मिलाकर 81 विश्रामगृह, किसान भवन या निरक्षण कुटीर जैसे भवन बने हैं। अभी तो हम केन्द्र सरकार से साथ संघर्ष कर रहे हैं कि उन्होंने जल जीवन मिशन में हमारे लगभग 27 करोड़ रुपये काट

23.03.2026/1445/ए0एस0/ए0पी0/-03

लिये है और उन्होंने यह कहा कि आपने इसमें अपने लिए विश्राम गृह बनाए हैं। हम उनसे कह रहे है कि वे सभी विश्राम गृह पिछली सरकार के समय बने हैं। लेकिन 27 करोड़ रुपये का कट पानी में लग गया है, क्योंकि यह पैसा पानी की स्कीम के लिए आना था। हम उनसे संघर्ष कर रहे है कि एक बार प्रदेश को पैसा जारी किया जाए। हमने जनवरी से जलशक्ति विभाग से विश्राम गृहों की बुकिंग को ऑनलाइन कर दिया है। अभी तो मात्र एक से डेढ़ महीना हुआ है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

23.03.2026/1450/AT/DC/01

प्रश्न संख्या 3988 जारी... उप-मुख्यमंत्री जारी...

अभी जितने भी रेस्ट हाउस हैं जिनका उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं वे सभी रेस्ट हाउस उपयोग में आ जाएंगे। सभी ऑनलाइन हैं और पहाड़ी लोकेशनों पर स्थित हैं तो कुछ न कुछ अर्निंग शुरू हो **जाएगी। बाकी इन्होंने जो कहा कि उनके क्षेत्र का रेस्ट हाउस पूरा करवाना है इय प्रश्न की मंशा वही है और हम उसे पूरा कर देंगे।**

Speaker: Hon'ble Chief Minister wants to supplement.

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय PWD से संबंधित सदस्य ने एक सवाल किया है। जब आप खाने-पीने के लिए पैसे ले रहे हैं तो व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए। यह सही बात है कि जहां खाने-पीने की व्यवस्था होगी, वहां कई जगह रेस्ट हाउस से दुकानें काफी दूर होती हैं इसलिए सर्विसेज को आउटसोर्स करना पड़ेगा। हम इस पर कार्य कर रहे हैं कि एक मेन्यू बनाया जाए जिसमें रेट फिक्स किए जाएगे और किसी नजदीकी दुकानदार को यह जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि वह सर्विस संभाले। वह अपना स्टाफ रखे, अपना वेटर रखे और सर्विस रिक्वेस्ट को संभाले।

दूसरी बात, रेस्ट हाउस की सफाई बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हम आउटसोर्स के माध्यम से सफाई की व्यवस्था करेंगे। जहां छोटे-छोटे क्यारियां बनी हैं उन्हें भी सुंदर बनाया जाना चाहिए। इस पर भी हमारी सरकार विचार कर रही है और आने वाले समय में आउटसोर्स के माध्यम से कुछ नियुक्तियां की जा सकती हैं।

23.03.2026/1450/AT/DC/02

प्रश्न- संख्या 3989

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल: अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर जो सूचना रखी गई है जिसमें यह कहा गया है कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत धनराशि के आवंटन हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है यह तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार बड़सर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लगभग 160 मकान अभी भी लंबित पड़े हैं। यह गुमराह करने वाला उत्तर है जिसमें कहा गया है कि कोई भी सूची लंबित नहीं है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ऐसा उत्तर क्यों दिया गया? इन 3 वर्षों में मात्र 22 मकान ही अनुसूचित

जाति के लिए बड़सर विधान सभा क्षेत्र को मिले हैं जबकि इससे पहले पूर्व में जय राम जी की सरकार में वर्ष 2022-23 में लगभग 35 मकान मिले थे। यह कमी क्यों हुई? साथ ही, खंड 'ख' में जो पैसा अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित हुआ है वह बहुत कम है। सड़कों और पानी की योजनाओं पर भी बहुत कम पैसा खर्च हुआ है।... (व्यवधान)

अध्यक्षः यह अनुसूचित जाति है, जनजाति नहीं है।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें दोनों अनुसूचित जाति और जनजाति शामिल हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है वह मेरी भी चिंता है। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि देना चाहता हूं। वर्ष-1975 में यह योजना आरंभ की गई थी और 30 अक्टूबर 2022 के बाद इसे स्वर्ण जयंती नाम दिया गया। पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र एकत्र किए जाते हैं। There is a Committee which includes Member of Parliament, MLAs and all Panchayati Raj representatives. यह इसमें शामिल होते हैं। यह सही है कि इस बार धनराशि बहुत कम मिली है। But I must complement Hon'ble Chief Minister in this august House, who dispatched all

23.03.2026/1450/AT/DC/03

the adversities. He faced all bad circumstances. फिर भी जिन लोगों के घर किसी भी कारण से गिर गए थे या पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे उन्हें 7-8 लाख रुपये दिए गए। आप सभी को इसके बारे में जानकारी है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि शायद गलत आवेदन पत्र आए हैं

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

23.03.2026/1455/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या : 3989 जारी... स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी ---

उनको क्रमवार नहीं देखा गया है, ऐसा नहीं है क्योंकि जो यहां पर हों या दूर-दराज क्षेत्रों में हों जहां पर there is single line administration. ये सारे के सारे पत्र बाकायदा इकट्ठे किए जाते हैं और मैं आपको अभी बता दूं। I agree that there is big pendency. Release of funds against sanction cases सचमुच में बहुत कम हुआ है। However 152 fresh cases are pending for approval जो कि हमारी डिस्ट्रक्ट वैल्फेयर कमेटी तय करती है। वे सारे जब उस कमेटी में आएंगे, उसको पात्रता के आधार पर वहां देखा जाता है। आप जानते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है जैसे अग्निकांड से हो गया या जैसे अभी पीछे त्रासदी आई थी, वह नम्बर-1 हो जाएगा। Secondly, we will have to wait, इसी प्रकार से कोई दिव्यांग हैं, कोई विधवा स्त्री है या कोई बहुत ही गरीब है तो जिस प्रकार की हमारे पास रिकमेंडेशन्ज़ आती हैं, हम लिस्ट बनाते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं है।से मैंने तो अभी तक नहीं देखा परंतु अगर माननीय सदस्य को इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति नज़र आई है and needs clarity; Hon'ble Member you let me know and I shall look into the issue.Thank you.

23.03.2026/1455/केएस/डीसी/2

प्रश्न संख्या : 3990

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मेरा प्रश्न लगा था उसका मुख्य मंत्री जी की तरफ से काफी लम्बा-चौड़ा जवाब आया है। लेकिन यह जिसने बनाया है उसको पूछिए क्योंकि सारे का सारा जवाब गलत बनाया गया है। जैसे यहां पर चुनाव क्षेत्र लिख दिया है ज्वाली और पैसा जा रहा है देहरा को।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए क्योंकि प्रश्न काल समाप्त होने में सिर्फ दो मिनट का समय ही शेष है।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही पूछ रहा हूं लेकिन पहले थोड़ी भूमिका तो बनानी ही पड़ेगी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि पेज नं0-19 में एन0डी0आर0एफ0 में आपने जो पैसा दिया है, जिला कांगड़ा में ज्वाली के लिए 172 लाख रुपये, देहरा के लिए 148 लाख रुपये, फिर देहरा के लिए 110 लाख रुपये, लम्बा गांव के

लिए 112 लाख रुपये और जसवां-प्रागपुर के लिए ज़ीरो। इसके बाद डी0सी0पी0 में भी यही हाल है। बैजनाथ के लिए 63 लाख रुपये, देहरा के लिए 111 लाख रुपये और प्रागपुर के लिए 2 लाख रुपये। इसी तरीके से पेज नं0-19 पर फिर देखिए उसमें भी नगर पंचायत देहरा को 26 लाख रुपये अलग से, 134 लाख रुपये अलग से और जसवां-प्रागपुर के लिए 1.5 लाख रुपये। क्या कारण है कि इतना ज्यादा फर्क है। यह मैं सिर्फ चार-पांच चुनाव क्षेत्रों की तुलना कर पाया हूं क्योंकि यह जवाब लेट मिला है। क्या कारण है कि जसवां-प्रागपुर के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? क्या कारण है कि जो डी0सी0 कांगड़ा हैं, अगर उनको पत्र दिया जाता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती । वे कांग्रेस के एजेंट की तरह काम करते हैं। जो मैंने डाटा दिया है, इसको देखते हुए जिन अधिकारियों द्वारा यह पैसा बांटा गया है, क्या आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे कि जसवां-प्रागपुर के साथ क्यों किया गया?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय हो गया है।

अध्यक्ष : नहीं, अभी दो मिनट शेष है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, फिर हाउस में लगी आपकी घड़ी ठीक करनी पड़ेगी।

23.03.2026/1455/केएस/डीसी/3

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी के सामने वाली घड़ी ठीक नहीं है, इसको ठीक कर देंगे। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : मैंने सोचा कि 3.00 बज गए, प्रश्नकाल समाप्त हो गया तो अध्यक्ष जी से अनुमति ले लूं। इसलिए मैंने बोल दिया कि समय हो गया।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, अभी एक मिनट का समय है। ...(व्यवधान) बिक्रम सिंह जी, मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप बैठ जाओ।

मुख्य मंत्री : बिक्रम सिंह जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। अध्यक्ष जी ने मुझे बोल दिया कि आप जवाब दीजिए। मैंने तो घड़ी की तरफ इशारा किया था। आप इतनी जल्दी गुस्सा

हो जाते हैं। आपको भी पानी पिलाना पड़ेगा। ...(व्यवधान) आप थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, जवाब बड़ा विस्तृत आया है और माननीय सदस्य ने जो अपने विधान सभा क्षेत्र का हाल बताया है, आने वाले समय में जितना कुछ हो सकता होगा, ..(व्यवधान) थोड़ा-बहुत ही निकालकर करेंगे।

प्रश्नकाल समाप्त

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

23.03.2026/1500/av/hk/1

अध्यक्ष : अब मुझे जीरो आवर के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अगर आप सहयोग करेंगे तो ये माननीय सदन के माध्यम से सारी उठाई जा सकती हैं। सर्वप्रथम माननीय सदस्या श्रीमती रीना कश्यप अपना विषय उठाएगी।

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अपना विषय उठाने हेतु समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं शून्यकाल में अपने विषय के अंतर्गत यह कहना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश के बन्दोबस्त विभाग में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कार्ड ऑपरेटर्ज का कार्य अनुबन्ध दिनांक 28 फरवरी, 2026 को समाप्त हो चुका है। जबकि ये हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 10 वर्षों से राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और आधुनिक मानचित्र तैयार करने का कार्य कर रहे थे। परंतु इन सभी का एग्रीमैंट समाप्त होने के कारण इनके समक्ष जो बेरोज़गारी की स्थिति उत्पन्न हुई है, मेरा उसके लिए माननीय मंत्री से अनुरोध है कि आप इस संदर्भ में अवश्य संज्ञान लें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री इस विषय पर संज्ञान लेंगे।

23.03.2026/1500/av/hk/2

अब माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज अपना विषय उठाएंगे।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन में मुझे कांगड़ा-चम्बा जिले के एक मेहनतकश, परम्परागत और अपेक्षित समाज की आवाज उठाने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपका विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं।

गद्दी समुदाय का पारम्परिक भेड़ पालन व्यवसाय केवल एक व्यवसाय नहीं है अपितु हिमाचल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। परंतु इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे चरागाहों का घटता आकार, बाढ़-बंदी, वन विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, पलायन के दौरान होने वाली बीमारियां, चोरियां, दुर्घटनाएं, जंगली जानवरों द्वारा उनके पशुओं को पहुंचाए जाने वाले नुकसान, जलवायु परिवर्तन से सिकुड़ते घास के मैदान और ऊन की घटती कीमत। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भेड़ पालक ने बताया कि दस रुपये में तो बीड़ी का एक बंडल तक नहीं आता और हमारी ऊन 10 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। उनको इस प्रकार बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको ट्रैवल के दौरान पशु चिकित्सा मोबाइल की समस्या भी रहती है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए एक स्थाई नीति बनाई जाए और साथ-ही-साथ युवाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए क्योंकि यह हमारे हिमाचल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है जोकि केवल किताबों में ही न रह जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिए बजट अभिभाषण में इस प्रकर की योजना का उल्लेख हुआ है। In view of the Budget pronouncement, the issue may be taken care of by the Government.

23.03.2026/1500/av/hk/3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार अपना विषय उठाएंगे।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अपना विषय उठाने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा विषय उन खाली पड़े भवनों के संबंध में है जो प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल जिनको जीरो एनरोलमैंट के कारण बंद किया गया, आज उनके सारे भवन खाली पड़े हैं। इसी के साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत विभाग की एक ऐसी बिल्डिंग खाली पड़ी है जो बनाई गई परंतु उसको आज तक किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। उसको बने हुए लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं और अब वह गिरने की कगार पर आ गई है। मेरा इस सदन के माध्यम से

टी सी द्वारा जारी

23.03.2026/1505/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

शून्य काल ... जारी

श्री सुरेश कुमार... जारी

सरकार को सुझाव है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, जो बिल्डिंग से रहित हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र भोरंज में मुख्य मंत्री जी ने जल शक्ति विभाग का एक सब-डिवीजन दिया है जिसने कार्य करना आरंभ कर दिया है लेकिन वहां अभी बिल्डिंग बनी नहीं है। इसी के साथ बिजली बोर्ड के दो सब-डिवीजन भोरंज और भरेड़ी सब-डिविजन दोनों इस समय किराए की बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। इसलिए क्यों न ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो सरकारी भवन खाली हैं उनमें इन ऑफिसिस को शिफ्ट किया जाए ताकि सरकार के पैसे की बचत हो और जो विभाग किराए के मकानों में चल रहे हैं उन्हें भी स्थायी स्थान मिल सके। मेरा

आग्रह है कि ऐसी नीति बनाई जाए जिससे खाली पड़ी सरकारी बिल्डिंग्स का प्रॉपर उपयोग हो सके। धन्यवाद।

अध्यक्ष : यह विषय पहले भी डिस्कशन में आ चुना है। मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सजैशन दिया है कि जहां भी सरकारी संस्थान खाली पड़े हैं और जिन विधान सभा क्षेत्रों में ऑफिस किराए के मकान में चल रहे हैं उन्हें इन खाली पड़े भवनों में शिफ्ट करने की दिशा में सरकार एक नीति लेकर आएगी ताकि नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता न

अध्यक्ष : श्री विनोद कुमार : उपस्थित नहीं ।

23.03.2026/1505/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

मनाली से अटल टनल, रोहतांग की ओर जाने वाले मार्ग पर होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या के संदर्भ में ।

कुमारी अनुराधा राणा: अध्यक्ष महोदय, शून्य काल के माध्यम से मैं सदन का ध्यान मनाली से अटल टनल रोहतांग की ओर जाने वाले मार्ग पर होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अटल टनल, रोहतांग की सौगात मिले लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। वर्ष 2020 में इसका लोकार्पण हुआ था। यह टनल लाहौल स्पिति जिला के लिए सामरिक दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही स्थानीय लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहले जहां 6 महीने तक यह क्षेत्र देश और प्रदेश से कट जाता था, अब यहां सर्दियों में बर्फबारी के समय में भी यात्रा संभव हो पाई है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है और वह है ट्रैफिक जाम की समस्या। यह समस्या विशेष रूप से पीक सीजन में अधिक गंभीर हो जाती है। कई बार एक किलोमीटर का सफर तय करने में 5 से 6 घंटे तक का समय लग जाता है। ऐसे में एम्बुलेंस, इमरजेंसी व्हीकल्स, इंटरव्यू या एग्जाम देने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एम्बुलेंस समय पर

अस्पताल नहीं पहुंच पाई और मरीज की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। इसी प्रकार कई लोगों का करियर भी प्रभावित हुआ है क्योंकि वे समय पर इंटरव्यू या एग्जाम में नहीं पहुंच सके।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि मनाली से अटल टनल रोहतांग तक के मार्ग के लिए एक विशेष ट्रैफिक यूनिट का गठन किया जाए। यदि हम मनाली और शिमला की तुलना करें तो दोनों स्थानों पर टूरिस्ट फ्लो लगभग समान है लेकिन शिमला में अल्टरनेटिव रोड्स अधिक हैं और ट्रैफिक पुलिस की संख्या भी अधिक है। मनाली क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 15 से 20 जवान ही ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हैं जो पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त ए0टी0आर0 और एन0जी0टी के भी जवान है परंतु इनका आंकड़ा बहुत कम है। शिमला में भी टूरिस्ट सीजन में जाम की समस्या रहती है लेकिन मनाली में की आवाजाही यहां से भी ज्यादा होती है। इसलिए वहां अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है। इसके साथ ही जगह-जगह पर पार्किंग की उचित व्यवस्था भी की जानी चाहिए। लाहौल स्पिति के स्थानीय लोगों को दैनिक जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। पहले जहां 1 से 2 घंटे का सफर होता था, अब वही सफर 7 से 8 घंटे में पूरा होता है।

23.03.2026/1505/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

अतः निवेदन है कि एक विशेष ट्रैफिक यूनिट का गठन किया जाए जिसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस जवान तैनात किए जाएं। हालांकि जो

एन0एस0 द्वारा ... जारी

23-3-2026/1510/एन0एस-वाई0के0-1

शून्य काल -----क्रमागत कुमारी अनुराधा राणा------जारी

जवान मौके पर सेवाएं देते हैं वे दिन-रात काम करते हैं। मैं देखती हूं कि वे बर्फवारी में जान की परवाह किए बगैर दिन-रात पर्यटकों को रेस्क्यू करते हैं और सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि वहां पर एक विशेष ट्रेफिक यूनिट का गठन

किया जाए और साथ ही जगह-जगह पार्किंग की व्यवस्था की जाए ताकि मनाली और लाहौल-स्पिति के लोगों तथा पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।

Speaker : Thank you. Undoubtedly, this is an important issue, which you have brought to the notice of the House. Certainly, the Government or the Police Department will be taking care of this by having a flying squad type of an arrangement and whatever action will be taken by the Police and by the Government, we will inform you accordingly.
अब श्री डी0एस0 ठाकुर जी अपना विषय उठाएंगे।

श्री डी0एस0 ठाकुर : उपस्थित नहीं।

श्री हरदीप सिंह बावा : उपस्थित नहीं।

श्री नीरज नैय्यर : उपस्थित नहीं।

23-3-2026/1510/एन0एस-वाई0के0-2

अध्यक्ष : अब श्री लोकेन्दर कुमार जी अपना विषय उठाएंगे।

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने शून्य काल के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित विषय उठाना था और इसी विषय का उत्तर मुझे प्रश्न के माध्यम से प्राप्त हुआ है। निरमंड में पटवारियों की लगातार दिक्कतें आ रही हैं। मुझे अब इसका जवाब मिल गया है तो मैं अपना विषय शून्य काल में नहीं उठाना चाहता हूं।

23-3-2026/1510/एन0एस-वाई0के0-3

'प्रदेश में कार्यस्थलों पर और सरकार व प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में कार्य कर रही महिलाओं के साथ छेड़खानी व अन्य घटनाओं के बारे

अध्यक्ष : अब श्री मलेन्द्र राजन जी अपना विषय उठाएंगे।

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी व सरकार का ध्यान 'प्रदेश में कार्यस्थलों पर और सरकार व प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में कार्य कर रही महिलाओं के साथ छेड़खानी व अन्य घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।' पिछले कई वर्षों में ऐसे मामलों में वृद्धि होना चिंता का विषय है और यह दर्शाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों/प्रावधानों को ओर अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में ऐसे मामलों में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या कितनी है, उनकी जांच की क्या स्थिति है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? इसका पूरा विवरण दिया जाए। इसके अतिरिक्त मैं यह भी आग्रह करता हूं कि यदि कहीं पर शिकायतों के निपटारे में देरी या लापरवाही सामने आई है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यह विषय प्रदेश की महिलाओं की गरिमा व सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। मैं मुख्य मंत्री जी व सरकार से प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।

Speaker : Hon'ble Member, for your information, this issue is also listed in the Question Hour vide Question No. 4122 and fixed for 27th March, 2026. If in any case you will not be satisfied with the answer on the respective date then you can further ask supplementary in this behalf.

23-3-2026/1510/एन0एस-वाई0के0-4

एन0एच0ए0आई द्वारा पानी की निकासी नालियां नहीं निकालने से उत्पन्न स्थिति बारे

अध्यक्ष : अब श्री इन्द्र सिंह जी अपना विषय उठाएंगे।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र गोहर से डडौर तक एन0एच0ए0आई0 ने जो नालियां निकालनी है वे अभी तक नहीं निकली गई हैं। वहां पर कनेड़, गौहर और डडौर का जो सरप्लस वाटर आता है वह लोगों के घरों में घुस जाता है।

मेरे क्षेत्र के चक्कर प्लांट की भी ऐसी ही स्थिति है। वहां पर हेम राज जी, भूत सिंह जी, राजो राम जी और महन्त राम जी के घरों में इस बार भी तीन दिन बरसात होने के कारण पानी भर गया है। वहां पर एन0एच0ए0आई0 द्वारा चैम्बर बनाया गया है लेकिन चैम्बर से आगे निकासी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि पानी खड्ड में जाए। इस चैम्बर का पानी लोगों के खेतों में जाता है और जनता उस चैम्बर को बंद कर देती है। बंद करने के बाद पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। मेरा मुख्य मंत्री जी, लोक निर्माण मंत्री जी व सरकार से निवेदन है कि वहां पर एन0एच0ए0आई0 को बोल कर ड्रेन निकाली जाए और सरप्लस वाटर को खड्ड में डाला जाए। धन्यवाद।

अंग्रेजी----- आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

23.03.2026/1515/RKS/YK-1

शून्यकाल... जारी

Speaker : Thank you. This is again an issue pertaining to the National Highways Authority of India. Certainly, the Vidhan Sabha Secretariat will take up the issue with the NHAI and we expect from them and will direct them to take immediate necessary action in this behalf and whatever action will be taken by them, we will inform you accordingly.

23.03.2026/1515/RKS/YK-2

अब माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी अपना विषय प्रस्तुत करेंगे।

खैर कटान में मार्किंग न होने से किसानों का आर्थिक नुकसान

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के सर्किल में 10 वर्ष के बाद खैर या दरख्तों का कटान किया जाता है। इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं जो सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ है।

जिन परिवारों के पास रोजी-रोटी का कोई साधन, सरकारी सेवा या रोजगार का कोई माध्यम नहीं होता, वे अपने फार्म सैक्टर के उत्पादन पर ही निर्भर रहते हैं। 10 ईयर फेलिंग रोटेशन के अंतर्गत खैर के पेड़ों का कटान किया जाता है। इसमें बिलासपुर वन मण्डल के अंतर्गत घुमारवीं रेंज के कुछ क्षेत्र मेरे चुनाव क्षेत्र में भी आते हैं। झंडूता, जोहला, राहण, बरठीं, समोह, बराड़, थुराण और डाढ क्षेत्रों में मार्किंग नहीं हो पाई थी जिसके कारण 10 ईयर फेलिंग के अंतर्गत किसानों के खैर नहीं बिक पाए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कई बार किसान एडवांस ले लेते हैं या एक प्रकार की चेन प्रक्रिया चलती है जिसमें छोटे स्तर के ठेकेदार जो गांवों से ही होते हैं तथा कुछ बड़े ठेकेदार भी शामिल होते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में गांव के किसानों का ही शोषण होता है। इसी प्रकार घुमारवीं, पनोल, सडयार और समोह क्षेत्रों में भी मार्किंग नहीं हो पाई थी। तीन दिन पहले मेरा एक प्रश्न लगा था जिसमें यह उत्तर दिया गया कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं विभाग से निवेदन है कि प्रश्नों के उत्तर सही दिए जाएं। यह रिकॉर्ड पर है कि इन बीट्स में मार्किंग नहीं हुई है। अतः आप इस विषय की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करवाएं। गांव के गरीब लोगों ने अपने बच्चों की शादियां करनी हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च उठाना है, अपने मकान बनाने हैं और जीवनयापन की अन्य छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करना है लेकिन इस कारण उनकी योजनाएं बुरे तरीके से प्रभावित हुई हैं। अब स्थिति यह है कि ये पेड़ सूख रहे हैं जिससे उनकी कीमत आगे चलकर न के बराबर रह जाएगी। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस विभाग को देखते हैं इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पूरे मामले की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। विभाग कोर्ट आदि के बहाने प्रस्तुत करता है परंतु इस प्रकार के बहानों से बचते हुए यदि कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसे शीघ्र सुधारा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकार के कार्यों में बाधा नहीं बनते बल्कि

23.03.2026/1515/RKS/YK-3

किसी ही विशेष केस में ऐसा होता है जिसे समय रहते ठीक किया जाना चाहिए। मेरा यही कहना है। धन्यवाद।

Speaker : This is again a very important issue which you have brought into the notice of the House. This pertains to the whole of the Himachal Pradesh not only to the Jhanduta. Certainly, the Vidhan Sabha Secretariat has taken a cognizance of this issue. We will ask the concerned Department to take immediate necessary steps in this behalf. If any policy is to be framed then the Government should frame a policy accordingly. So that the poor farmer should not be allowed to be exploited at any stage. Thank you very much for bringing a very important issue before the House.

23.03.2026/1515/RKS/YK-4

अब माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी अपना विषय उठाएंगे।

अश्वनी खड्ड के निकट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पर्यावरणीय खतरा।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में यह विषय उठाने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अश्वनी खड्ड के समीप सयूंठा क्षेत्र में एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस परियोजना के निर्माण हेतु सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई हैं? जिस स्थान पर यह साइट चिन्हित की गई है वह खड्ड से मात्र कुछ दूरी पर ही है। आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 2015 में जब इसी स्थान पर यह ट्रीटमेंट प्लांट फट गया था तब उसका सारा दूषित पानी अश्वनी खड्ड में मिल गया था। उस समय पूरे शिमला क्षेत्र में गंभीर रूप से पीलिया फैल गया था जिसके कारण लगभग 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में यह एस0टी0पी0 दोबार खड्ड के बिल्कुल निकट बनाया जा रहा है। यदि भविष्य में कभी क्लाउड बर्स्ट या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आ जाए और यह प्लांट फट जाता है तो इसका प्रभाव सोलन तक पड़ सकता है। इससे न केवल शिमला के आसपास के लोगों को भारी नुकसान होगा बल्कि साधुपुल होते हुए सोलन तक खड्ड के किनारे बनी पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हो जाएंगी।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

23.03.2025/1520/बी.एस./ए.जी.-1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जारी...

साथ में साधु पुल से सोलन तक हमारी खड्ड के किनारे जो पानी की स्कीमें लगी है वे सारी उससे से प्रभावित होंगी। मैं सरकार से जानना चाहूंगा क्या इस ट्रीटमेंट प्लान को लगाने के लिए यह जगह उचित है? और जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने इसकी प्लानिंग की है अगर कल को इसमें कोई त्रासदी होती है तो क्या वे इसकी जिम्मेदारी लेंगे? यही मेरा आपसे प्रश्न है?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। प्रदेश की राजधानी केलिए यहां से पीने की पेयजल योजना है और जहां पानी का ट्रीटमेंट प्लांट है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि वहां से 10 मीटर की दूरी पर जो है एस0ट0पी0 लग रहा है। वह पानी पीने के लिए पूरे शिमला के लिए होगा। अगर थोड़ा सी भी उसमें कहीं कोई लीकेज हो गई तो जिस प्रकार से जिक्र किया है, बहुत संकट होगा और पीलिया के कारण एक वक्त में यहां शिमला में एक दर्जन से ज्यादा लोग जॉन्डिस के शिकार हुए हैं। इसको गंभीरता से देखना चाहिए। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि जो मिनिस्ट्री इंचार्ज है मुझे लगता है कि अगर आपके शून्य काल की इंटीमेशन जाती है और साथ-साथ अगर रेस्पॉन्ड करें तो उसका कुछ आनंद आएगा, भले ही नंबर कम हो जाएगा लेकिन जवाब देही भी हो जाएगी और उसके साथ-साथ उसमें उसकी गंभीरता भी बनेगी। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन सारी बातों को गंभीरता से लें। क्योंकि यह प्रदेश की राजधानी से ले करके सोलन तक जुड़ा हुआ विषय है।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने और माननीय सदस्य लखनपाल जी ने जो मसला संज्ञान में लाया है, हम इसकी पड़ताल करवा लेंगे।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब जो दूसरी बात आपने कही है, बहुत सारे माननीय सदस्य सुबह ही नोटिस दे देते हैं। इस कारण इसका नोटिस विभाग को नहीं जा सकता। Realising the

importance of the issue, विधान सभा सचिवालय उसी दिन उस विषय को उठाने की अनुमति दे देता है। पर we monitor it at our own level; the issues, which have been raised under the Zero Hour by the Hon'ble Members, and the directions, which have been given to the respective department through the House, whether that has been carried or not. In any case, till now, the reports are positive.
23.03.2025/1520/बी.एस./ए.जी.-2

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस एस0टी0पी0 प्लांट के बारे में माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं। वैसे तो जो इसका इनिशियल प्रपोज है और सैंक्शन है वह पूर्व की सरकार के समय में ही पूर्ण हो गया था। आपके समय में ही आदरणीय भारद्वाज जी ने इसे करवा दिया था। फिर भी हमारी सरकार इस विषय के ऊपर गंभीर है कि कहीं पर भी इस तरीके का प्लांट नहीं होना चाहिए जो किसी भी वाटर सोर्स के बहुत नजदीक है। मगर फिर भी, as I was told by the department, इसमें जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वे लिए गए हैं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय हमारे जितने भी एस0टी0पी0 प्लांट्स शहर के अंदर बना रहे हैं उन सब में रिट्रोफिटिंग करवाई गई है और आधुनिक हिसाब से उसको ट्रीट करने के लिए उन प्लांट्स को, मैं केवल इसी प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं। मगर जितने भी शहर के अंदर और भी चल रहे हैं उनमें रिट्रोफिटिंग करवाई जा रही है और उन प्लांट्स की ऑक्सिडाइजेशन करवाई जा रही है।

मैंने खुद लाल पानी और नीचे समर हिल के प्लांट का निरीक्षण किया। एक समय था आप उस एरिया से क्रॉस नहीं कर सकते वहां इतनी बदबू थी। अब आप वहां पर प्लांट के अंदर भी चले जाएं, there is no stench at all. I was assured by the department the steps that the department is taking, उससे आने वाले समय में जो पानी है, टेक्निकली मैं नहीं कह रहा हूं कि पीना है, but according to the tests, it is fit for human consumption. अगर उसको करना है तो उस हिसाब से हर तरीके का इसमें डिपार्टमेंट द्वारा प्रिकॉशनरी मेजरस दिए जा रहे हैं और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। **मगर फिर भी आदरणीय लखनपाल जी ने जो कंसर्न इसमें रेज किए हैं, the proximity**

between the natural source i.e. the river and the plant, उसके बारे में हम जांच करेंगे और देखेंगे।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

23.03.2026/1525/DT/AG-1

लोक निर्माण जारी...

इसमें यदि कोई प्रिरिक्विजिट पाया जाता है, या इसमें जो टर्म्स एंड कंडिशन्ज हैं कि उसको नदी से इतना दूर रखना है, **उसमें यदि कोई कमी पाई जाती है that can always be looked into. उसके ऊपर कार्य किया जायेगा, but I want to assure you कि जितने भी एस0टी0पीज0 प्लांट, particularly, after the jaundice breakout that happened few years back in Shimla, यानी वर्ष 2013 में जब मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और श्री सुधीर शर्मा जी उस समय टी0सी0पी0 एव यू0डी0 मंत्री थे, उस समय यह बहुत बड़ा कांड शिमला में हुआ था और उसमें एक डैथ भी हो गई थी। उसके बाद we have been taking stringent measures ताकि इस तरह की चीजें न हों, इस पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिर भी माननीय सदस्य द्वारा जो चिंताएं जताई गई हैं, उसको हम देखेंगे और अगर नदी के वह बहुत पास है तो उसकों वहां से दूर स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा।**

23.03.2026/1525/DT/AG-2

अध्यक्ष : शुन्य काल में अगला मामला श्री केवल सिंह पठानिया जी द्वारा उठाया जाएगा।

श्री केवल सिंह पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पशुपालन मंत्री जी की इंटरवेंशन चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के धारखंडी में मोछ गांव पड़ता है जहां पर पिछले कल श्री मूल राज, सुपुत्र श्री बिशना राम जिनकी 60 भेंडें-बकरियां ऊना जिलें मे ट्रेन के नीचे आ गई हैं। इसमें एफ0आई0आर0 तो दर्ज करवा दी गई है पर एफ0आई0आर0 हिमाचल पुलिस द्वारा दर्ज की गई है लेकिन इसके साथ-साथ यह मामला रेलवे पुलिस का भी है। लेकिन अभी तक पुलिस व पशुपालन विभाग की टीम वहां पर नहीं पहुंची है। क्योंकि यह मामला 60 भेड़-बकरियों का है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा

कि इसी बजट में 300 करोड़ रुपये का बजट गद्दी समुदाय के लिए रखा गया है और ऊन का समर्थन मुल्य 100 रुपये प्रतिकिलो कर दिया गया है। लेकिन यह मामला जो घटित हुआ है इस मामले में मैं चाहता हूं कि माननीय पशुपालन मंत्री इसमें रेलवे अधिकारियों व पशुपालन विभाग के अधिकारियों की एक टीम का गठन करे जो इसकी जांच करे। अभी भी 30 या 40 भेड़-बकरियां साइड में ही पड़ी हुई हैं, इसलिए मैं इस मामले में माननीय मंत्री जी की इंटरवेंशन चाहता हूं।

Speaker : Hon'ble Minister, if you want to intervene, you can. वैसे तो इसमें मुख्य मंत्री जी की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है क्योंकि इसमें कंपनसैशन पे होगा and case is to be registered.

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर दर्दनाक मामला है जो हमारे गद्दी भाई जनजातिय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, वे अपनी भेड़-बकिरयों को निचले क्षेत्रों में लेकर जाते हैं और यह जो रेलवे ट्रेक बना है इसमें अभी ट्रायल बेस पर ही गाड़ियां चल रही हैं उससे कुछ भेड़े और बकरियां उस रेल की जद में आ गईं हैं और काफी भेड़-बकरियां मर गई हैं। मैं माननीय सदस्य को अश्वस्त करना चाहुंगा कि **हमारे उस जिला के डिप्टी डायरैक्टर वहां स्वयं जाकर घटना का निरिक्षण करेंगे और भेड़-बकरियों का पोस्ट-मॉरटम भी करवायेंगे और जो भी कंपनसैशन होगी वे उनको मुहैया करवाई जायेगी।**

Speaker : This is an important issue. The Vidhan Sabha Secretariat has taken cognizance of this issue. This issue has to be taken up with the Railway Ministry also because this railway line has to be fenced accordingly so that

animals, children or human beings are not accessed to the railway line. We will take up this issue with the Railway Ministry through the Vidhan Sabha.

शून्य काल समाप्त और इसी के साथ आज के शून्य काल में प्राप्त विषय भी समाप्त।

अब मुख्य मंत्री महोदय इस सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्य सूची से अवगत करवायेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदन को इस सप्ताह की कार्यसूची से अवगत करवाता हूं, जो इस प्रकार से हैः

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी, सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो कि इस प्रकार हैः-

सोमवार, 23 /मार्च, 2026 1.शासकीय/विधायी कार्य ।
2.बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2026-27

सामान्य चर्चा।

मंगलवार, 24 /मार्च, 2026 1.शासकीय/विधायी कार्य ।
2.बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2026-27
सामान्य चर्चा।

बुधवार, 25 /मार्च, 2026 1.शासकीय/विधायी कार्य ।
2.बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2026-27
सामान्य चर्चा।

वीरवार, 26 सितम्बर, 2020 अवकाश।

23.03.2026/1525/DT/AG-3

शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 1.शासकीय/विधायी कार्य ।
2.बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2026-27

मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

शनिवार, 28 मार्च, 2026 1. शासकीय/विधायी कार्य ।

2.बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2026-27
मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

23.03.2026/1530/ए.एस.-एन.जी./1

साप्ताहिक कार्यसूची के प्रश्चात..... जारी

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं-अतिरिक्त सचिव (विधि-अंग्रेजी), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः कार्मिक (ए-IV)-बी(15)-3/25-पार्ट-I, दिनांक द्वारा 28.02.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 28.02.2026 को प्रकाशित की प्रति पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय कृषि मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय आयुष मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

आयुष मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न कागजातों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सह-आचार्य (इंजीनियरिंग) ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025, जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीएन(टीई) ए(3)-2/2020, दिनांक द्वारा 02.12.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 05.12.2025 को प्रकाशित;

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सह-आचार्य (अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी) ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025, जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीएन(टीई) ए(3)-3/2025, दिनांक द्वारा 02.12.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 05.12.2025 को प्रकाशित; और

iii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, प्रधानाचार्य (बहुतकनीकी) ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025, जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीएन(टीई) ए(3)-8/2024, दिनांक द्वारा 03.01.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 12.01.2026 को प्रकाशित।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2025-26), लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का 124वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

2. समिति का 125वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है; और

3. समिति का 126वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 178वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2025-26), लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं:-

1. समिति का 29वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा संख्याः 5.5 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

2. समिति का 52वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) पर बने 13वें कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में अन्तर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2025-26), कल्याण समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति का 46वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित समिति का षष्टम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2022-23) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा

कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री संजय अवस्थी, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2025-26), मानव विकास समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का 32वां प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
2. समिति का 33वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि वित्त विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है।

23.03.2026/1530/ए.एस.-एन.जी./5

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

विचार :

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) विचार किया जाए।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) विचार किया जाए।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, इस बिल के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि यह बिल क्या है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार विधवा व अनाथ बच्चों के लिए डीजल व पैट्रोल पर एक सैस लगाने जा रही है। ताकि हमारी जो भी योजनाएं हैं या भविष्य की सरकार की कोई योजनाएं होंगी तो हर सरकार के पास एक अधिकार हो और उसके तहत इन लोगों के लिए समय-समय पर कल्याण की योजनाओं लागू की जाएंगी, इस संदर्भ में वैल्यू एडिड टैक्ट में सैस लगाने के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) विचार किया जाए।

इस बिल के खण्ड-2 व खण्ड-3 पर माननीय सदस्य, सर्वश्री राकेश जम्वाल, रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल से संशोधन प्राप्त हुए हैं लेकिन वे इन-ऑर्डर नहीं हैं लेकिन माननीय सदस्य बोल सकते हैं। मैं माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचार रखें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) लेकर आई है। जिसके तहत पैट्रोल और डीजल पर सैस लगाने का प्रावधान किया जाना है। हम इसका विरोध करते हैं और मैंने अपने संशोधन में भी कहा था कि श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

23.03.2026/1535/ए0एस0/ए0पी0/-01

श्री रणधीर शर्मा जारी .....

इस संशोधन को हटा दिया जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पहले से ही महंगे हैं। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पर 17.5 प्रतिशत वैट और डीजल पर 13.9 प्रतिशत वैट है। हिमाचल में आने वाले पेट्रोल और डीजल पर पहले से ही बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। अब इस पर 5 रुपये प्रति लीटर का सैस लगाकर पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच जाएगी। क्योंकि वर्तमान में, पेट्रोल के रेट 94.13 रुपये प्रति लीटर और डीजल

के रेस 86.23 प्रति लीटर हैं। यदि 5 रुपये का सैस लगाया जाता है तो ये रेट पेट्रोल के लिए 100 रुपये के करीब और डीजल के लिए 90 रुपये से ऊपर चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसकी वजह से आम आदमी पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। अनाथ और विधवा वर्ग के लिए अनेक सामाजिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक वेलफेयर स्टेट है और इन वर्गों के लिए योजनाएं चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की पहले से ही कई योजनाएं चल रही हैं। लेकिन प्रदेश सरकार जनता पर अतिरिक्त बोझ डालकर पैसा इकट्ठा करना और फिर उसे योजनाओं के नाम पर देना तर्कसंगत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि यह सैस बढ़ाया जाता है तो सरकार का राजस्व बढ़ाने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसका कारण यह है कि वर्तमान में पंजाब में पेट्रोल 97.70 रुपये और डीजल 88.20 रुपये है। अभी हिमाचल के लोग तो हिमाचल में पेट्रोल-डीजल भरवाते है क्योंकि हम उनसे सस्ता रेट देते है। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे पंजाब और हरियाणा के लोग हिमाचल आकर पेट्रोल-डीजल भरवाते हैं। लेकिन इस सैस के बाद हमारे रेट पंजाब और हरियाणा से भी ज्यादा हो जाएगें। इसके बाद बाहरी राज्यों के वाहन हिमाचल में पेट्रोल-डीजल भरवाने के बजाय अपने ही राज्यों में भरवाना पसंद करेंगे। इससे आपकी बिक्री कम हो जाएगी। जब बिक्री कम होगी तो जो वैट पहले 17.5 प्रतिशत और 13.9 प्रतिशत ले रहे है उसका

23.03.2026/1535/ए0एस0/ए0पी0/-02

भी घाटा होगा और इस नए सैस से भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। चंडीगढ़ में डीजल फिलहाल हिमाचल से सस्ता है। देखने में आया है कि कई कमर्शियल गाड़िया और वोल्वो बसें चंडीगढ़ में डीजल भरवाती हैं क्योंकि वहां 3 रुपये का अंतर है। अगर आप 5 रुपये का सैस और लगा देंगे तो यह अंतर 8 रुपये का हो जाएगा। फिर तो पेट्रोल भी चंडीगढ़ में सस्ता होगा। इसलिए, इस फैसले से सरकार की मंशा पूरी नहीं होगी और जनता पर बोझ बढ़ेगा। इसलिए मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। पूर्व सरकार ने जो वैट कम किया था,

उसे इस सरकार ने आते ही फिर से बढ़ा दिया। जिससे यह दरें पहले ही 17.5 प्रतिशत और 14 प्रतिशत तक पहुंच गई हैं। दूसरी बात यह है कि मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में भी कहा था कि विश्व में युद्ध के हालात है और इस हालातों के कारण पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, ऐसी आशंका आपने अपने बजट भाषण में भी की थी। जब वैश्विक कारणों से कीमतें बढ़ेंगी और ऊपर से आप भी सैस लगाएंगे तो हिमाचल की जनता कहां जाएगी? पहले से ही रेट्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए कृपया करके आप पेट्रोल-डीजल को छोड़िये क्योंकि इससे आम आदमी पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। आज लगभग हर परिवार के पास कोई न कोई वाहन है, चाहे वह कार हो, बाइक हो या स्कूटर। मात्र कुछ ही परिवार होंगे जिनके पास कोई गाड़ी नहीं होगी। इसलिए सब पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को सरकार वापिस ले, ये जन विरोधी है। इससे जनता को दिक्कत आने वाली है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

23.03.2026/1540/AT/DC/01

श्री रणधीर शर्मा जारी...

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस अमेंडमेंट को सरकार वापस ले। यह जनविरोधी है, इससे जनता को दिक्कत आने वाली है। सरकार जिस मंशा से इसे ला रही है कि वह अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है वह भी नहीं बढ़ेगा और पूरा नहीं होगा। इसलिए इस अमेंडमेंट को तुरंत वापस लिया जाए। यही निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय श्री त्रिलोक जम्वाल जी। आपने भी अमेंडमेंट दिया है तो इसे एक साथ मूव कर लो और डिस्कस भी कर लो।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट एच0पी0 वैल्यू एडेड टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026 सरकार लाई है, जैसा कि मुझसे पूर्व माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा

जी ने कहा कि इस अमेंडमेंट का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ेगा। इस अमेंडमेंट के बाद डीजल के रेट मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा हो जाएंगे। यह भी बिल्कुल सही है कि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड जहां हमारा अधिकतर क्षेत्र लगता है वहां डीजल सस्ता होगा और हमारे यहां महंगा होगा तो वैट में भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। सरकार की यह मंशा भी पूरी नहीं होगी। लेकिन हिमाचल वासियों पर प्रत्येक व्यक्ति पर टैक्स का बोझ बढ़ता जाएगा। मेरा जिला बिलासपुर इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा क्योंकि वहां सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियन है। ए0सी0सी0 सीमेंट फैक्ट्री और बागा क्षेत्र से जुड़े सभी ट्रक ऑपरेटर बरमाणा, बेरी और आसपास के क्षेत्रों के उन्हें प्रतिदिन कितना नुकसान होगा इसका अभी सही आकलन नहीं हो पा रहा है। पहले ही अन्य चीजों का बोझ है और अभी जैसे क्रूड ऑयल की कीमतें पिछले कल बढ़कर लगभग 110 रुपये प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इसका सीधा प्रभाव डीजल और पेट्रोल पर पड़ेगा। जब यह प्रभाव आएगा तो पहले सरकार ने 7 रुपये बढ़ाए अब 5 रुपये और जुड़ गए, अगर उसके बाद अगर ईरान, अमेरिका और इराक के बीच युद्ध चलता रहा तो आने वाले 15-20 दिनों में डीजल और पेट्रोल के दाम और बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में गरीब आदमी कहां जाएगा जिसके पास स्कूटर है, बाइक है, जो ट्रैक्टर चलाता है, जो पिकअप

से अपना काम करता है, जो अपने परिवार की रोजी-रोटी चलाता है, जो टैक्सी चलाकर परिवार पालता है वह कहां जाएगा? किसान कहां जाएगा?

इस अमेंडमेंट का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ेगा। तथ्यात्मक स्थिति श्री रणधीर शर्मा जी ने पहले ही रख दी है। लेकिन जो 17 प्रतिशत वैट बढ़ने की बात हो रही है वह बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा और जो डीजल पर 13.9 मिल रहा है वह भी घटेगा।

अध्यक्ष : यह वैट नहीं है, यह सेस है।

श्री त्रिलोक जम्वालः अध्यक्ष महोदय, प्रभाव तो पड़ेगा। सेस लगेगा तो अंत में अंतिम उपभोक्ता पर ही असर पड़ेगा। राशन महंगा होगा ...(व्यवधान)

Speaker : Here you are right.

श्री त्रिलोक जम्वाल : सब्जी के दाम बढ़ेंगे, दूध के दाम बढ़ेंगे। हर चीज पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए लेकिन पूरे प्रदेश की जनता के हितों को नजरअंदाज करके नहीं। सरकार को अन्य तरीकों से योजना बनानी चाहिए। यही मैं अपना निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए इस अमेंडमेंट को हटाया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : इस पर राकेश जम्वाल ने भी अमेंडमेंट दिया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हैं। इसलिए वह अपने आप ही चली गई। अब इसके बाद यदि अन्य माननीय सदस्य चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मैं अनुमति दूंगा। आपने जो अमेंडमेंट मूव किया है वह ऑर्डर में नहीं है लेकिन आपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से जो आवश्यक और जरूरी है, वह तो आपने रख दिया है। इसलिए इस भाग को अनुमति दी जा रही है। क्योंकि इसमें क्लॉज लिखे हैं आपने तो यह ऑर्डर में नहीं है क्योंकि इसमें एक नया क्लॉज ऐड हुआ है और धारा 6 में संशोधन किया गया है। Anyways that is not in Order but still you have ventilated your view point through these amendments and the Government may take a call on behalf of this. Now I would request rest of the Hon'ble

23.03.2026/1540/AT/DC/03

Members to take part in deliberations. सत्ती जी भी बोलना चाह रहे थे और माननीय नेता प्रतिपक्ष भी बोलना चाह रहे थे। लेकिन पहले कौन बोलना चाह रहे है? आप बोलिए फिर उसके बाद मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे। माननीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

23.03.2026/1545/केएस/डीसी/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने पैट्रोल और डीज़ल के ऊपर सैस लगाने का विषय हम सभी के सामने रखा है, जैसा रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल जी ने कहा कि हमारा एरिया तो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है तो हमारे एरिया के जितने भी पैट्रोल पम्प हैं, वे चाहे किसी के भी हैं, उनको भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके साथ-साथ जैसे बताया गया कि आज की डेट में पैट्रोलियम पदार्थों के ऊपर ही सारी अर्थव्यवस्था चली हुई है। अरब कंट्रीज़ में, जहां पैट्रोलियम पदार्थ ज्यादा होते हैं, उनमें जब थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है तो पूरे विश्व के अंदर उससे हाहाकार मचता है जैसे आजकल हम युद्ध के परिणाम देख रहे हैं। अभी तक हम सभी का सौभाग्य है कि देश के अंदर जो स्थिति है, उसमें अभी ऐसी बातें ध्यान में नहीं आईं हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर डीज़ल या पैट्रोल में कोई बढ़ोत्तरी हो रही है या नहीं। एक दिन मैं न्यूज़ पेपर में पढ़ रहा था कि जो पैट्रोलियम पदार्थ पैदा करने वाले देश हैं, उनमें पैट्रोल 107 रुपये प्रति लीटर हो गया है। हमारी केंद्र सरकार का अभी शायद उसमें वेट एण्ड वॉच चला होगा नहीं तो जैसे रणधीर शर्मा जी ने कहा, वहां से भी रेट बढ़ सकते हैं क्योंकि देश की पूरी अर्थव्यवस्था इसके ऊपर टिकी है। अतः इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय मेरा यह है कि मुख्य मंत्री जी ने विधवा सैस जो शब्द लगाया है, मुझे लगता है कि यह विधवा महिलाओं का अपमान है। यह उनके लिए बहुत ही दुखदायी शब्द होगा कि हमारे नाम से सरकार पैसा इकट्ठा कर रही है। यह उनकी गरिमा के विपरीत है। इसलिए मुख्य मंत्री जी, एक तो आप इसके ऊपर पुनर्विचार करें और दूसरा, डीज़ल और पैट्रोल के जो आप दाम बढ़ा रहे हैं, उसके कारण हिमाचल प्रदेश में जो दिक्कतें आने वाली हैं, आपको लगता होगा कि इससे गवर्नमैंट की इनकम में पैसा आएगा

लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें पिछले तीन वर्षों में भी आप लगभग 6-7 रुपये डीज़ल और पैट्रोल के दाम बढ़ा चुके हैं। फिर प्राइवेट बसों वाले हड़ताल कर देते हैं कि हमारा किराया बढ़ाओ। वे किराया बढ़ाएंगे फिर टैक्सी वाले और थ्री व्हीलर वाले भी किराया बढ़ाएंगे। सीमेंट महंगा हो जाएगा जो कि आपके तीन साल में 6-7 बार पहले ही महंगा हो चुका है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और जो विधवा शब्द आपने जोड़ा है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो पूरी तरह से पुनर्विचार करें क्योंकि यह शब्द अच्छा नहीं है। धन्यवाद।

23.03.2026/1545/केएस/डीसी/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की ओर से जो हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन)विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) का यहां प्रस्तुतिकरण हुआ है, मैं इसके विरोध में खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो जैसा आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती ने कहा, प्रदेश में अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, विधवा के नाम पर सैस लगाकर यह कहीं भी अंतरात्मा को अनुमति नहीं देता है, कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि इस तरह के नाम का जिक्र करके हम प्रदेश की सरकार का खर्च चलाने की योजना बनाएं। यह कतई भी उचित नहीं है। इस भाव में जाने की आवश्यकता है। ऑफ़न एण्ड विडो, ऐसे लागों के नाम पर पैसा इकट्ठा करके हम सरकार का संचालन करना चाहे तो यह कतई भी उचित नहीं है। दोनों शब्द, ऑफ़न और विडो का उपयोग इस प्रकार के काम के लिए नहीं होना चाहिए, इस सोच के लिए और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए जिसके लिए आप कर रहे हैं। एक तो मैं यह कहना चाहूंगा। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, हम इस बात से सहमत हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन आप इस बात को भी देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जो हमारे सामने है, उसके मध्यनज़र आने वाले समय में पूरे देश और पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा इज़ाफा होने वाला है, ऐसा लगता है और इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

23.03.2026/1550/av/hk/1

श्री जय राम ठाकुर------- जारी

This is bound to happen. मैं कल ही सुन रहा था कि कतर में जिस प्रकार से एक रिफाइनरी पर बम्ब या मिसाइल गिराई गई है, उसको दोबारा से फंक्शनल करने के लिए तीन वर्ष का समय लगेगा यदि उस पर दूसरी मिसाइल नहीं गिराई गई। आप इस बारे में खुद कल्पना कर सकते हैं और वहां से बड़ी मात्रा में भारत के अंदर भी तेल आता है इसलिए हमें इस बात को भी समझना होगा। आप यहां पर तेल की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने की सम्भावना लग रही है। ऐसी सूरत में इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर इस प्रदेश की गरीब जनता के ऊपर पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि गरीब के ऊपर तो पड़ेगा ही अपितु इससे कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं छूटेगा। अगर हम इससे भी आगे देखें तो हमारे साथ लगते राज्यों में अगर तेल की कीमतें कम होंगी तो यहां से जितनी भी गाड़ियां बाहर जाएंगी वे सारी-की-सारी वहीं से तेल भरवाकर वापिस आएंगी। सीधी-सी बात है क्योंकि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जब पैट्रोल सस्ता था तो दूसरे प्रदेश की गाड़ियां यहां से तेल भर कर जाती थीं जिससे हमारी आय में बढ़ोतरी होती थी। इसलिए इन सारी चीजों को लेकर सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए, आपको इसके लिए थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए।

हम आपकी भावना से वाक़िफ हैं। यहां पर आर्थिक संकट है और उससे बाहर निकलने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन हम इस बात को भी हमेशा कहते हैं कि ऐसे कदम भी मत उठाइए जिससे कि गरीब आदमी का कचूमर निकल जाए। आपने जिस प्रकार से एंट्री टैक्स पर जल्दबाजी में फैसला लिया और अब आप उसके इम्पैक्ट्स भी देख रहे हैं क्योंकि पंजाब विधान सभा के अंदर वहां के वित्त मंत्री कहते हैं कि जहां-जहां से हिमाचल ने एंट्री

टैक्स लगाया वहां-वहां से हम भी हिमाचल की गाड़ियों पर लगाएंगे। आप उसका रियेक्शन देख सकते हैं क्योंकि साथ लगते राज्यों के साथ जहां-जहां पर हमारे

23.03.2026/1550/av/hk/2

प्रदेश के बोर्डर एरियाज लगते हैं वहां लोगों के बीच इम्पैक्ट देखिए कि उनमें कितना गुस्सा है। उनको इसके बढ़ने से किस प्रकार की असुविधा व परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण यहां पर्यटकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा कदम मत उठाइए जिसके कारण लाभ की बजाय नुकसान ज्यादा हो। हम इस बात से सहमत हैं कि सरकार के सामने संकट है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि फिलहाल आप यहीं रुक जाइए। आगे बढ़ने के बाद फिर पीछे मुड़ना पड़े ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आप इस बिल को वापिस लेकर यहीं पर रुक जाइए। आने वाले समय में जब हालात सुधरेंगे तो आप बढ़ा सकते हैं। हमने भी अपनी सरकार के कार्यकाल में 5 रुपये वैट कम किया था। परंतु आपने आते ही एक नहीं अपितु दो बार बढ़ा दिया। उसके बाद आप हालात देख रहे हैं कि ये अभी भी नहीं सुधरे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि फिलहाल आप यहीं रुक जाइए और कुछ हालात सुधरने के बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, दो शब्द 'विधवा और ऑर्फन' हमारी भावना के अनुकूल नहीं है। अतः अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इन दो शब्दों को ढाल बनाना उचित नहीं है।

23.03.2026/1550/av/hk/3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार बोलेंगे।

आपके पास अगर इसके अतिरिक्त कोई सुझाव है तो आप उसी पर बोलिए।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार यहां पर जो हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) लेकर आई है, मैं उसके विरोध हेतु खड़ा हुआ हूं।

यहां पर जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात रखी है और इस विधेयक में सरकार ने पैट्रोल और डीजल के रेट्स को लेकर 5 रुपये तक इज़ाफे की बात कही है।

टी सी द्वारा जारी

23.03.2026/1555/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री विनोद कुमार ... जारी

... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जैसे यहां पर आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अंदर जो पेट्रोल और डीजल के रेट को लेकर अंतर है उसके कारण हिमाचल प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की सेल बढ़ी है। यह स्वाभाविक भी है जैसे चंडीगढ़ में डीजल का रेट 3 रुपये कम है तो इस तरफ से जो लोग चंडीगढ़ जाते हैं वे अधिकतर वहीं डीजल डलवाते हैं क्योंकि उन्हें यह 3 रुपये सस्ता मिलता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब से सरकार बनी है तब से दो बार पेट्रोल और डीजल के रेट लगभग 7 रुपये तक बढ़ाए गए हैं। जब ये रेट बढ़ाए गए थे उस समय बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल शुरू कर दी थी क्योंकि उनका कहना था कि 7 रुपये की वृद्धि से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए तो बस व टैक्सी का किराया भी बढ़ा गया। बस में गरीब आदमी सफर करता है और किराया बढ़ाने से उसकी जेब पर सीधा असर पड़ता है। जब टैक्सी का किराया बढ़ता है तो उसका बोझ उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि अनाथ बच्चों और विधवा बहनों को लेकर जो सैस लगाने की बात कही गई है उस पर पुनर्विचार करने की

आवश्यकता है। इस सैस के माध्यम से प्रदेश के हर जनमानस की जेब पर प्रभाव पड़ेगा। मैं केवल यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः अब मुख्य मंत्री महोदय इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे।

23.03.2026/1555/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विधवा और अनाथ बच्चों के लिए हम एक सैस का बिल लेकर आ रहे हैं और विपक्ष द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। यह देखकर मुझे दुःख होता है कि जो बिल विधवा और अनाथ बच्चों के हित में लाया गया है उसका विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने अधिकतम सीमा 5 रुपये तक रखी है। इसके भीतर 10 पैसे, 5 पैसे या 25 पैसे तक का सैस भी लगाया जा सकता है। श्री जय राम ठाकुर जी तो और आगे चल पड़े और पंजाब की आम आदमी पार्टी की भाषा बोलने लग पड़े। हम शब्दों पर नहीं जाते हैं। हमारी भावना को समझिए। हमारी भावना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है और उन विधवा बहनों के लिए है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है। उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके जीवन-यापन और अन्य सुविधाओं के लिए हमने यह प्रावधान किया है। अभी हरियाणा और पंजाब के रेट हिमाचल प्रदेश से लगभग 2 रुपये अधिक हैं। हमें संतुलन बनाकर चलना है। हमने यह संतुलन अनाथ बच्चों और विधवा बहनों के हित को ध्यान में रखकर किया है। ...(व्यवधान) यदि उनके पास स्कूटी या गाड़ियां हैं तो यह अच्छी बात है। हमारी यही भावना है कि

एन0एस0 द्वारा ... जारी

23-3-2026/1600/एन0एस-वाई0के0-1

मुख्य मंत्री-----जारी

हमारी यही भावना है। हिमाचल प्रदेश में कोई बच्चा अपने आपको अनाथ न समझे और कोई विधवा बहन अपने आपको यह न सोचे कि मेरे पति की मृत्यु के बाद कोई उसको देखने वाला नहीं है। उनको सरकार देखने वाली है। उन अनाथ बच्चों और विधवा बहनों ने सरकार से मांग नहीं की है बल्कि यह सरकार की एक सोच है और उस सोच के अनुसार सरकार जब कल्याणकारी राज्य बनने के लिए नीतिगत परिवर्तन लाती है उसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। हमने इसको स्टडी किया है कि हरियाणा और पंजाब में 2 रुपये ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, अगर इनको इतनी ही चिंता है और यहां पर बात करते समय कत्तर का उदाहरण दे रहे थे, डीजल के रेट का उदाहरण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, 27 रुपये का सैस लगाते हैं उसको कम करवाएं ताकि लोगों का फायदा हो। मैं आपको भारत सरकार के सैस बताना चाहता हूं। एक्साइज ड्यूटी पर 10 रुपये सैस, Agriculture Infrastructure Development Cess यानी हमारी तो आर0डी0जी0 भी काट देते हैं। आप सब लोग भी उसको देते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और हिमाचल प्रदेश की लगभग 75 लाख जनता भी उसको देती है तथा बी0जे0पी0 वाले भी देते हैं। Agriculture Infrastructure Development Cess अढ़ाई रुपए लीटर ऑन पेट्रोल, चार रुपए लीटर ऑन डीजल और सोशल वैल्फेयर चार्ज भी लिया जाता है। ये जो पेंशन स्कीमें चल रही हैं और मोदी जी सम्मान निधि दे रहे हैं तो उसमें भी 10 प्रतिशत सैस लगता है। Road and Infrastructure Cess 50 रुपये मीट्रिक टन उसके ऊपर लगता है। ...(व्यवधान) 28 रुपये के करीब सैस लगता है। अध्यक्ष महोदय, हम यह बिल उन विधवा बहनों और अनाथ बच्चों के लिए ला रहे हैं तो ये विरोध करके अमेंडमैंट ला रहे हैं। ...(व्यवधान) सरकार तो चल रही है, सरकार आत्मनिर्भर भी हो रही है। हमारे बजट में आपने जितना मर्जी विरोध करवाना था आप दिल्ली जाकर करवा आए। मुझे समझ नहीं आता कि भाजपा हिमाचल विरोधी क्यों है? ...(व्यवधान)

Speaker : Please Order in the House.

23-3-2026/1600/एन0एस-वाई0के0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने एक अप्पर लिमिट तय की है। **मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम पंजाब और हरियाणा से अपने पेट्रोल व डीजल का रेट कम रखेंगे।** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो अमैंडमैंट्स माननीय सदस्यों ने लाई है,

Speaker : That is not in Order, पर जो इन्होंने सुझाव दिए हैं।

मुख्य मंत्री : तो इस बिल को आप पास करने की इजाजत दीजिए।

अध्यक्ष : श्री रणधीर शर्मा जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी हर बात पर राजनीति करते हैं तो आप इसको छोड़ दें। आप तो विधवा और अनाथ बच्चों पर राजनीति करने लग पड़े हैं। ऐसी राजनीति करना ठीक नहीं है। आप यह सैस चाहे 1 रुपये से लेकर 4 रुपये लगाएं तो जिनके पास चाहे छोटी या बड़ी गाड़ी है या चाहे वे अनाथ हैं, विधवाएं हैं या उनके जो परिजन हैं यह उनसे भी लिया जाएगा। फिर उनसे लेकर जो महंगाई बढ़ेगी, जो चीजें महंगी होंगी वे विधवाएं, अनाथ बच्चे भी लेंगे तो महंगाई हर चीज की बढ़ेगी। ट्रक वाले का खर्च अगर एंट्री टैक्स से ज्यादा आएगा या डीजल महंगा होने से ज्यादा आएगा और अगर वे कंपनी से सीमेंट खरीदेंगे तो उसको महंगा करेंगे। ट्रैक्टर वाला रेत और बजरी महंगा करेगा। राशन वाला राशन महंगा करेगा। क्या विधवाएं ये सामान नहीं लेती हैं? महंगाई की मार उनको भी झेलनी पड़ेगी। आपने उनको देना है कि नहीं, अभी यह पता नहीं है। आपने मिल्क सैस शराब और बिजली बिल से लिया और अभी तक दूध वालों को नहीं मिला है। इसलिए उनको कितना देना है, इसका पता नहीं है लेकिन उनको मार झेलनी पड़ेगी। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि अनाथ बच्चों और विधवाओं को फायदा होगा। आप उनका फायदा नहीं करेंगे। आप पूरे प्रदेश की जनता जिनमें विधवाएं भी आती हैं, अनाथ बच्चे भी आते हैं उन पर आप आर्थिक बोझ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको वापिस लिया जाए। आप इसको ईगो का प्रश्न न बनाएं। यह हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में है। ...(व्यवधान) मैं यह

विधान सभा में बोल रहा हूं, कोई लोकसभा में नहीं बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप अवस्थी जी को समय दें ताकि ये खड़े होकर बोल लें। इनको बीच में बोलने की आदत है।

23-3-2026/1600/एन0एस-वाई0के0-3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरी तरफ देख कर बोलें।

श्री रणधीर शर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको वापिस लेना चाहिए और इसको पारित नहीं करना चाहिए

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

23.03.2026/1605/RKS/YK-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

यह सरकार के हित में नहीं है। अगर आप 10 पैसे, 50 पैसे या 1 रुपया सस्ता भी करेंगे तब भी हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा करने से वैट का लाभ भी कम होगा। आपने यह देख लेना। जब सेल कम होगी तो निश्चित रूप से वैट भी कम होगा। इसलिए यह संशोधन न हिमाचल के हित में है, न विधवाओं के, न अनाथ बच्चों के और न ही इस सरकार के हित में है इसलिए इस संशोधन को वापिस लिया जाए।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने आप पूरी राजनीति की है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप अनाथ बच्चों व विधवाओं के विरोधी क्यों हैं? आप केंद्र सरकार के पास जाकर यह कहिए कि आपने जो सैस लगाया है उसे 10 रुपये कम कर दीजिए इससे हिमाचल प्रदेश की जनता को फायदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा डीजल पर 27 रुपये और पेट्रोल पर 37 रुपये सैस लिया जा रहा है। फिर आप यहां कैसे अधिकारों को छिनने की बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार ने आर0डी0जी0 के रूप में हमारा हक छिना है।

अध्यक्ष महोदय, जो बजट पर चर्चा होनी है, मैं उस वक्त इन सब बातों का जवाब दूंगा। अभी आप इस बिल को पास करने की अनुमति दें।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार।

23.03.2026/1605/RKS/YK-2

(भाजपा विधायक दल के सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए।)

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर कुछ कहना चाहता हूं। हमने विधवा बहनों और अनाथ बच्चों के प्रति जो बिल लाया है उसमें जिस प्रकास से ये वॉकआउट कर गए इससे ऐसा लगता है कि ये बड़े-बड़े पेट्रोल पम्प वाले उद्यमियों से मिलकर आए हैं। इनके खुद के भी कइयों के पेट्रोल पम्प हैं। लेकिन हम इन धनवान सेठों को छोड़कर विधवा बहनों और अनाथ बच्चों के साथ खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) पारित हुआ"

23.03.2026/1605/RKS/YK-3

(भाजपा विधायक दल के सभी सदस्य सदन में वापिस आए।)

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानः सामान्य चर्चा ।

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान पर सामान्य चर्चा प्रारंभ होगी तथा इसका समापन 25, मार्च 2026 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उत्तर के साथ होगा। समय की उपलब्धता को देखते हुए विपक्ष के नेता को 45 मिनट का समय तथा अन्य सदस्यों को अधिकतम 10-15 मिनट का समय सुनिश्चित किया गया है। मेरा सभी

माननीय सदस्यों से निवेदन रहेगा कि वे अपना-अपना भाषण बजट तक ही सीमित रखकर निर्धारित अवधि के भीतर समाप्त करें

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

23.03.2025/1610/बी.एस./ए.जी.-1

अध्यक्ष जारी...

और जो इश्यूज आपने ऑलरेडी गवर्नर एड्रेस में डिस्कस कर लिए, I think, there is no need to discuss those issues time and again in the budget speech also. मेरे पास बोलने वाले माननीय सदस्यों की लिस्ट भी आ चुकी है और दोनों दलों से पांच- पांच अन्य माननीय सदस्य भी इसमें भाग लेना चाह रहे हैं। यह सदन 7:00 बजे अपराह्न तक चलेगा अगर समय बढ़ाना पड़ा तो बड़ा लेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जय राम ठाकुर जी से कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान पर हिस्सा लें।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट अनुमान यहां इस सदन में मुख्य मंत्री जी ने बतौर वित्त मंत्री प्रस्तुत किए हैं। मैं उस पर चर्चा के लिए यहां खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस सदन के अंदर लगातार बिना रुके 29 बजट देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और जिसमें से 5 बजट मैंने बतौर वित्त मंत्री प्रदेश के मुख्य मंत्री रहते हुए स्वयं की प्रस्तुत किये हैं। अब की बार का जो बजट यहां पर इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया यह 4 घंटे 9 मिनट 33 सेकंड तक चला। मेरे ख्याल से इतना ही समय लगा है और स्वाभाविक रूप से जब आपके पास बोलने को कुछ नहीं है तो अबकी बार नया तरीका निकला गया कि बजट भाषण लंबा कर दो। मैं अपनी सारी बातें बजट को लेकर कहूंगा। लेकिन पहली बात, इस सदन के अंदर बजट प्रस्तुत करने के दौरान जो परंपराएं रही हैं वे टूटी हैं और व्यवस्थाएं तारतार हुई हैं।

पहली परंपरा तो यह टूट गई कि मुख्य मंत्री जी ऑल्टो गाड़ी में आते थे। अब की बार ऑल्टो गाड़ी में नहीं आए। अब की बार वह गाड़ी छोड़ दी और हर वक्त जब यहां आते थे और तो कहते थे ऑल्टो गाड़ी में इसलिए आता हूं कि यह बजट जो है यह समाज के

सामान्य वर्ग के लिए लगे इसलिए मैं ऑल्टो में आता हूं। आप अपना रिकॉर्ड निकाल लेना और ध्यान से देख लेना। आते ही अबकी बार यह परंपरा टूटी है और प्रदेश के बजट का जिक्र करने की बजाय आप बजट भाषण में हार्मोन स्ट्रेट की तरफ पहुंच गए, आपने वहां से शुरुआत की और उसके बाद मिडिल ईस्ट पहुंच गए। उसके बाद एक शब्द का इस्तेमाल किया। उस शब्द के कारण यहां व्यवधान पड़ा। हम ईमानदारी से यहां पर बजट सुनने के

साथ 23.03.2025/1610/बी.एस./ए.जी.-2

लिए आए थे। उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। उस दिन जब विधायक दल के हमारे साथियों के साथ बैठे और एक विषय को लेकर के जो आपका एंटी टैक्स का इशू था उस पर अपनी बात बाहर कहानी थी उसे कह दिया। लेकिन हम सभी विधायकों ने तय किया था कि ईमानदारी से बजट सुनना है। यह एक ऐसा अवसर होता है जब पूरे प्रदेश का हर व्यक्ति इसको सुनता है। इसलिए इसका एक-एक अक्षर सुना जाना चाहिए और हम सब लोग सहमति के साथ यहां पर बैठे थे। लेकिन एकाएक शब्द ऐसा इस्तेमाल कर दिया जिस पर हमको आपत्ति थी और आपत्ति होनी भी चाहिए। हम इस हिमाचल प्रदेश के और इस देश के नागरिक है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

23.03.2026/1615/DT/AG-1

जय राम ठाकुर जारी...

और एक नागरिक होने के नाते जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है उस जिम्मेवारी को निभाते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। हम अपना काम जिम्मेवारी के साथ करते हुए यहां पर पहुचे हैं, इसलिए ऐसे शब्द पर आपत्ति होना स्वाभाविक था। उसके कारण ही व्यवधान हुआ। व्यवधान की वजह हम नहीं थे, वजह वही थे। क्योंकि मुख्य मंत्री महोदय को बजट भाषण पढ़ने में असुविधा हो रही थी इसलिए अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा व्यवस्था दी गई। आपने सदन को 15 मीनट के स्थगित करने की व्यवस्था भी दी। लेकिन मुख्य मंत्री ने चाहा कि हाउस एडजार्न नहीं होना चाहिए और ऐसी सूरत में एडजार्नमेंट वापिस लेने का फैसला आपने किया। जब आपने इसमें उचित समझा की यह बहुत महत्वपूर्ण ऑकेशन है प्रदेश

का बजट प्रस्तुत हो रहा है इसमें हमें कॉर्डिनेशन के साथ बात करनी चाहिए और इस बजट को सुनना चाहिए। आपने उस दिशा में प्रयत्न किया और आप सफल भी हुए। उसका परिणाम यह हुआ कि वह शब्द आपने कार्यवाही से हटाया और उसके बाद हम सभी विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर उस बजट को सुनने के लिए बैठ गये।

इसके बाद माननीय मुख्य मंत्री बजट पढ़ते रहे और यह इतना निरस बजट है कि मैं यहां देख रहा था कि सदन में पहली बार सत्ता पक्ष के विधायक व मंत्री भी ऊब गये और ऊब कर हाउस से बारी-बारी उठकर बाहर जाने लगे। कई बार तो दो-चार सत्ता पक्ष के सदस्य ही सदन में बैठे हुए थे। ऐसे हालात में फिर आपने उचित समझा की बहुत लंबा बजट है जब आपने बजट के पेजिस का जिक्र किया और आपने कहा कि इन्हें पढ़ने में काफी वक्त लगेगा। इसलिए आपके द्वारा एक व्यवस्था और दी गई पहले आपने चाय पीने की व्यवस्था दी फिर उसके बाद लंच के लिए ब्रेक दी। हमनें हमने इस सदन में पहली बार देखा कि बजट चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कई चरणों बजट प्रस्तुत किया गया। पहला चरण व्यवधान का, उसके बाद बजट शुरू हुआ और उसके बाद लंच का दुसरा चरण लंच के बाद तीसरा चरण यानी कई चरणों में बजट प्रस्तुत होकर समाप्त हुआ जिसमें 4 घंटे, 9 मीनट और 33 सैकंड लगे और यही व्यवस्था परिवर्तन है।

हम देख रहे थे कि कुछ-न-कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ तब हुई जब हम लोगों ने कहा कि उस शब्द पर हमें एतराज है। हमने कहा कि किस अधिकारी ने यह शब्द डाला-किसने यह बजट बनाया? तब मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपके समय में बजट अधिकारी बनाते थे और हमारे समय में बजट हम खुद बनाते हैं। तभी तो इस

23.03.2026/1615/DT/AG-2

प्रदेश की वित्तीय स्थिति सही मायने में समझ आई कि इस प्रदेश की स्थिति का वर्तमान में जो हाल बना है वह इस वजह से बना है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री एक पल कुछ कहते हैं और दूसरे पल कुछ कहते हैं। एक तरफ से कह रहे है कि मैं अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दिन-रात मेहनत करके इस बजट को तैयार किया और दूसरी तरफ कहते हैं कि यह बजट अधिकारियों ने नहीं मैंने तैयार किया है।

अध्यक्ष महोदय प्रदेश की वर्तमान स्थिति का भगवान ही मालिक है, अब मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं। हम तो यही कह सकते हैं कि भगवान भरोसे ही प्रदेश चला है। जब अधिकारियों द्वारा बजट न बनाकर मुख्य मंत्री स्वयं बजट बना रहे हैं और आज प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि कि विधवाह के नाम पर और अनाथ बच्चों के नाम पर सरकार को चलाने के लिए

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

23.03.2026/1620/ए.एस.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर..... जारी

इक्ठ्ठा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, यदि हौसला व हिम्मत है तो ऐसा होना चाहिए कि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कदम ले रहे हैं।...(व्यवधान) (माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहना चाह रहे थे) नहीं अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।...(व्यवधान) मैं नहीं बैठूंगा।...(व्यवधान) I am not yielding. ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, यह नहीं होगा।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी ने जवाब देना है तब बोल लेंगे या मेरे वक्तव्य के बाद बोल लेंगे।...(व्यवधान)

Speaker : Shri Jai Ram Thakur ji, will you yield?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, प्लीज नहीं।...(व्यवधान) ऐसा नहीं चलेगा।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पैरा-9 में लिखा है,...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी के पास शब्द आ गए हैं और वे कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी उन शब्दों को लिख कर रख लेंगे।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, आप अधिकारियों को दे दीजिए और वे उन्हें छाप

देंगे।...(व्यवधान) हम आपको पूरा सुनेंगे लेकिन जब हमारा भाषण समाप्त हो जाएगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री जय राम ठाकुर जी, मुख्य मंत्री जी इंटरवीन करना चाहते हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, आप बाद में बोल लेना।...(व्यवधान)

23.03.2026/1620/ए.एस.-एन.जी./2

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप भी बैठ जाइए और नेता प्रतिपक्ष जी भी आपके समय में बैठे रहेंगे।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, आप लास्ट में बोलेंगे।...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी चले ही जाते हैं और कभी रुक भी लिया करो।...(व्यवधान) इनका दिल तो खासतौर पर अध्यक्ष महोदय के साथ लगा हुआ है। बजट के समय नदौन व देहरा का जिक्र हुआ था कि सब कुछ नदौन-देहरा, नदौन-देहरा हो रहा है बाकि प्रदेश का कौन है, मालूम नहीं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने आपको तो दिल में जगह दे रखी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं तो चाहता हूं कि आप सब लोग मुझे दिल में ही जगह दे दें तो मेरे लिए यही काफी है।...(व्यवधान) बाकि काम तो मैं स्वयं कर लेता हूं।...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हमारे दिल में तो आप सदैव रहेंगे।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के बजट में जगह नहीं है लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत जगह है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के पेज नम्बर-3 के पैरा संख्या-9 में मुख्य मंत्री जी कहते हैं "अध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिस्थितियों में हम रेवेन्यू सरप्लस हो ही नहीं सकते हैं, इसके कुछ बुनियादी कारण हैं"।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकते और दूसरी ओर कहते हैं कि वर्ष 2027 में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और वर्ष 2032 में हम देश के सबसे अमीर राज्य हो जाएंगे। मुख्य मंत्री जी, आप एक पल में कुछ कहते हैं और दूसरे पल में कुछ कहते हैं।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, बजट भाषण में आपने कहा है कि हम रेवेन्यू सरप्लस कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब तो यही हुआ कि हम आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब यह भी हुआ कि वर्ष 2032 में हम देश के अमीर राज्य नहीं हो सकते।

23.03.2026/1620/ए.एस.-एन.जी./3

इसके बाद भी मुख्य मंत्री जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा अंतर है और सचमुच में हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, अब तो मुख्य मंत्री जी को इंटरवीन करने दीजिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, मुख्य मंत्री जी रिकॉर्ड स्टेट कर देंगे कि ये क्या चाहते हैं।...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री, आप बोलिए।...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : मुझे उठना जरूरी है।(विपक्ष के माननीय सदस्यों को देख कर कहा)...(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष जी, बजट भाषण की लाइन पढ़ रहे हैं तो मैं इनके कथन को थोड़ा ठीक कर दूं।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हम आज जो बिल लेकर आए थे, वह सरकार चलाने के लिए नहीं लाए हैं। यह सैस नियमानुसार उन्हीं पर खर्च होगा जो विधवा या अनाथ होगा। कोई भी इसे इधर-उधर खर्च नहीं कर सकता।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

23.03.2026/1625/ए0एस0/ए0पी0/-01

मुख्य मंत्री जारी .....

एक बात और, हम रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में इस समय नहीं हो सकते। लेकिन जो नीतिगत परिवर्तन हम ला रहे हैं उससे वर्ष 2027 में राज्य आत्मनिर्भर होगा और वर्ष 2032 तक सबसे समृद्धशाली राज्य भी बनेगा। इसका उदाहरण भी मैं देना चाहता हूं। आपको उदाहरण देना जरूरी है क्योंकि आप किसी और ही दिशा में चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें 3 वर्षों में 17,000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 ग्रांट के रूप में मिले। ...(व्यवधान) सुन लो न ...(व्यवधान) आत्मनिर्भर की बात बता रहा हूं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमें 17,000 करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 ग्रांट मिली। भारतीय जनता पार्टी को उनके समय में आर0डी0जी0 ग्रांट के रूप में 47,000 करोड़ से 54,000 करोड़ रुपये मिले और जी0एस0टी0 कंपनसेशन के रूप में 13,000 करोड़ से 16,000 करोड़ रुपये तक मिले। लगभग 70,000 करोड़ रुपये उन्हें पांच वर्ष के कार्यकाल में मिले। आप ही बताइए कि 17,000 करोड़ रुपये से नीतिगत परिवर्तन लाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना कितना कठिन है। जिस राज्य की सरकार को 70,000 करोड़ रुपये अधिक दिए गए हों वे उससे राज्य का कर्ज कम कर सकते थे। लेकिन वे 76,700 करोड़ रुपये का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपये का एरियर हमारे लिए छोड़कर चले गए। पूर्व सरकार द्वारा जो वैट के पांच रुपये कम किए गए थे। उन्हें हमने जैसे ही लगाया, उसके लिए जनता ने भी हमें समर्थन दिया। जनता ने हमें दो-तिहाई बहुमत से जीत दिलाई और वे छह सीटें, जिन्हें आपने खरीदा था, वे भी हमने जीतीं। यह जो नियम हमने बनाए हैं यह आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना है और इस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह जो वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया है। वह हमने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दिया है। जिसे आज तक इस संपदा से कुछ नहीं मिला। उसी को ध्यान में रखकर हमने यह बजट बनाया है।

23.03.2026/1625/ए0एस0/ए0पी0/-02

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा। अध्यक्ष महोदय, कहते हैं

भ्रम में हैं वो कि कल भी वक्त होगा,
रुख़सत होंगे वे अधूरी ख्वाहिशें लेकर।

अध्यक्ष महोदय इनकी यह ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी, पूरी नहीं हो पाएंगी। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि ख्वाहिशें रखिए लेकिन ऐसी ख्वाहिशें मत रखिए जो अधूरी रह जाएं। वे आपको अधिक पीड़ा, दर्द और तकलीफ देंगी और रात को सोने नहीं देंगी। इसलिए अच्छा होगा कि ख्वाहिशें थोड़ी रखें। इससे आगे तो ख्वाहिश बिल्कुल भी मत रखना क्योंकि वह ख्वाहिश और भी अधिक पीड़ादायक होगी। अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुत हुआ और बजट में वही ढाक के तीन पात। जब मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया कि बजट अधिकारियों ने नहीं बल्कि उन्होंने बनाया है तो हम सबने सोचा कि इस बार का बजट बहुत अच्छा होगा, कुछ हटकर होगा या बेहतर होगा। अध्यक्ष महोदय, यह इस सरकार का चौथा बजट है और इसके बाद आपका मात्र एक बजट शेष रहेगा, जो चुनावी वर्ष का होगा। उसके बाद विदाई की शहनाई बज जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आप कल्पना करें कि देश कहां जा रहा है। वर्ष 2023-24 का बजट 53,412 करोड़ रुपये था, वर्ष 2025 का बजट 58,514 करोड़ रुपये था और वर्ष 2026-27 का जो बजट आपने प्रस्तुत किया है, वह 54,928 करोड़ रुपये का

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

23.03.2026/1630/AT/DC/01

श्री जय राम ठाकुर जारी...

है। यानी कि आप लगभग वहीं पहुंच गए हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो बजट प्रस्तुत हुआ। वह भी पिछले बजट की तुलना में कम था। आगे बढ़ने की बात तो दूर अगर हम एक ही जगह पर खड़े रहते तो भी हमें कुछ तसल्ली होती कि हम स्थिर हैं। लेकिन हम तो वहां से भी पीछे चले गए हैं जहां से शुरुआत की थी। यह प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम पिछले दो कार्यकाल के बजट की तुलना करें और 100 रुपये के व्यय को आधार मानें तो वर्ष 2018-19 में 39.56 रुपये विकास कार्यों पर खर्च होते थे। वर्ष 2019-20 में भी 39.56, वर्ष 2020-21 में 41.22 और वर्ष 2021-22 में यह अब तक का सबसे अधिक 43.94 था, यानी लगभग 1 रुपये में से 44 रुपये विकास कार्यों पर खर्च होते थे जब हमारी सरकार थी। इसके बाद वर्ष 2022-23 में यह घटकर 29 रुपये रह गया। जब से आप सत्ता में आए हैं महानुभाब जी आपने जब से चरण चरणबद्ध तरीके से रखे हैं। आप देखिए कि आप किस तरह से चले है। विकास कार्यों के लिए वर्ष 2023-24 में 29 रुपये, वर्ष 2024-25 में 28 रुपये आपका दूसरा चरण उस से भी पीछे चला गया और वर्ष 2025-26 जब आपका तीसरा चरण चला तो यह घटकर 24 रुपये रह गया। अब वर्ष 2026 में 100 रुपये में से केवल 20 रुपये ही विकास कार्यों के लिए रह गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है। यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज और अन्य खर्चों को भी इसमें से निकाल दें तो यह राशि 5 से 6 रुपये के बीच ही रह जाती है। यह आंकड़े अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए हैं और मुख्य मंत्री जी ने बतोर वित्त मंत्री उस पर मोहर लगाई है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि विकास के लिए पैसा नहीं है। अगर नहीं है, तो इसे स्वीकार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे वह प्रेजेंटेशन अच्छी तरह याद है जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने हमारे सामने रखी थी जिसमें कहा गया था कि विकास के लिए पैसा नहीं बचेगा क्योंकि पहले देनदारियों का भुगतान करना होगा फिर सब्सिडी, ब्याज और ऋण की अदायगी

23.03.2026/1630/AT/DC/02

करनी होगी। इन सबके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सच्चाई तो यह है, अगर यही सच्चाई है तो इसे छुपाया क्यों जा रहा है? जब छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं है तो इसे छुपाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंत में सच्चाई छुपती नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़कर एक और बात करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी मीडिया में लगातार अपनी बातें रखते हैं और स्वाभाविक है कि मीडिया उन्हें प्रकाशित भी करता है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है और मैं आपके प्रति पूरा सम्मान रखता हूं। लेकिन थोड़ा सा हमारी बात भी प्रकाशित कीजिए जो हम कह रहे हैं। खास तौर पर मैं एक तुलना आपके सामने रखना चाहता हूं। हमें बार-बार कहा जाता है कि आपने ऋण लिया, आपने ऋण लिया, आपने ऋण लिया

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

23.03.2026/1635/केएस/डीसी/1

श्री जय राम ठाकुर जारी ---

(श्री अनिल शर्मा, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

सभापति महोदय, अगर मैं वर्ष 2010 से शुरू करुं, पीछे के आंकड़े मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लम्बा चला जाएगा। जब इस प्रदेश की बागडोर आदरणीय धूमल जी के पास थी, वर्ष 2010 में प्रदेश का ऋण 23 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा। वर्ष 2011 में आदरणीय धूमल जी मुख्य मंत्री थे। उस समय 8.70 परसेंट एनुअल ग्रोथ के साथ ऋण पहुंचा 25 हजार करोड़ रुपये। वर्ष 2022 में भी आदरणीय धूमल जी मुख्य मंत्री थे। जब उन्होंने सरकार छोड़ी तो एनुअल ग्रोथ 15.04 परसेंट के साथ 28,760 करोड़ रुपये ऋण पहुंचा । फिर उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और आदरणीय वीरभद्र प्रदेश के मुख्य मंत्री बने। वर्ष 2013 में उनके कार्यकाल में 11.27 परसेंट की एनुअल ग्रोथ के साथ ऋण पहुंचा 32 हजार करोड़ रुपये। फिर वर्ष 2014 में भी वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे। उस समय एनुअल ग्रोथ 10.94

परसेंट के साथ ऋण पहुंचा 35,500 करोड़ रुपये । उसके बाद वर्ष 2015 में भी प्रदेश के मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी थे। 9.86 परसेंट एनुअल ग्रोथ के साथ ऋण पहुंचा 39 हजार करोड़ रुपये। उसके बाद वर्ष 2016 में भी वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे। उस समय एनुअल ग्रोथ 10.26 परसेंट के साथ 43 हजार करोड़ रुपये प्रदेश के ऊपर ऋण हो गया। वर्ष 2017 में वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल का अंतिम वर्ष था। एनुअल ग्रोथ 12.79 परसेंट के साथ 48,900 करोड़ रुपये के लगभग ऋण पहुंचा। अगर कांग्रेस के पूरे कार्यकाल का हिसाब निकाला जाए तो ओवर ऑल ऋण की ग्रोथ 10 परसेंट के हिसाब से रही और इतनी ही लगभग धूमल जी के समय में भी रही।

सभापति महोदय, हमारी सरकार वर्ष 2018 में आई और वर्ष 2018 में एनुअल ग्रोथ 3.09 परसेंट के साथ हमारे पहले साल का ऋण 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा। वर्ष 2019 में मैं मुख्य मंत्री था, वित्त मंत्री था तो एनुअल ग्रोथ 6.0 परसेंट के साथ ऋण पहुंचा 53 हजार करोड़ रुपये। वर्ष 2020 में हमारी सरकार में 9.43 परसेंट एनुअल ग्रोथ के साथ ऋण पहुंचा 58 हजार करोड़ रुपये । उसके बाद वर्ष 2021 में 8.6 परसेंट एनुअल ग्रोथ के साथ 63 हजार करोड़ रुपये तक ऋण पहुंचा। यह कोविड का

23.03.2026/1635/केएस/डीसी/2

दौर था। उसके बाद जो मेरा अंतिम वित्तीय वर्ष था जहां मैंने कन्क्लूड किया और उसके बाद श्री सुखविन्दर सिंह सूक्खू जी आए तो लास्ट ईयर का 68, 700 करोड़ रुपये का ऋण प्रदेश के ऊपर हुआ और एनुअल ग्रोथ 8.89 परसेंट थी। मेरा पांच साल के ऋण लेने की परसेंटेज 7.2 थी। जब उसके बाद सुक्खू जी के चरण आए, चरणबद्ध तरीके से आप आए श्रीमान जी, ...(व्यवधान) सुन लीजिए। बहुत दिलचस्प है। मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। ...(व्यवधान) नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हिसाब दे रहा हूं। सभापति महोदय, आगे बढ़ते हैं।

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, मैं करेक्ट करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : मैं वह भी हिसाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान) उसके बाद सभापति महोदय, इनके चरण पड़े। पहला चरण आपका पड़ा ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, मैं करेक्ट करना चाहता हूं।

सभापति : मुख्य मंत्री जी, आपको समय मिलेगा। इनको बोलने दें।

श्री जय राम ठाकुर : नहीं, सभापति महोदय, मैं नहीं बैठूंगा। यह पॉसिबल नहीं है। ...(व्यवधान) कृपया आप सुनो तो सही। अब आगे बढ़ते हैं। ...(व्यवधान)

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

23.03.2026/1640/av/hk/1

श्री जय राम ठाकुर------- जारी

मैं पूरा हिसाब लेकर आया हूं जोकि मैं आज चुकता करके ही जाऊंगा। जब हमारी व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार के चरण पड़े तो वर्ष 2023 में 16.62 प्रतिशत एनुअल ग्रोथ के साथ ऋण 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा। उसके बाद वर्ष 2024 में ऋण 93 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, यह नहीं हो सकता। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं नहीं बैठूंगा। इस तरह से तो हमारा बोलना बेकार है। आपने पहले चरण में सीधा 80 हजार करोड़ रुपये पहुंचाया और माननीय मुख्य मंत्री, वर्ष 2024 में आपका दूसरा चरण पड़ा जब 16.25 एनुअल ग्रोथ के साथ ऋण 93 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया। उसके उपरांत वर्ष 2025 में 16.13 प्रतिशत एनुअल ग्रोथ के साथ ऋण 108000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। एनुअल ग्रोथ के हिसाब से अगर इनके ऋण की औसत वैल्यू देखी जाए तो 16.13 प्रतिशत आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी, आप बाद में बोल लेना। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक नया काम 'ऑफ बजट बोरॉईंग' शुरू किया है। यह गलती वर्ष 1994 से 1998 तक हुई थी। उस समय विद्युत कॉरपोरेशन से लोन लिया गया था। उसके बाद आपने हुडको से 3 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया है। ...(व्यवधान) वह आपने लैण्ड एक्विजिशन का कम्पनसेशन देने के लिए बांट भी दिया और वह पैसा अभी तक इसमें रिकॉर्डिड नहीं है। अगर उसको भी मिलाया जाए तो आपका लोन 111000 करोड़ रुपये से

ऊपर चला गया है। धन्य हो, आपके चरण जबसे इस प्रदेश में पड़े हैं उसको प्रदेश की जनता कभी नहीं भूल सकती।

सभापति महोदय, ये बोलते हैं कि भाजपा सरकार में ऋण 76 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। हमने जब लगभग 69 हजार करोड़ रुपये के करीब छोड़ा था तो हमारी लोन की 65000 करोड़ रुपये की लिमिट पैंडिंग थी जोकि हमने एग्जॉस्ट नहीं की थी। वह हमने इसलिए नहीं कि थी कि बेवजह का लोन क्यों लेना। हमें जितनी जरूरत थी उसके मुताबिक ऋण लिया। लेकिन जब प्रदेश में श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी की सरकार के चरण पड़े तो तीन महीने में 65000 करोड़ रुपये ले लिए और उसमें वित्तीय वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काउंट किया गया जबकि तब तक

23.03.2026/1640/av/hk/2

हम विपक्ष में आ गए थे यानी उसको भी हमारे खाते में डाल दिया गया। ...(व्यवधान) वित्तीय वर्ष की बात मत कीजिए, आप हमें यह बताइए कि उसको यूज़ किसने किया?

सभापति महोदय, ये आर0डी0जी0 की बात करते हैं। इनके खाते में 30 हजार करोड़ रुपये गए हैं क्योंकि अक्तूबर माह में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। उसके बाद अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक पैसा किसने यूज़ किया, क्या उसको जय राम ठाकुर या भाजपा की सरकार को यूज़ करने दिया गया? मैं अपने मीडिया के साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करें इस डाटा को थोड़ा ठीक कर लें जोकि जनता के सामने गलत जा रहा है। यह लगभग 30 हजार करोड़ रुपये के करीब था। आप री-पेंमैंट की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) हमारा तो आपने एक-एक जमा किया और उसके लिए तो आप हर समय कैल्कुलेटर पर हिसाब लगाते रहते हैं। ...(व्यवधान)

टी सी द्वारा जारी

23.03.2026/1645/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री जय राम ठाकुर ... जारी

सभापति महोदय, ये फैक्ट्स प्रदेश के सामने जाने चाहिए। यह आंकड़े चौकाने वाले भी हैं और जब हम इन्हें दुरुस्त कर रहे हैं तो थोड़ा हैरान करने वाले भी हैं।

सभापति महोदय, आगे बढ़ते हुए, इन्होंने पूछा कि हमने कितना लोन वापिस किया? अगर मैंने अपने कार्यकाल में मु0 40,352 करोड़ रुपये का लोन लिया तो मु0 38,276 करोड़ रुपये वापिस भी किए। हमारी लोन रिटर्न करने की परसेंटेज 95 प्रतिशत रही यानी जो लोन हमने लिया था उसका 95 प्रतिशत हमने वापिस किया और केवल 5 प्रतिशत की ग्रोथ हमारे समय में हिमाचल प्रदेश में हुई, यह भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। वहीं, जब आपके (मुख्य मंत्री जी की ओर इशारा करते हुए) चरण पड़े तो अभी तक आप लोन की री-पेमेंट 60 प्रतिशत भी टच नहीं कर पाए है। इसलिए आपको इन सभी बातों को भी समझना पड़ेगा। अगर हम रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करें, आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मैं यह भी रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। अगर आप पंद्रहवें वित्तायोग से मिलने वाले समस्त केंद्रीय अनुदान को देखें क्योंकि आर0डी0जी0 अभी 31 मार्च तक मिल रही है तो वर्ष 2021-22 में कुल 24,990 करोड़ रुपये, वर्ष 2022-23 में 22,723 करोड़ रुपये, वर्ष 2023-24 में 24,315 करोड़ रुपये,वर्ष 2024-25 में 23,413 करोड़ रुपये, वर्ष 2025-26 में 23,050 करोड़ रुपये और वर्ष 2026-27 में आर0डी0जी0 बंद होने के बावजूद भी 21,124 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि सेंट्रल टैक्सिज का शेयर बढ़ा है, उसमें ग्रोथ हुई है और केन्द्र सरकार से जो डेवोल्यूशन के रूप में पैसा आता है उसमें भी वृद्धि हुई है।

सभापति महोदय, एक और आंकड़ा है जिसे यह लोग हमेशा छुपाते हैं। सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस जो इनको मिल रही है, हमारे समय में बहुत कम थी क्योंकि उस समय केन्द्र सरकार का बजट कम था लेकिन इस कार्यकाल में मोदी जी ने लगातार उस राशि को बढ़ाया। वर्ष 2023-24 में 1,516 करोड़ रुपये, वर्ष 2024-25 में 2,380 करोड़ रुपये और

वर्ष 2025-26 में लगभग 3,400 करोड़ रुपये मिले यानी लगभग 7,300 करोड़ रुपये आपको 50 वर्ष के लिए बिना ब्याज के मिल चुके हैं।

23.03.2026/1645/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

यह आंकड़ा हमने बड़ी मेहनत से निकाला है जिसे आप छुपाते रहे। यह बिल्कुल फैक्ट्स पर आधारित है। जहां हमें 5 वर्ष में केवल 1,800 करोड़ रुपये मिले क्योंकि उस समय इस हैड में राज्यों को देने के लिए बहुत कम पैसा होता था, वहीं आप लगभग 7,300 करोड़ रुपये ले चुके हैं। इसके बावजूद आप कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने कुछ नहीं किया।

सभापति महोदय, दूसरी बात, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर आपने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया हुआ है। आप दिल्ली गए, आपको वित्त मंत्री से मिलना चाहिए था, आपको प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए था लेकिन आप राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के पास चले गए। आपने वहां जाकर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात की तो जवाब मिला, what is this RDG? What I have to do with this? यानी उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

23-3-2026/1650/एन0एस-वाई0के0-1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

आप मंत्रिमण्डल को लेकर गए और आपके राष्ट्रीय नेता आपको यह बोलते हैं कि what I have to do with this. मुझे क्या करना है, आप अपना प्रदेश देखें। What is this RDG? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने यह आंकड़ा बहुत मेहनत से निकाला है क्योंकि जब आप गलत बोल रहे हैं तो हमें उसको ठीक करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ी और हमने मेहनत की।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

वर्ष 1974 से लेकर वर्ष 2014 तक यानी 40 वर्षों में मोदी जी की सरकार से पहले आर0डी0जी0 जो हिमाचल प्रदेश को मिली है उसको हमने कैलकुलेट करके निकाला है और ये 21,956 करोड़ रुपये मिले हैं। ...(व्यवधान) ये फिग्र्ज हैं और आप इनको बाद में देख लेना। अध्यक्ष महोदय, यू0पी0ए0 की सरकार देश में रही और उस समय देश के प्रधानमंत्री जाने-माने अर्थशास्त्री थे और वे देश के ही नहीं दुनिया के जाने-माने अर्थशास्त्री थे। यह बात अलग है कि चलाता कोई और ही था। हिमाचल प्रदेश को दो फाइनैंस कमीशन में 18,000 करोड़ रुपये मिले। प्रदेश को एक बार 10,202 करोड़ रुपये और दूसरी बार 7,889 करोड़ रुपये मिले जोकि लगभग 18,000 करोड़ रुपये बनते हैं और ये दस वर्षों में मिले। यू0पी0ए0 की सरकार के बाद जब एन0डी0ए0 की सरकार बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हिमाचल प्रदेश को 14वें वित्तायोग में 40,624 करोड़ रुपये मिले और 15वें वित्तायोग में 37,189 करोड़ रुपये मिले। उसके बाद हमें कोविड के कारण बीच में इंटरिम रिलीफ 11,431 करोड़ रुपये मिले। अगर इन तीनों राशियों को मिलाएं तो यू0पी0ए0 सरकार के 18,000 करोड़ रुपये के एवज में हमें 89,254 करोड़ रुपये मिले। हमें ज्यादा मिला। अब आप बताइए कि अन्याय तब हुआ जब 18,000 करोड़ रुपये मिले या अन्याय तब हुआ जब 89,254 करोड़ रुपये के रूप में हमें आर0डी0जी0 मिली। मोदी जी ने डॉ0 मनमोहन सिंह जी से लगभग 72,000 करोड़ रुपये ज्यादा दिए। उसके बावजूद भी आप मोदी जी को पानी पी-पी कर कोस रहे थे। यहां पर आपने उस दिन इतने ज्यादा गिलास पानी के पी लिए। आप कल्पना कीजिए लेकिन यह स्थिति सबके सामने आनी चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आर0डी0जी0 बंद होने के कारण आर्थिक संकट और ज्यादा गंभीर हुआ है। मैं यह भी कह सकता हूं कि हमारे

23-3-2026/1650/एन0एस-वाई0के0-2

सामने चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अपॉरच्युनिटी भी है। आप कहते हैं कि आप योद्धा हैं। फिर योद्धा तो ऐसे लम्बे नहीं पड़ते हैं जैसे आप अपने आपको दिखा रहे हैं, यह उचित नहीं है। अगर आप योद्धा हैं तो योद्धा की तरह लड़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर बजट भाषण की तरफ जाना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने यहां पर आंकड़े गोल-गोल घूमा कर पेश किए हैं और इसके लिए अंग्रेजी में एक कहावत है 'You can be fool one person all the times, but you cannot be fool all the persons all the times.' इसको हिंदी भाषा में कहते हैं कि 'काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती।' यह एक मुहावरा है। यह हो गया और प्रदेश ने अनुभव कर लिया। चरणबद्ध तरीके से प्रदेश का जो (***) उसकी स्थिति आपके सामने है।

अध्यक्ष : (***) शब्द कार्यवाही से निकाले जाएं।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

23.03.2026/1655/RKS/YK-1

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको पावर सैक्टर के बजट प्रावधानों के बारे में बताउंगा। आप देखिए कि इस क्षेत्र में वर्ष 2024 में 570 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 में 838 करोड़ रुपये यानी 47 प्रतिशत इंक्रीज थी। इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में 268 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें 472 करोड़ रुपये की कमी पाई गई है यानी यह बजट 56.12 प्रतिशत माइनस किया गया है। इसके बावजूद भी आप यह कह रहे हैं कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट का बजट 20.59 प्रतिशत माइनस चला गया है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में 21.15 प्रतिशत बजट कम किया गया है। पिछली बार इस क्षेत्र में 201 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था जबकि इस बार 158 रुपये बजट प्रावधान रखा गया है। वाटर सप्लाई में 42.06 प्रतिशत कम बजट प्रावधान किया गया है। यह हो क्या रहा है? एलिमेंट्री एजुकेशन में 44.47 प्रतिशत बजट कम किया है। स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में 47.06 प्रतिशत बजट कम किया गया है लेकिन आप रोबोटिक सर्जरी की ओर जा रहे हैं। मैं इस पर भी बाद में बोलूंगा। कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक्टिविटीज में 34.39 प्रतिशत कम बजट प्रावधान किया गया है। आप ग्रामीण

अर्थव्यवस्था को सुधारने जा रहे हैं लेकिन आपने इस क्षेत्र में 52.12 प्रतिशत बजट कम किया है। आप महिला विकास की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अति गरीब महिलाओं को फ्री बिजली की सुविधा और हर माह 1500 रुपये देंगे। आपने एस0सीज0, ओ0बी0सीज0, माइनोरिटीज और सोशल वेलफेयर सिक्योरिटी पेंशन में 62.63 प्रतिशत कम बजट का प्रावधान किया है। वुमेन एंड चाइल्ड डवलपमेंट में भी आपने बहुत कम बजट दिया है। अगर हम बजट का टोटल करें तो आपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 42 प्रतिशत बजट कम किया है। अब आप अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन आपने महत्वपूर्ण विभागों का इतना बजट कम कर दिया है। वर्ष 2011 के बाद अगर हम स्थाई नौकरियों का आंकड़ा देखें तो वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश में 1,87,604 स्थाई नौकरियां थीं और उस वक्त प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। वर्ष 2012 में 1,87,419 और वर्ष 2013 में 1,87,761 स्थाई नौकरियां थीं। वर्ष 2012 के अंत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री बन। प्रदेश में वर्ष 2014 में 1,83,600, वर्ष 2015 में लगभग 1,82,000, वर्ष 2016 में 1,78,744 और वर्ष 2017 में 1,77,388 स्थाई नौकरियां थीं। मैं आपको यह रिकॉर्डिड फिगर बता रहा हूं।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

23.03.2025/1700/बी.एस./ए.जी.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

वर्ष 2017 में आदरणीय वीरभद्र सिंह जी थे, उस वक्त 1,77,388 थी।ये सब रिकॉर्डिड फिगर्स हैं और जब हमारी सरकार बनी तो हमारे समय में इसमें ग्रोथ आई और यह 1,81,376 हुई, वर्ष 2019 में 1,81,231 इसमें मामूली सी चेंज है। वर्ष 2020 में 1,81,379, उसके बाद वर्ष 2021 में 1,87,899, वर्ष 2022 में 1,90,137 और आपकी सरकार में यह घटते- घटते वर्ष 2023 के बाद चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग चरणों में वर्ष 2023 में 1,85,698 वर्ष 2024 में 1,80,800, वर्ष 2025 में 1,75,579 यानी के आपकी सरकार के कार्यकाल में लगभग 15,000 नौकरियां समाप्त हुई हैं। हम समझते हैं कि इनमें से कुछ रिटायरमेंट भी हुए होंगे। लेकिन आप जो बात कहते थे कि हम नौकरियां देंगे। एक लाख

नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में देंगे और यह आपकी गारंटी थी। कहते थे 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे और पक्की नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां, 58 साल वाली नौकरियां, यही बोलते थे। आपकी वह नौकरियां चरणबद्ध तरीके से कम हो रही हैं अभी तो 3 साल हुए हैं, अभी चौथा साल पूरा होना है। आपकी अभी से 15,000 से ज्यादा नौकरी खत्म हो गई हैं। लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिली है और उन सारी चीजों को ले करके मैं समझता हूं कि अब यह आंकड़े आपके सामने आए हैं। मैं इस बारे में थोड़ा बाद में भी बात करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ करके अगर हम चीजों को देखें तो अबकी बार मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण का जिक्र हार्मोन स्ट्रेट से किया है और उन सारी चीजों को ले करके मैं अगर लंबी बात कहूं तो यह उचित नहीं है। लेकिन यह सच्चाई है कि प्रदेश की स्थिति आज की तारीख में आर्थिक दृष्टि से ऐसी हो गई है कि हम एक तरह से वेंटिलेटर पर हैं और वेंटिलेटर पर होने का मतलब कि पूरा हिमाचल प्रदेश आज बिल्कुल लाइव स्पोर्ट्स सिस्टम पर ही आ गया है, अब कहीं अगला चरण ऐसा ही रहा तो अगले चरण में तो फिर जैसे डॉक्टर मरीज को बोलते हैं कि अब ले जाइए और सेवा करिए यह हमारी स्थिति बन रही है। इसमें मैं अपने आप भी महसूस करता हूं कि यह स्थिति बहुत ही खराब है और यह बहुत चिंता का विषय है।

23.03.2025/1700/बी.एस./ए.जी.-2

अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ करके हम इस बात को देख रहे थे कि अब की बार का जो बजट है यह 3,586 करोड़ रुपये के घाटे का है। यानी के 6.3 परसेंट की इसमें गिरावट है और हम इस बात को ले करके पहले से कह रहे हैं कि पूरी दुनिया भर के बजट आगे की तरफ पढ़ रहे हैं। चाहे वह देश का बजटहो या प्रदेश का बजट, हर बजट आगे की तरफ बढ़ रहा है और संभवतः पूरे देश में से हिमाचल एकमात्र राज्य है जिसका बजट आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात कहें, ...(घंटी)... अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने एक डॉक्यूमेंट शुरू किया। मैं दूसरे पर आ ही रहा हूं।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, मैंने आपको याद दिला ली कि मैंने आपको 5 मिनट और ज्यादा दे दिये हैं। यदि आप और समय चाहेंगे तो आपको और समय दे देंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि इसमें बहुत मेहनत से काम किया हुआ और यह बहुत लोगों के काम आएगा और आपके भी बहुत काम आएगा। अध्यक्ष महोदय यदि पूंजीगत निवेश की बात करें तो वर्ष 2023-24 में 6,781 करोड़ रुपये। वर्ष 2024 में 6,229 करोड़ करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 में 3,941 करोड़ रुपये है तथा वर्ष 2026-27 के इस बजट में हम जा करके कहां खड़े हो गए

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

23.03.2026/1705/DT/AG-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

3090 करोड़ पर और यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कैपिटल इंवेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें 6781 करोड़ रुपये से 3090 करोड़ में पहुंच गये हैं। पूंजिगत निवेश की अगर हम बार करें तो वह 55% गिर गया है और हम नीचे की तरफ आ गये हैं। यह सचमुच में दिल को दहलाने वाला मामला है। कैसे हमारे विकास कार्य होंगे, कैसे हमारी सड़कें बनेगी, कैसे वॉटर सप्लाई स्कीम्ज बनेंगी, कैसे इनका मेंटेंन्स होगा, कैसे हम हास्पिटल बनाएंगे? आप व्यवस्था परिवर्तन का जो दौर लेकर आयें हैं उसमें प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रैंथन करने की दृष्टि से काम करेंगे? हमारी सरकार के समय more than 7000 crore Rupees से ऊपर हमारा पूंजिगत निवेश था लेकिन आज वह 3089 करोड़ तक आ गया तो यह आंकड़ा सचमुच में प्रदेश के लिए प्रदेश को बहुत परेशान करने वाला है।

अगर हम राजकोषीय घाटे की बात करें तो वर्ष 2023-2024 में 10300 करोड़ रुपये, वर्ष 2024-2025 में दूसरे चरण में 10337 करोड़ रुपया, तीसरे चरण में यानी वर्ष 2025-2026 में यह 12,414 करोड़ बढ़ा, वर्ष 2026-2027 में 9896 करोड़ रुपये पर हम पहुंचे-यह सरकार का बजट डाक्यूमेंट कहता है। चार वर्षों में राजकोषीय घाटा 42947 करोड़ रुपये यानी अब लगभग 45000 करोड़ तक पहुंच गया है, क्या यह ये दिखाता है कि हम सहीं दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? यह प्रदेश के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। राजस्व घाटे में अगर

हम रोज के खर्चे का भी जिक्र करें तो सचमुच उसमें उधार के सिवाय और कुछ राजस्व नहीं है। क्योंकि राजस्व की रेवेन्यू रिसिट हमारी 4361 करोड़ रुपये की है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 46938 करोड़ रुपये है। इसके बाद प्रदेश का जो रेवेन्यू डेफिसिट रहता है 6577 करोड़ रुपये रहता है। वह क्या दर्शाता है, वह रोजमर्रा के खर्चे, वेतन, पेंशन, बिजली की बिल आदि दर्शाता है। आज ऐसी स्थिति में प्रदेश खड़ा हो गया है जहां आने वाली जरनेशन हमको इस बात के लिए हमेशा कोसती रहेगी। वे कहेंगे कि आखिर जब इस प्रदेश में ऐसी परिस्थिति बन रही थी तो माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सक्खू जी चरणबद्ध तरीके से क्या कर रह थे? व्यवस्था परिवर्तन की वह सरकार क्या कर रही थी? अध्यक्ष महोदय, अगर प्रदेश में कर्ज का हम जिक्र करें तो जितना सरकार लेती है उससे ज्यादा सरकार को चुकाना पड़ता है। वर्ष 2026-2027 में ऋण की जो अदायगी सरकार के द्वारा की जानी है वह लगभग 13000 करोड़ रुपये से अधिक है।

23.03.2026/1705/DT/AG-2

इसे चुकान के लिए फिर सरकार 10000 करोड़ रुपये के लगभग लोन लेगी। इसके बाद भी सरकार के पास 3000 करोड़ रुपये का गेप रह जाएगा। उसकी भरपाई सरकार के द्वारा कैसे की जायेगी, यह भी एक चिंता का विषय है। उसका जिक्र बजट में कहीं भी नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, हमने ओ0पी0एस0 का कभी विरोध नहीं किया। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि ओ0पी0एस0 का सही मायने में इम्पैक्ट 2027 के बाद आयेगा? क्योंकि प्रदेश में जो कर्मचारियों की बल्क में रिटायरमेंट होगी वह वर्ष 2027 के बाद ही होगी, उसके बाद एक कदम भी रखना बहुत कठिन हो जायेगा। मुख्य मंत्री भी अधिकारियों को कह ही रहे हैं कि कोई रास्ता निकालो और कह रहे हैं कि क्या हम यू0पी0एस0 की ओर जा सकते हैं? क्या हम फाइनेंशल लाइबिल्टी स्टेट से सैंटर को ट्रांसफर कर सकते हैं? माननीय मुख्य मंत्री ने राजनैतिक दृष्टि से एक फैसला लेना था और उन्होंने वह लिया-उसका इनको लाभ भी हुआ और ये सत्ता में आ गये और लोकतन्त्र में इसे स्वीकार भी करना चाहिए। हमने बड़े हर्ष के साथ इस को स्वीकार भी किया। लेकिन चिंता का विषय आने वाली जनरेशन के लिए है क्योंकि फाइनेंशन इम्पैक्ट जिस प्रकार से

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

23.03.2026/1710/ए.एस.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर..... जारी

2027 के बाद लोड होगा, उसके बाद आने वाली पीढ़ी के लिए नौकरी की संभावनाएं/गुंजाइश तो शायद नहीं रहेंगी, खासकर सरकारी क्षेत्र में और यह स्थिति हमारे सामने आने वाली है क्योंकि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति वर्तमान में जिस प्रकार से दिखाई दे रही है। मैं इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत लम्बी बात नहीं करना चाहूंगा लेकिन आपको ऐसे रास्ते अपनाने पड़ेंगे जिससे आर्थिक तंगी से बाहर निकला जा सके। हालांकि मैं सुझाव देने की सोच रहा था, लेकिन सुझाव देने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि आप (मुख्य मंत्री जी को कहा) पहले तो सुनते ही नहीं हैं और अगर सुनते भी हैं तो मानते नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी, सब लोगों की ऐसी धारणा आपके बारे में बन गई है। इस धारणा से आप कैसे बाहर निकलेंगे, मुझे लगता है कि यह बहुत कठिन है। अभी आपने नया एलान कर दिया कि हम डिफरमैंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य नहीं है कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के दरवाज़े को खटखटा चुके हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब क्या है, यही तो है। अगर आप प्रदेश में किसी के पैसे काट सकते हैं, तो वह सिर्फ तभी संभव है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है, जोकि आर्टिकल 360 के अंतर्गत आती है। आपने यह 50, 30 या 20 प्रतिशत का जो डिफरमैंट किया है, क्या कानून इसकी अनुमति देगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में कोविड के दौरान सैलरी काटी गई थी। माननीय हाई कोर्ट में सरकार के विरोध में फैसला हुआ कि ऐसा नहीं किया जा सकता। वहां की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट

ने भी फैसला दिया कि सैलरी नहीं काटी जा सकती। ऐसी स्थिति कहीं यहां भी न बन जाए। आप बहुत चालाकी व चुस्ती से राजनीतिक मकसद के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका समय किसी तरह से निकल जाए।

23.03.2026/1710/ए.एस.-एन.जी./2

जिस तरह से पहले से हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ खड़ी हैं, जिसमें कर्मचारियों का डी0ए0 व एरियर शामिल हैं, उसी प्रकार आप एक और लायबिलिटी क्रिएट करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में हज़ारों करोड़ों रुपये की होगी। हजारों करोड़ों रुपये की लायबिलिटी होने के बाद आप तो निकल जाएंगे लेकिन जो आने वाली सरकार आएगी उसके लिए आप भयानक संकट पैदा करके जाएंगे क्योंकि लोग उनसे पैसा मांगेंगे। मेरा दावा है कि यही स्थिति होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सैलरी को काटना तभी संभव है जब आप आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करें। लेकिन आप वह नहीं कर रहे हैं। आपने पैसे के डिफरमैंट का एलान कर दिया है और उसे बजट में भी रख दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और अपने दल की ओर से भी हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कानूनी तौर पर हम नहीं बल्कि बाकी जो कर्मचारी-अधिकारी हैं जिनकी सैलरी आप काटेंगे, क्या वे आपकी बात से सहमत हैं? इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है।...(व्यवधान) डिफरमैंट का मतलब तो यही है कि पैसा अभी नहीं मिलेगा। 6 महीने के लिए आप डिफर करेंगे, फिर 6 महीने के बाद दूसरा चरण आ जाएगा। फिर कहेंगे कि अगले 6 महीने के लिए और डिफर कर देते हैं। उसके बाद आप अगले 6 माह के लिए और डिफर कर देंगे। इस तरह से आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और आप निकल जाएंगे। लेकिन आने वाली सरकार के लिए आप भयानक संकट पैदा करके जाएंगे।

मुख्य मंत्री जी, आप यह भी बताइए कि आपकी पहली बजट की जो कमिटमेंट्स थीं, उनमें से कौन-सी पूरी हुई हैं? उन सिक्स ग्रीन कॉरिडोर का क्या हुआ? हम ढूंढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि वे कहां-से-कहां तक बने। आपका वॉटर सैस कहां गया? ऑबरोय होटल का फैसला दो साल पहले हो गया था, लेकिन अभी तक उसकी बिडिंग भी नहीं हो पाई। इसका कारण क्या है? यह सब प्रदेश जानना चाहता है

23.03.2026/1710/ए.एस.-एन.जी./3

आपने बहुत भाषण दिया कि हमने किया, हमने किया, उसका फैसला आपके समय में हुआ लेकिन केस कब से चल रहा था? इसलिए इस बात को लेकर आप थोड़ा स्पष्ट करें। आपने कहा कि मनरेगा का नाम बदला गया है। नाम ही तो बदला है

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

23.03.2026/1715/ए0एस0/ए0पी0/-01

श्री जय राम ठाकुर जारी.....

वी0बी0-जी0राम जी। वी0बी0-जी0राम जी0 मेरे नाम से थोड़ा नज़दीक है। अगर बोलने में कठिनाई आए तो मेरा ही नाम ले लिया करो। लेकिन आपको मैं बताऊं कि उसमें 95,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। आपने तो न जाने कितनी हमारी योजनाओं को बंद कर दिया है। अगर हम आपसे पूछें कि हिमकेयर योजना का क्या हाल है? आपकी सरकार ने तो हमारे द्वारा चलाई गई हिमकेयर योजना का सत्यनाश कर दिया। अगर हम पूछें कि मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी जी के नाम पर क्यों कर दिया? हमारी सरकार के समय में जनमंच का आयोजन किया जाता था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका नाम बदलकर "सरकार गांव के द्वार" कर दिया। आप देखिए वहां पर क्या हो रहा है। आदमी खड़ा होकर आपसे बोल रहा है कि यह सब माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी उपस्थिति में कहा गया था कि ये मीटर भी ले जाओ और सामने लगा बिजली का खंभा भी ले जाओ। हम तो दिया जलाकर काम चला लेंगे। इस

स्थिति में आज आप प्रदेश को खड़ा कर रहे हैं। आपने प्रदेश में इस तरह हालात पैदा कर दिए हैं कि अब बिजली की जगह लोगों को दिए से काम चलाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने तो हमारी कितनी योजनाएं बंद कर दीं। आपने हमारी सरकार में चलाई गई सहारा योजना को लगभग बंद कर दिया है। आपने शगुन योजना को लगभग बंद कर दिया है। आपकी तो एक योजना का नाम बदला उस पर आप हाहाकार कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और उसमें पूर्व में जितना पैसा मिलता था उससे ज़्यादा पैसा अब दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने कार्यकाल में जो योजनाएं शुरू की थीं, उन्हें हमने चलाया। सैकड़ों करोड़ रुपये से हमने सहारा योजना चलाई और इसके लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए। हिमकेयर योजना के लिए हमने 500 करोड़ रुपये खर्च किए। गृहणी सुविधा योजना के लिए हमने लगभग 170 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया। जनमंच के लिए हमने 52,000 से ज्यादा शिकायतों का समाधान किया। शगुन योजना में हमने लगभग 40 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया। स्वावलंबन योजना में 230 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च किया। इसके अलावा हमने 125 यूनिट

23.03.2026/1715/ए0एस0/ए0पी0/-02

बिजली मुफ्त दी। हमने पुष्पक्रांति की शुरुआत की। हमने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। चाहे कोविड के दौरान हम संकट में रहे, दो वर्षों तक संकट में रहे, लेकिन हमने पैसे का रोना नहीं रोया। आप तो बेचारा बनकर रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोविड के बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में 4,500 किलोमीटर से अधिक सड़क बनाई। जे0जे0एम0 के अंतर्गत 72 साल में मात्र 7 लाख 63 हजार पानी के कनेक्शन थे। लेकिन पांच साल में हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जे0जे0एम0 के अंतर्गत 4,111 करोड़ रुपये खर्च करके 8 लाख 53 हजार कनेक्शन दिए। इसके साथ-साथ आप तो अपनी फ्लैगशिप योजनाओं पर भी 60 करोड़ रुपये के करीब खर्च नहीं कर पाए हैं। यह हकीकत है। अभी भी आप जिन बातों का ज़िक्र कर रहे हैं, वे खोखले वादे हैं और सदन को गुमराह करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें उचित नहीं हैं। प्रदेश को आप कब तक गुमराह करते रहेंगे, यह मैं ज़रूर कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लंबी बातें अब न करते हुए कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को आपने बहुत बड़े संकट में डाल दिया है और आज जो आपने बिल पास किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। अनाथ और विधवा के प्रति हमारा सम्मान है। उनकी मदद का रास्ता निकालना चाहिए लेकिन उनके नाम से सरकार चलाने का रास्ता नहीं निकालना चाहिए। यह कतई उचित नहीं है। आप जो कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। अनाथ बच्चों के नाम पर मदद करिए, जो करना है करिए, लेकिन उनके नाम से पैसा लेकर प्रदेश की सरकार चलाने के लिए जो खर्चे का इंतज़ाम आप कर रहे हैं मैं समझता हूं कि वह कतई उचित नहीं है। आपके पहले, दूसरे और तीसरे बजट की घोषणाएं धरी की धरी पड़ी हैं। अभी आप चौथा बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह राजनीतिक मकसद से नहीं है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

23.03.2026/1720/AT/DC/01

श्री जय राम ठाकुर जारी...

आप 300 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला कर रहे हैं। एक तरफ आपके फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी सब्सिडी मिलती है, चाहे राशन पर हो या बिजली पर उसे बंद करना पड़ेगा और यहां आप 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं और किनको देने की बात कर रहे हैं? उन परिवारों को जो गरीबी रेखा (बी0पी0एल0) के हैं जिनमें लगभग 1 लाख परिवार अति गरीब हैं, उन्हें देने की बात कर रहे हैं और अपने बजट में आपने सब्सिडी को लगभग 50 प्रतिशत से भी कम कर दिया है और बहुत कम कर दिया है। एम0एस0पी0 में आप कह रहे हैं कि हम एम0एस0पी0 देने की घोषणा करते हैं। किस बात के लिए? राजनीतिक मकसद के लिए? हम आपसे एक बात कहते हैं कि आपने बहुत सारी योजनाएं, दर्जनों योजनाएं बिना फंडिंग के लॉन्च कर दी हैं। 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात आपने कही थी वो सारी बातें धरी-की-धरी रह गई हैं। बहुत हो गया अब किसी को भी भरोसा नहीं रह गया है, भाभी जी के सिवाय। इसलिए मेरा आपसे

निवेदन है कि आप इसे छोड़ दीजिए। मेहरबानी करके जब नेतृत्व पर भरोसा समाप्त हो जाता है तो बहुत बड़ा संकट आता है।

अब भाभी जी को आप सदन के अंदर ले आए हैं। भाभी जी हम इस बात के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते थे, कई बार हमें इस बात को लेकर थोड़ा संकोच होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं। अंत में अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की सरकार के ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, वे चिंता का विषय हैं। इन सारी चीजों को लेकर सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई है। इसके ऊपर जवाब देना भी महसूस नहीं करती है। चल रहा है तो चल रहा है, यह ऐसे नहीं चल सकता।

मैं पूछ रहा था कि व्हाइट फ्लावर हॉल का क्या हुआ? बी0बी0एम0बी0 के बारे में आपने बहुत सारी बातें कही थी उसका क्या हुआ? जो पावर प्रोजेक्ट हमने पी0एस0यू0 को दिए थे, आपने कहा था कि हम उन्हें वापस लेंगे। लेकिन साढ़े तीन साल से आप वही बात दोहरा रहे हैं। हम इस गीत को सुन-सुनकर हम सब बहरे हो गए हैं। लेकिन उसके बाद

23.03.2026/1720/AT/DC/02

प्रगति क्या हुई? वही पी0एस0यू0 वहां पर काम कर रहे हैं। वे आपसे 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा के खर्च की मांग कर रहे हैं और वह पैसा आप देने की स्थिति में नहीं हैं। इस बारे में आप स्पष्ट नहीं हैं।

आप रोबोट सर्जरी की बात कर रहे हैं। प्रदेश में स्थिति क्या है? प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हाई-एंड हेल्थ सर्विसेज की तरफ बढ़ना अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजों को लेकर प्रश्न खड़े हैं। जिस रेट पर मशीनों को खरीदा गया है, उस पर बहुत प्रश्न खड़े हुए हैं। Da Vinci रोबोटिक सर्जरी मशीन और लेटेस्ट एक्स0आई0 मशीन लगभग 16.50 करोड़ से 17 करोड़ रुपये के बीच आती है। मुझे मालूम नहीं कि आपने इसे कितने में खरीदा है। ...(व्यवधान) हम आपसे कह रहे हैं आप पारदर्शिता लाए आप उसकी प्रक्रिया तो बताईये अपने उसमें क्या किया? हमें जो जानकारी मिली है उसमें कहा गया कि दो मशीनें खरीदनी थी, अब आप छः खरीदने जा रहे हैं वह क्यों खरीदने जा रहे हैं? छः मशीनें खरीदने की क्या जरूरत है? इसलिए जहां एक्स-रे की मशीन नहीं है,

कहां गए वो आपके आदर्श स्वास्थ्य केंद्र खोले थे, एक जगह में भी गया लेकिन वहां पर एक्स-रे की मशीन भी नहीं है। सारी सुविधाएं तहस-नहस पड़ी हुए हैं। न स्टाफ है, न इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप इन सारी चीजों को लेकर इस प्रकार से बातें कर रहे हैं तो भगवान ही मालिक है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा कि

धूल खुद की थी, मगर आईना बदलता रहा,
हर कमी दूसरों में ढूंढ कर संभालता रहा।
सच से आंख मिलाने की हिम्मत ना हुई उसे,
यूं ही वह बहानों के पीछे पलता रहा।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो यह बजट यहां पर रखा गया है, भले ही यह इतिहास का लंबा बजट हो और इसमें ज्यादा समय लगा हो लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें आंकड़े गलत प्रस्तुत किए गए हैं।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

23.03.2026/1725/केएस/डीसी/1

श्री जय राम ठाकुर जारी ---

इनको छिपाने की कोशिश की गई है। प्रदेश के सामने जो सही आर्थिक स्थिति आनी चाहिए थी, अनावश्यक रूप से उसको छिपाने की कोशिश पता नहीं क्यों की जा रही है और प्रदेश 10 साल पीछे चला गया है। बजट तो आप 4 साल पीछे ले गए हैं लेकिन प्रदेश विकास की दृष्टि से 10 वर्ष पीछे चला गया है जो हम सभी प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही पीड़ा का विषय है। अध्यक्ष महोदय, जो गलत तरीके से आंकड़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, आपकी झूठी घोषणाएं, जो हाउस के अंदर और हाउस के बाहर आप बार-बार असत्य बोलते हैं, इससे सभी प्रदेशवासी शर्मिंदा हैं और अध्यक्ष महोदय, इस बजट का समर्थन करना हमारे लिए किसी भी तरह से संभव नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

23.03.2026/1725/केएस/डीसी/2

मुख्य मंत्री : जय राम जी, अब मैं लास्ट में बोल रहा हूं परंतु जब मैं रिप्लाई दूंगा तो आप भी भाग मत जाना क्योंकि आप भाग जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जितने आंकड़े जय राम जी ने पढ़े, अगर ये अपने समय में वित्त मंत्री होने के नाते उनको पढ़ते तो बहुत अच्छा होता। प्रदेश की स्थिति उस समय से सुधरनी शुरू हो जाती। एक तो इन्होंने लोन का गलत आंकड़ा पढ़ दिया। वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो इन्होंने लोन का आंकड़ा पढ़ा, 76,774 करोड़ रुपये थे उस समय और यह करेक्शन कर लेना। ...(व्यवधान) मैंने तभी कहा कि जिन्होंने इनको आंकड़े लिख कर दिए, मैं सहानुभूतिपूर्व आपके साथ हूं। जो आप आंकड़े पढ़ रहे थे, वित्तीय वर्ष, आर0डी0जी0 आदि-आदि के बारे में, अगर सही मायने में आप अपने समय में उनको पढ़ लेते तो प्रदेश की इतनी बुरी हालत ना होती। हमने तो आपको सही बताया। फाइनेंशियल बजट में लोन की लिमिट तय होती है और उसके हिसाब से उनकी किश्तें भी देनी पड़ती हैं। इनके समय 76,774 करोड़ रुपये वित्त वर्ष में था। इन्होंने आर0डी0जी0 के बारे में कहा कि 30 हजार करोड़ रुपये मिली। आर0डी0जी0 हर महीने आती रही है। दिसम्बर तक तो आर0डी0जी0 इनके समय में आई। लास्ट के तीन महीने की आर0डी0जी0 हमको आई। आर0डी0जी0 का एक फॉर्मुला है। जो सैंटर और स्टेट्स टैक्सिज़ हैं, हर महीने आते हैं। आर0डी0जी0 हमारी 5-6 तारीख़ को हर महीने आती थी। इन्होंने वह भी गलत बताया। एक बात इन्होंने ठीक कही ...(व्यवधान) नहीं, जिसने आपको आंकड़े दिए उस बेचारे ने आपको ठीक से नहीं समझाया। शायद आप जल्दी में होंगे क्योंकि आप काम जल्दी जल्दी करते हैं। तीसरी बात, कि डॉ0 मनमोहन सिंह जी के समय इतनी आर0डी0जी0 आई। वर्ष 1952 से हमें इतनी आर0डी0जी0 आई। लेकिन वर्ष 1952 में बजट का साइज़ क्या था? इन्होंने पूरे आंकड़े दिए। इन्फलेशन्ज़ क्या थे, वर्ष 2000 में क्या था, उन सारी चीजों के इन्होंने आंकड़े दिए। अच्छा किया इन्होंने पढ़ लिया। बाकी बातों का मैं बाद में जवाब दूंगा। कुछेक बातें बहुत ज़रूरी हैं जिनको अभी करेक्ट करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने और 87 हजार करोड़ रुपये आर0डी0जी0 आई। अच्छी बात है। 14वें वित्तायोग ने

40 हजार रुपये दी, 15वें वित्तायोग ने 37 और 11000 की एक्स्ट्रा आर0डी0जी0 दी। बहुत अच्छी बात कही। आर0डी0जी0 क्योंकि मिलती है? आर्टिकल

23.03.2026/1725/केएस/डीसी/3

271(1) में एक प्रावधान है कि आय और व्यय के बीच के अंतर को पाटने के लिए आर0डी0जी0 मिलती है। आपने अपने राज्य को, जब आप मुख्य मंत्री थे उस समय आपने इतना खर्चा किया, जो ये खर्चे का आंकड़ा बता रहे थे, मैं तो मान रहा हूं। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और 1 हजार करोड़ रुपये की बिल्डिंगें तो हमारे सामने आ गईं। मैं तो मान रहा हूं। हमने क्या किया? हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आगे बढ़े। इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात की। फाइनेंशियल इमरजेंसी की इन्होंने बात की। मैं उस बात को भूल जाऊंगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब फाइनेंशियल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। हमारे व्यवस्था परिवर्तन से फाइनेंशियल की उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

23.03.2026/1730/av/hk/1

मुख्य मंत्री------- जारी

हम तो इसी वर्ष आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। आर0डी0जी0 8000 करोड़ रुपये कम होने के बावजूद भी ...(व्यवधान) पिछली बार हमारी आर0डी0जी0 सिर्फ 3200 करोड़ रुपये थी। उसके बावजूद हमने सभी सरकारी कर्मचारियों को 7 प्रतिशत डी0ए0 और 70 वर्ष से ऊपर के पेंशन्र्ज को एरियर देने के साथ-साथ बजट में क्लास-iv का एरियर देने की बात भी की थी।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, विधायकों और अधिकारियों के वेतन में जो 30 प्रतिशत या 20 प्रतिशत की कटौती की गई है उसके बारे में आपने एक बहुत अच्छी बात की है जिसके

लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आपने कहा कि हम सारे विधायक देने को तैयार हैं, इस तरह से आपने स्वीकार किया कि इस सदन के सारे विधायक देने को तैयार हैं और मैं आशा करता हूं कि अब आपमें से कोई कोर्ट नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त आप ब्यूरोक्रेसी का पक्ष ले रहे हैं जबकि ये हमारे पास खुद सहमति दे चुके हैं कि हम देंगे। ...(व्यवधान) आपके पास फोन करके बोल रहे होंगे कि आपने आज यह मुद्दा उठाना। हमने क्लास-i और क्लास-ii का तीन प्रतिशत डैफर किया है और उसके लिए हमने 6 महीने का समय मांगा है। हमने जो आत्मनिर्भरता की बात की है वह इस दिशा में बढ़ते हुए कदम हैं। जिसकी पिछले वर्ष तीन हजार करोड़ रुपये आर0डी0जी0 काट दी और हम अगर व्यवस्था परिवर्तन की ओर कदम न बढ़ाते तो आज प्रदेश आर्थिक संकट में होता। हमारा प्रदेश आर्थिक संकट में नहीं है अपितु हम सुधारात्मक तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।

इसके अतिरिक्त ये लोग बार-बार कह रहे हैं कि सैस लगाया गया। लेकिन हम इस सैस को अपनी विधवा बहनों और अनाथ बच्चों को अच्छा जीवनयापन करने के लिए खर्च करेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे से न तो कोई विधवा बहन मिली और न ही कोई अनाथ बच्चा मिला कि हमारे लिए यह योजना लेकर आइए। यह योजना इसलिए लाई गई है ताकि उनको कानूनी रूप से मजबूत किया जा सकें ताकि वे अपने आत्मसम्मान को किसी के पास गिरवी न रखें। उसमें चाहे उनके रिश्तेदार होते हैं या मामा के पास रहते हैं, उनका आत्मसम्मान सरकार होगी और सरकार ही उनकी माता व पिता होगी।

23.03.2026/1730/av/hk/2

इसीलिए उनको 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' का दर्जा दिया गया है। मैं इसीलिए बीच में बोलने के लिए खड़ा हो रहा था क्योंकि मैं आंकड़े ठीक करना चाह रहा था। हम चाहते हैं कि हमारी विधवा बहनों को भी आत्मसम्मान मिले और यह प्रदेश आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने एक बात बहुत अच्छी कही है। मैंने सोलन और कुल्लू के लिए दो रोबॉटिक मशीन के ऑर्डर करने हैं। मैं इस सदन के अंदर बोल रहा हूं कि अगर जय राम ठाकुर जी यह बोलते हैं कि 28 करोड़ रुपये से कम की आएगी तो जिसको ये बोलेंगे

हम उसको ऑर्डर दे देंगे। वैसे 25 तारीख तक तो उसने कागज देने हैं, अब आप बताइए कि आप कब तक कागज देंगे वरना आपकी सदस्यता भी रद्द की जाए? ...(व्यवधान) हमारे जिला कुल्लू और सोलन में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उन कागजों को फटाफट दीजिए। आपको जो सूचना देते हैं उनसे पूरे तथ्य लेकर यहां बात किया कीजिए वरना आपकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, पेखुबेला के बारे में सी0बी0आई0 ढूंढ रही है और विमल नेगी जी की डैथ को एक वर्ष का समय हो चुका है तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट कब आएगी, आप जो यहां पर बड़ा हल्ला करते थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता से हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, उनमें जिनका भी तीन प्रतिशत डैफर किया गया है उसको 6 महीने के भीतर देने की कोशिश की जाएगी क्योंकि हमारी तब तक थोड़ी परिस्थितियां और ठीक होंगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम भविष्य में उन परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेंगे। ये एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि ओ0पी0एस0 बंद नहीं करेंगे तथा दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि आपको वर्ष 2027 में इतना फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम वर्ष 2027 में भी ओ0पी0एस0 देंगे, वर्ष 2029 में भी हम ही ओ0पी0एस0 देंगे और वर्ष 2032 में जिनको ओ0पी0एस0 नहीं लगी होगी उनको भी वर्ष 2032 में ओ0पी0एस0 लगाएंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब चर्चा में आगे माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया भाग लेंगे।

अगला वक्ता टी सी द्वारा जारी

23.03.2026/1735/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, बजट की इस चर्चा में, मैं अपने आप को शामिल करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दो दिन पहले माननीय सदस्य श्री परमार जी ने यहां जानकारी दी थी कि 28 राज्यों में से 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी यानी एन0डी0ए0 की सरकार है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश से हमारे 4 सांसद लोकसभा के और 2 सांसद राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टीमय है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सैकिण्ड टाइम रिपीट हुई है और हरियाणा में थर्ड टाइम रिपीट हुई है लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में आप अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाए। इससे आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका शासन कैसा था? इसकी असेसमैंट आपको खुद करनी पड़ेगी कि जब हर जगह आपकी सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपको बाहर का रास्ता क्यों दिखाया? ...(व्यवधान) गलती महसूस नहीं की, आप फिर बीच में ही खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार थी जिसके पास लगभग 47,000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 का पैसा था। इसके अलावा इनके पास लगभग 13,000 करोड़ रुपये जी0एस0टी0 कम्पन्सेशन का पैसा था। कुल मिलाकर लगभग 70,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त थे जो इससे पहले किसी भी सरकार के पास नहीं थे। इन्होंने कहा कि पहले आर0डी0जी0 कम थी और यह बाद में बढ़ी है। जैसे मुख्य मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का अर्थ यह है कि इन्कम और खर्च के बीच जो अंतर है, उसे पूरा करने के लिए पैसा दिया जाता है। यदि हम वर्ष 1980-81 की बात करें तो उस समय हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू 212 करोड़ रुपये था और खर्च 232 करोड़ रुपये था। जबकि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 20 करोड़ रुपये था तो क्या उस समय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी हमें 10,000 करोड़ रुपये दे देती? अगर किसी भी फिगर को भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो वह बहुत बड़ी लगती है, जैसे कहा जाता है कि

23.03.2026/1735/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। उदाहरण के तौर पर यदि 100 लोग मिलकर 100 रुपये कमाते हैं तो प्रति व्यक्ति 1 रुपये आता है। लेकिन यदि 10 लोग

मिलकर 100 रुपये कमाते हैं तो प्रति व्यक्ति 10 रुपये आते है। क्या 100 रुपये कमाने वाला बड़ा है या 10 रुपये वाला? इसी तरह से आर0जी0डी0 के बारे में भी प्रदेश में भ्रामक प्रचार करने की कोशिश की जा रही है।

यह सबको पता है कि आर0डी0 किसने कम की? पनगड़िया जी को तो सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है जबकि आर0डी0जी0 काटने वाले दिल्ली की गद्दी पर विराजमान है। हिमाचल प्रदेश की जनता को समझ आ गया है कि आर0डी0जी0 इनकी (विपक्ष) की वजह से कटी है तो उनको यह बताना भी आवश्यक है कि यह बजट किन परिस्थितियों में बना है। यह जानकारी केवल हमें ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता को भी पूरी-की-पूरी होनी चाहिए है।

अध्यक्ष महोदय, आपके पास 70,000 करोड़ रुपये थे, आपने उनका क्या किया? आज आप कहते हैं कि अस्पतालों में पट्टियां नहीं हैं। क्या आपके समय में सब कुछ व्यवस्थित था। आप कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी क्यों शुरू की जा रही है, लेकिन कम से कम अब यह प्रयास तो हो रहा है। इस सरकार के पास संसाधन सीमित हैं फिर भी हैल्थ, रूरल इकॉनमी, एग्रीकल्चर और एजुकेशन सैक्टर में महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। यदि ये सुधार 5 से 8 वर्ष पहले किए गए होते तो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती।

आप कहते हैं कि हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में गए और वहां देखा कि वहां एक्स-रे मशीन नहीं चल रही थी । वर्ष 2022 से पहले वहां मशीनें भी थीं, डॉक्टर भी थे यानी सब कुछ था और मुख्य मंत्री जी आए और ये सब कुछ उठा कर ले गए। ...(व्यवधान) आप स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की बात करते हैं। क्या हमने किसी स्टाफ को निकाला, क्या किसी डॉक्टर को टर्मिनेट किया, क्या किसी नर्स को हटाया गया? ऐसा नहीं हुआ बल्कि हमने इसमें वृद्धि की है।

ये जो समस्याएं हैं, ये आपके छोड़े हुए लेगेसी इश्यूज हैं। आज आदरणीय मुख्य मंत्री जी इस फटी हुई

एन0एस0 द्वारा ... जारी

23-3-2026/1740/एन0एस-वाई0के0-1

श्री भवानी सिंह पठानिया-----जारी

अर्थव्यवस्था को सीलने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में उसको सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि स्टाफ नहीं है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वर्ष 2022 से पहले स्टाफ था? क्या वर्ष 2022 से पहले एक्सरे मशीनें और लिफ्टें चल रही थीं और क्या वर्ष 2022 से पहले अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी होती थी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल नहीं थीं। क्या आपके आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-7 एम0डी0 डॉक्टर्ज थे? ...(व्यवधान) हम शिक्षा के क्षेत्र में टीका-टिप्पणी करते हैं कि आपने एजुकेशन में क्या कर दिया? मेरा विपक्ष के साथियों से यही सवाल है कि आपकी सरकार के समय में एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में क्या बच्चों की बढ़ौतरी हो रही थी? आपकी सरकार के समय में हमारे स्कूल नेशनल रेंकिंग में किस श्रेणी में थे? उस समय हम 21वें स्थान पर थे। क्या पूर्व सरकार ने किसी भी प्रोडक्ट में एम0एस0पी0 दिया था? क्या आपने गेहूं और हल्दी के ऊपर एम0एस0पी0 दिया था? आप अपना एक प्रोडक्ट बताइए जिसके ऊपर आपने एम0एस0पी0 दिया हो। अब आप हमें बातें कर रहे हैं कि आपने एम0एस0पी0 दिया और 60 रुपये व 90 रुपये एम0एस0पी0 कम है। मैं कहना चाहता हूं कि यह आपके शून्य से बेहतर है। मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज आपने सोची भी नहीं और उस चीज को अगर सीमित संसाधनों में हम कर रहे हैं तो आपको समस्या आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2022 के बाद हमारी सरकार आई तो साधारण परिवार से एक व्यक्ति को मुख्य मंत्री बना दिया गया तथा इन्होंने देखा कि ये मुख्य मंत्री धीरे-धीरे पॉपुलर होना शुरू हो गया। वर्ष 2023 में आपदा आई और उस आपदा में हमें केंद्र सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। मुख्य मंत्री जी व पूरे मंत्रिमण्डल ने अपने रिसोर्सिज के साथ निपटने की कोशिश की। जब इन्होंने देखा कि आपदा से निपटते-निपटते मुख्य मंत्री जी की पॉपुलेरिटी बढ़ रही है तो इनके दिमाग में और कोतुहल बढ़ा कि अब क्या करें? फिर इन्होंने जब देखा कि सारे चोर दरवाजे बंद किए जा रहे हैं तो इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि इनको वैसे नहीं रोक सकते तो इनकी सरकार को गिरा दो। इन्होंने सरकार को गिराने के

लिए ऑपरेशन लोटस किया और ऑपरेशन लोटस में क्या हुआ? ये औंधे मुंह गिरे। उसके बाद एक बार दोबारा जनाधार का

23-3-2026/1740/एन0एस-वाई0के0-2

परीक्षण हुआ। उसमें लोगों ने क्या किया की पहले कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जीता कर नहीं भेजा था लेकिन इस बार उन्होंने मुख्य मंत्री की पॉलिसीज या इन्होंने दो वर्षों में जो-जो काम किए थे उस पर अपने मुहर लगा कर दोबारा से हमारे विधायकों की संख्या 40 कर दी। अध्यक्ष महोदय, कहानी अब शुरू होती है। अब ये सरकार भी नहीं गिरा सकते, मुख्य मंत्री जी को हटा नहीं सकते तो कहीं ऐसा न हो जाए कि कांग्रेस वर्ष 2027 में दोबार रिपीट कर जाए। इसलिए विपक्ष ने यह कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश को किसी-न-किसी तरीके से आर्थिक रूप से चौक करने का फैसला लिया। आप चाहे 16वें वित्तायोग की बात कीजिए, केंद्र सरकार एक-एक डिसीजन हिमाचल प्रदेश के विरोध में आज तक लेती आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर मनरेगा की बात करता हूं। विपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि हमने सिर्फ नाम बदला है। इन्होंने मनरेगा का नाम ही नहीं बदला बल्कि इन्होंने मनरेगा की आत्मा को, मनरेगा के शरीर को जला कर नष्ट कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने यह कैसे किया है। हम हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 6,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से अपने गांव के विकास के लिए ड्रॉ करते थे और उस विकास का निर्धारण हमारे गांव में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति करता था। उदाहरण के लिए राधे श्याम यह बोलता था कि मुझे अपनी 15 मीटर की सड़क पक्की करवानी है और वह ग्राम सभा में जाकर अपना प्रस्ताव रखता था। उस प्रस्ताव का सैल्फ कोड बनता था और उसके बाद ब्लॉक से ऑथोराइजेशन मिलती थी तथा उसके काम का एग्जीक्यूशन मनरेगा के थ्रू हो जाता था। अब क्या है कि ग्राम सभा की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब यह है कि अब ग्राम पंचायत डिसाइड नहीं करेगी कि आपके गांव में क्या काम होगा? अब आप बताइए कि इसमें पंचायती राज का क्या रोल रह गया है? ...(व्यवधान) यह दिल्ली से डिक्टेट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए।

Speaker : No disturbance please. ...(Interruption) No disturbance please. (Interruption) जब आपने बोलना है तो इसका जवाब दे देना।

23-3-2026/1740/एन0एस-वाई0के0-3

श्री भवानी सिंह पठानिया : अगर ऐसा नहीं है तो आप एस0ओ0पी0 दिखाएं। ...(व्यवधान) When there is no SOP, my assumption is the right assumption. अगर इनके पास एस0ओ0पी0 है तो यहां पर पेश करें। दिल्ली डिसाइड करेगा कि मेरी रियाली पंचायत के अंदर डंगा लगेगा कि नहीं। यह डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? फिर कहते हैं कि हमने तो सिर्फ इसका नाम चेंज किया है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

23.03.2026/1745/RKS/YK-1

इनका यह भी मानना है कि हम 90:10 स्टेट है। 90:10 स्टेट का मतलब यह है कि जो हम 6000 करोड़ रुपये ड्रॉ कर रहे हैं उसे ड्रॉ करने के लिए फूटी-कौड़ी नहीं देनी पड़ती। 90:10 का मतलब यह है कि 6000 करोड़ रुपये को ड्रॉ करने के लिए 600 करोड़ रुपये लाना पड़ेगा और उसे हम कहां से लेकर आएंगे? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनरेगा ऑटोमेटिकली नाम चेंज होने के बाद खत्म हुई कि नहीं? आप कैसे बोल रहे हैं कि मनरेगा का सिर्फ नाम चेंज हुआ है? ...(व्यवधान) 70:30 नहीं है, अब जीरो है। मनरेगा में अब जीरो है, आप चैक कर लीजिए। यहां मंत्री महोदय बैठे हैं, he will reply to that we don't pay anything for it. उसके बाद जो हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत आबादी गांव में बसती है जो मनरेगा के ऊपर निर्भर है लेकिन मनरेगा को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। आपने RDG भी बंद कर दी लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि सिर्फ RDG ही बंद नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूं कि हमें 6 प्रकार की सेंट्रल ग्रांट्स मिलती थी। Disaster Management, Rural and Local Body, Urban Body, Revenue Deficit, Sector Specific, State Specific. 16th Finance Commission has shutdown three Revenue Deficit Grant बंद कर दी गई जिससे हमारा साला का 6-7 हज़ार करोड़ रुपये बंद हो गया। Sector specific grants जोकि

कभी पावर सेक्टर और कभी वाटर बेस या किसी अन्य सैक्टर के लिए आती थी, Sector Specific Grants in 16th Finance Commission बंद हो गई है। तीसरा, State Specific Grants भी बंद हो गई हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ RDG ही बंद नहीं हुई है। आप देखिए कि फाइन प्रिंट के अंदर 6 में से तीन ग्रांट्स बंद कर दी गई हैं। Financial choking of states which do not cater to their ideology and उसमें हिमाचल प्रदेश एक अग्रणी स्टेट के रूप में उभर कर आता है। दूसरी चीज, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो हमारी USA, New Zealand और Europe के साथ ट्रेड डील हुई उसका सीधा खामियाजा हिमाचल प्रदेश को भुगतना पड़ेगा क्योंकि उसमें Apple के trade tariff और non-trade tariff दोनों के barriers को हटा दिया गया है। आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं है परंतु यह लिखा हुआ है कि both the barriers have been

23.03.2026/1745/RKS/YK-2

removed now. That means Washington Apple 40 रुपये में रोहडू या मेन मंडी में लैंड कर जाएगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बीच में इंटरप्ट न करें। जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लेना।

श्री भवानी सिंह पठानिया : सर, मेरा प्वाइंट यह है कि ये ट्रेड डील का समर्थन करते हैं या विरोध? अगर आप समर्थन करते हैं तो आप हिमाचल का विरोध करते हैं। हमारा जो 5000 करोड़ रुपये का सेब का व्यापार है, यह सिर्फ receipt है। अगर मैं velocity of money को इसमें लेकर चलता हूं तो 2.90 लाख हज़ार करोड़ रुपये का GSDP है। अगर एक रुपया पांच बार टर्न होता है और 5000 करोड़ रुपये सेब व्यापारी या किसान के पास आया तथा उसने उसका टेलीविजन खरीदा, टेलीविजन वाले ने उसकी फीस दी, फीस वाले ने उसको आगे दिया और फिर फाइनली बैंक में चला गया। अगर मैं five transactions लेकर चलता हूं तो 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपये of my GSDP out of the overall 290 is dependent on Apple जोकि केंद्र सरकार की इस नीति ने खतरे में डाल दिया है। तीसरी

चीज यह है कि हमारी जो 1600 करोड़ रुपये की lending limit थी उसमें हमने यह गुनाह किया कि हमारे कर्मचारी बुढ़ापे में अपनी dignified जिंदगी जिएं। इससके लिए जैसे ही मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी पहली कैबिनेट में OPS launch की उसके अगले साल हमें पता चला कि हमारी 1600 करोड़ रुपये की lending limit केंद्र सरकार द्वारा काट दी गई है। यह वह प्रदेश है जो दो बार आपदा से जूझा है। दो बार आपदा से जूझने के बाद हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी यहां पर आए और आकर सात-आठ महीने पहले हमको 1500 करोड़ रुपये आपदा पैकेज दे गए। लेकिन आज तक उस पैकेज की फूटी-कौड़ी नहीं आई। अब आप मुझे बताइए कि हमारे भारत देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अगर अपने मुंह से 1500 करोड़ रुपये की घोषणा करके गए और उसके बावजूद भी वह पैसे नहीं दे रहे हैं तो क्या यह mala fide intention नहीं है? आप यह बोल रहे होंगे कि शायद वे भूल गए होंगे। आप इतना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आप मीडिया में जाते हैं, अगर आपको बोलना है तो आप इन चार प्वाइंट्स पर बोलिए। ये चार प्वाइंट्स हिमाचल के हित की बात हैं।

23.03.2026/1745/RKS/YK-3

ये चार प्वाइंट, वे प्वाइंट हैं अगर आप इनमें बोलेंगे तो आपकी मान, गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन आप इन पर नहीं बोलेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्रीय सरकार जो कर रही है, वह गलत है और आप मौन रहकर उस गलत का समर्थन कर रहे हैं। जब हम प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव लेकर आए थे उस समय आप सदन से वॉकआउट कर गए थे। इस बार जब हमने RDG को लेकर बात की तो आप फिर मौन रहे।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

23.03.2025/1750/बी.एस./ए.जी.-1

श्री भवानी सिंह पठानिया जारी...

जब प्रेशर कुकर नये-नये आये थे तो लोग उनको खरीदते नहीं थे कि ये फट जाते हैं। फिर प्रेस्टीज प्रेशर कुकर आया। उन्होंने बोला कि हमारे इसमें स्पेशल गास्केट है। यह हमारा कुकर नहीं फटेगा। वे एक ऐड लेकर आए और उस ऐड पर उन्होंने एक छोटी सी चीज बोली और उसके बाद ये प्रेस्टीज प्रेशर कुकर हॉकिंस ने मार्केट में बड़ा गेन कर दिया था। वह ये था कि जो बीवी से करें प्यार वह प्रेस्टीज से कैसे करें इनकार। छोटी सी लाइन थी। मैं भी आपको यही बोलना चाहूंगा जो हिमाचल से करें प्यार, वे आर0डी0जी0 से कैसे करें इनकार। आर0डी0जी0 हमारे हक हलाल की कमाई है। रिवेन्यू डिफिसिट मेरा कम ही रहेगा और खर्च मेरा ज्यादा ही रहेगा। लेकिन अगर इसके बीच में जो एक हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वेश्चन दिया था, अगर केंद्र सरकार उसको बंद कर रही है और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो इतना आभास तो आपको भी हो गया होगा कि वर्ष 2027 में कौन आएगा या कौन नहीं आएगा? अब आपने अपने ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा लिया है। इसके बाद सर, अब मैं बजट पर आता हूं। ...(Interruption)

Speaker: He is the first speaker after the Leader of the Opposition.

श्री भवानी सिंह पठानिया : सर, ये सारी बातें बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मीडिया में इनके वक्ता बोल रहे हैं कि बजट कैसा है, नीरस है। मैं यह बताना चाहता हूं कि बजट जैसा भी है, जो भी है, ठीक है। बजट सुनने के बाद इनके होश थोड़े फाक्ता हो गये हैं। कारण यह है कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी-न-किसी तरीके से हम आर्थिक रूप से क्रिप्ल कर दें जिससे हमारी बेइज्जती जो जाए और बजट न बना पाएं। लेकिन जो बजट मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इसमें जो हमारी तीन मेंन प्रायोरिटी थीं, उन प्रायोरिटीज के ऊपर पूरा फोकस किया गया है और ये कैसे किया गया हैं, मैं आपको बताता हूं। इसी वजह से अब इनको समस्या यह हो गई है कि सिर्फ एक चीज इनके पास बची कि बजट का साइज 3,500 करोड़ रुपये कम हो गया। वह तो होना ही था। आप हमको आर0डी0जी0 के बारे में एक महीना पहले बोलोगे हैं कि यह पैसा हम आपको नहीं देने वाले, हम उसका प्रावधान कैसे कर सकते हैं। इसलिए बजट का साइज कम

23.03.2025/1750/बी.एस./ए.जी.-2

होना शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पैसा हमारे पास है, उसका उपयोग कैसे करें? अगर वह हमने ढंग से कर लिया तो हम बता देंगे कि कम पैसे में भी कैसे अधिक कार्य किया जा सकता है। यही इस बजट में दिखाने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, पहले पार्ट में मैं इस बजट के यह बोलना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख 90 हजार है। प्रति व्यक्ति आय ही एक ऐसा मिट्रिक है जिससे पता चलता है कि prosperity of a State or prosperity of a country कितना है। हम चाहे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं लेकिन हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय लगभग 101वें स्थान पर है, जोकि किसी भी एंगल से यह नहीं बताता कि हमारी एक पावरफुल इकोनॉमी हैं। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2 लाख 90 हजार है। अगर मुझे हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली बनाना है तो मुझे प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना होगा। आज से 3 साल पहले जब यह एनालिसिस हुआ, उसमें यह निकला कि हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सोलन का है और यह लगभग 6 लाख के आसपास है। दूसरे नंबर पर शिमला, तीसरे नंबर पर किन्नौर, और चौथे नंबर पर वह बेल्ट आती है जहां इंडस्ट्री है या जहां पर सेब है। हमारे तीन या चार सबसे गरीब जिले हैं, जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। उसमें सबसे पहले कांगड़ा, फिर चंबा, फिर ऊना, और फिर हमीरपुर आता है। ये चार जिले ऐसे हैं जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2 लाख 90 हजार है और कांगड़ा की लगभग 1 लाख 30—40 हजार पर है, तो मुझे हिमाचल की अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, मुझे फोकस करना पड़ेगा कांगड़ा, ऊना, चंबा और हमीरपुर पर और अगर आप देखें कि यह सफर जो उस समय शुरू हुआ उसकी झलक इस बजट में दिखती है। यदि हमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है तो हमने सबसे पहले सैक्टर आइडेंटिफाई किये हैं। हमने आइडेंटिफाई किया टूरिज्म, पावर और रुरल इकोनामी। ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कीं। और कांगड़ा चम्बा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। इसके पीछे क्या कारण था? कारण यह था कि अगर टूरिज्म प्रोजेक्ट्स कांगड़ा में आते हैं और वहां की प्रति व्यक्ति

आय बढ़ती है, तो हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी।

23.03.2025/1750/बी.एस./ए.जी.-3

इसके बाद अगर आप देखें, तो अर्थव्यवस्था में दूसरी बड़ी चीज सबसे पहले पशुपालन हैं पशुपालन के अंदर जो सबसे बड़ा प्लांट बन रहा है, वह डंगवार में बन रहा है यह लगभग 150 लाख लीटर प्रति दिन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी वाला मिल्क चिलिंग प्लांट बन रहा है। इसके बाद आपने एम0एस0पी0 डिक्लेयर कर दिया। यह आपने, गाय और भैंस के दूध के ऊपर दिया है। इसके बाद आपने उन चीजों पर एम0एस0पी0 उन-उन चीजों के ऊपर दिया जहां हमारे निचले क्षेत्रों में एक स्कोप था ताकि वहां पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके। आपने मक्की, गेहूं

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

22.03.2026/1755/DT/AG-1

श्री भवानी सिंह पठानिया जारी...

के ऊपर एम0एस0पी दिया गया और पिछले साल हल्दी के ऊपर भी एम0एस0पी0 दिया गया और इस साल सरकार ने अदरक के ऊपर भी MSP डिक्लेयर कर दिया है। अब इससे प्रतिव्यक्ति आय जो बढ़ने की संभावना है वह उन क्षेत्रों में है जो आज तक शायद नेग्लेक्टेड थे और आज तक शायद जो भी हमारी पॉलिसीज़ उनके लिए नहीं बन रही थीं। वो पॉलिसीज़ एग्रीकल्चर और हमारे कुछ अन्य क्षेत्रों को एक्सक्लूड करके बन रही थीं। इस बजट ने उन सभी चीज़ों को नलिफाई करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्य मंत्री के द्वारा जो क्षेत्र बताए गये हैं वे पर्यटन और ग्रामीण इकोनॉमी के क्षेत्र हैं। हमारे लीडर ऑफ अपोज़िशन यहाँ हैं नहीं, उन्होंने बोला कि यहां पर मैंने उन्नतीस बजट on the trot देखे हैं और उनमें से पाँच मैंने भी प्रस्तुत किए हैं। मेरा सवाल सिर्फ यही होगा कि उन उन्नतीस में से क्या एग्रीकल्चर या किसानों के ऊपर इतना

फोकस दिया गया उसे पहले कभी देख? अगर उन्होंने नहीं देखा तो यह एक ऐतिहासिक बजट है। जिस बजट को नेता प्रतिपक्ष एक निरस बजट बोल रहे हैं उसका कारण यह है कि जो भाजपा के मेन समर्थक है जो धनवान व्यक्ति हैं, जो बड़े-बड़े बिजनेमेन हैं, उनके लिए शायद इस बाजट में कुछ नहीं है। लेकिन इस बजट के अंदर वो सारे के सारे वर्ग शामिल हैं—गरीब, किसान, छात्र, बागवान—उन सबके लिए जो-जो होना चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा है।

अब आप देखिए रूरल इकोनॉमी कैसे गैल्वनाइज होगी—गाय के दूध की खरीद का मुल्य 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये कर दिया है, भैंस के दूध का खरीद मुल्य 61 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही 6 रुपये की स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी भी है, जिसका मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास भैंस है तो उसे लगभग उसका रेट 77 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा।

तीसरी चीज़, अगर आप देखें तो इसमें मुर्गी पालन के लिए भी स्कीम है। फिशरीज के क्षेत्र में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आज तक कभी किसी ने पहले कुछ किया होगा। पहली बार फिशरीज में इतना कुछ आया है। मेरी अपनी कॉन्स्टिटट्यूएंसी में भी बात हो रही

22.03.2026/1755/DT/AG-2

थी—एक किश्ती लगभग एक लाख रुपये की आती है, उस पर 70 प्रतिशत अनुदान सरकार के द्वारा दिया गया है, ये बहुत बड़ा अनुदान है और इससे बहुत सारे हमारे मछवारे थे या जो मत्स्य पालन का कार्य करते थे और जो यह काम छोड़ चुके थे, क्योंकि उनके किस्ती बदलने के लिए पैसा नहीं था। इसके द्वारा दोबारा आर्थिक रूप से खड़े हो सकते हैं।

गिलनेट कास्ट नेट के ऊपर सरकार के द्वारा 90 प्रतिशत सब्सिडी देने की बात कही गई है। पहले जो स्कीम थी उसमें 50 मैट्रिक टन का कोल्ड स्टोर लगाना पड़ता था, जो हिमाचल के लिए उपयुक्त नहीं था। इस बार 5 मैट्रिक टन के 20 कोल्ड स्टोर्स पर 70 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है। जो मछली मछवारों के द्वारा पकडी जाती है उसको सोसाइटी तक ले जाने के लिए कोल्ड बॉक्सेज़ दिए जा रहे हैं, 20 रेफ्रिजिरेटेड वैन पर

सब्सिडी दी गई है। सबसे बड़ी बात—पहले मछुआरों से 15 प्रतिशत रॉयल्टी ली जाती थी, यह 15 प्रतिशत मछुआरे की जेब से जाता था क्योंकि उसको अपना पैसा रॉयल्टी कटने के बाद मिलता था। अब उस रॉयल्टी को घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है, जो बहुत बड़ा निर्णय है। इसके लिए मैं प्रदेश के सभी फिशरमेन फोल्क को बधाई देता हूं और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी लोगों के फोन आए हैं क्योंकि मुर्गी पालन में मुख्य मंत्री द्वारा बहुत कि यह एक बहुत बड़ा कदम है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मतस्य पालन में भी मुख्य मंत्री जी द्वारा बहुत बड़ा कदम उठाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि अर्थ व्यवस्था कैसे बदलेगी। मैं अब हल्दी पर आता हूं अगर मैं इसे शिवा के साथ मर्ज करूं तो शिवा में 262 रुपये का एक प्रोजैक्ट डाला गया है इसमें लगभग 10000 हैक्टयर भूमि को और एड किया जा रहा है, प्रोजैक्टस शिवा प यदि ढंग से काम किया जाए तो यह किसान व बागवानों की जिंदगी बदल लेता है। इसमें अगर हम मल्टी क्रोपिंग कर दें तो इस पर मैं छोटी से कैलक्यूलेशन देना चाहूंगा ।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

23.03.2026/1800/ए.एस.-एन.जी./1

श्री भवानी सिंह पठानिया..... जारी

एक कनाल जमीन के अंदर मैं हल्दी लगाता हूं तो उसमें 80 किलोग्राम बीज लगता है। आज बीज का रेट लगभग 90 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस प्रकार से मेरा बीज का खर्चा एक कनाल के ऊपर लगभग 8000 रुपये के आसपास आता है। अगर मेरी अपनी गाय नहीं है तो गोबर का जो खर्चा आएगा, वह लगभग 2000 रुपये प्रति कनाल होगा। आमतौर पर व्यक्ति खुद ही काम करता है लेकिन अगर उसने लेबर भी लगाई तो लगभग 2000 रुपये लेबर का खर्चा आएगा। गुड़ाई, लगाने, काटने और बाकी सभी कामों को मिलाकर

लगभग 12000 रुपये प्रति कनाल खर्च आता है। एक कनाल में लगभग 450 गज के आसपास भूमि होती है, जिसमें 12000 रुपये का खर्चा आता है। इसमें जो प्रोडक्शन है, production can go as high as 15 times but for calculation sake I will only take it to 8 times. आपने 80 किलोग्राम बीज लगाया और उससे लगभग 640 किलोग्राम हल्दी तैयार होती है। अगर मैं 640 किलोग्राम को 150 रुपये से गुणा करता हूं तो लगभग 1,00,000 रुपये एक किसान को बचता है। एक कनाल में किसान का खर्चा 12000 रुपये है और आमदनी एक लाख रुपये है। अगले साल के लिए वह अपना बीज भी रख लेगा, इसलिए अगले साल उसका बीज का खर्चा लगभग शून्य हो जाता है। अगले साल से किसान को लगभग 90,000 से 95,000 रुपये प्रति कनाल नेट इनकम शुरू हो जाती है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी फसल एक कनाल में इससे ज्यादा रेवेन्यू नहीं दे सकती। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। आप अगले साल के अंत तक देखिएगा कि लोगों की जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। विपक्ष के लोग जो आंकड़े दे रहे हैं कि 40 या 41 लोगों से खरीदी तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल ही इस योजना की घोषणा की गई थी और ज्यादा लोगों ने हल्दी को नहीं लगाया था। कोई भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। आज सिर्फ़ फतेहपुर के अंदर लगभग ढ़ाई हजार किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं।

23.03.2026/1800/ए.एस.-एन.जी./2

इस साल हम कम-से-कम 400 क्विंटल हल्दी बेचेंगे और अगले साल हम कम-से-कम 5000 क्विंटल का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको दिखाएंगे क्योंकि यही वह चीज़ है जो रूरल इकॉनोमी को मजबूत कर सकती है और गांवों से पलायन को रोक सकती है। प्रोजेक्ट शिवा के अंदर हॉर्टिकल्चर, मल्टी-क्रॉपिंग के साथ हल्दी और उसके साथ-साथ मत्सय पालन, कुक्कुट पालन और बाकी कई काम भी आते हैं। अब मैं रूरल इकॉनोमी के बाद एजुकेशन की बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा एजुकेशन पर बहुत टीका-टिप्पणियां हो रही हैं कि एजुकेशन में यह क्यों और वह क्यों। मैं सिर्फ़ एक सवाल पूछूंगा कि वर्ष 2022 से पांच साल पहले आपने क्या किया? क्या हर सरकारी स्कूल वेल्हम या दून स्कूल था? क्या वहां पर शिक्षकों की भरमार थी? अभी माननीय शिक्षा मंत्री, श्री रोहित ठाकुर जी ने 12000 शिक्षकों की भर्ती की है। विपक्ष के समय में हम नेशनल सर्वे में 21वें नंबर पर चले गए थे, लेकिन अब हम वापस 5वें नंबर पर आ गए हैं। समस्या का समाधान तभी होगा जब हम समस्या को समझेंगे। समस्या यह है कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि माता-पिता के दिमाग में यह धारणा है कि सरकारी स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नहीं है। हो सकता है कि लोगों को यह बुरा लगे लेकिन जब मैं शिक्षकों से पूछता हूं कि आपका बच्चा कहां पढ़ता है तो वे कहते हैं कि वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। वह शिक्षक जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका उपयोग वह स्वयं नहीं कर रहा है। इसका कोई तो कारण होगा? मुख्य मंत्री जी ने उस कारण को समझने की कोशिश की है और पहला समाधान यह निकला कि शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करना है। हमारे सरकारी स्कूलों में वे सुविधाएं देनी होंगी जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। इसीलिए पहली कड़ी में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 42 राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल विभिन्न प्रकार की शेप्स में तैयार हो रहे हैं। साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोले जा रहे हैं। हर विधान सभा क्षेत्र में 4—5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे।

23.03.2026/1800/ए.एस.-एन.जी./3

इसके अलावा सबसे बड़ा निर्णय यह था, जिसका राजनीतिक इम्पैक्ट गलत हो सकता था लेकिन अब पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि स्कूलों को सी0बी0एस0ई में कन्वर्ट करना। इस पर भ्रामक प्रचार किया गया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड बंद हो जाएगा। हिमाचल बोर्ड बंद होगा तो कैसे होगा, उसके बारे में बताता हूं। हर साल लगभग 50,000

बच्चे हिमाचल बोर्ड में कम एडमिशन ले रहे हैं। आज लगभग 6.5 लाख बच्चे हिमाचल बोर्ड में एनरोल हैं। इस हिसाब से अगले 7 साल में इसकी एनरोलमेंट लगभग शून्य हो सकती है। इस प्रकार से वह तो बंद होना ही है। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि बच्चे खुद कहें कि हमें सरकारी स्कूल में पढ़ना है। इसमें दो चीज़ें बहुत जरूरी हैंः 1. शिक्षा की गुणवत्ता और 2. बोर्ड। सी0बी0एस0ई0 का निर्णय इसलिए लिया गया ताकि बच्चे वापस सरकारी स्कूलों में आएं और इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक कारण भी है। अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वह कोई छोटा-सा प्राइवेट स्कूल क्यों न हो, तो उसकी व बस की फीस कम-से-कम 5000 से 6000 रुपये प्रति महीना होती है। अगर दो बच्चे पढ़ रहे हैं तो 10,000 से 12,000 रुपये प्रति महीना खर्च होता है। लोग यह खर्च इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उनके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कुछ करना है और सरकारी स्कूल वैसी शिक्षा व सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। अगर घर के पास ही सी0बी0एस0ई0 वाला सरकारी स्कूल हो, जहां विश्व-स्तरीय शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो क्या मुझे (***) है... सॉरी, यह शब्द ऑब्जैक्शनेबल है। कृपया इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया है।

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं अलग तरीके से बोल देता हूं कि क्या मुझे मतवाले श्वान ने काटा है कि मैं अपने बच्चों को

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

23.03.2026/1805/ए0एस0/ए0पी0/-01

श्री भवानी सिंह पठानिया जारी .....

प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर साल का एक लाख बीस हज़ार रुपये खर्च करूं? इसके पीछे मुद्दा यही था कि स्कूलों के अंदर एनरोलमेंट बढ़ाना है। इसके दो मुख्य कारण थे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बोर्ड। हमने दोनों बदल दिए और अगले दो साल में आप देखेंगे कि जो भी आपके स्कूल सी0बी0एस0ई0 हुए हैं उनकी संख्या कम-से-कम 50 से 60 प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों की तुलना में बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ हमारे कॉलेजों का यही कारण है कि जब कॉलेज बंद होने की बारी आती है हर व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमारा कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए। मैं यह कह रहा हूं कि आपने एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया? अगर आप विश्लेषण करें, मेरा देहरी कॉलेज है। वजीर राम सिंह डिग्री कॉलेज देहरी वर्ष 1977 में सरकार ने टेकओवर किया था। आज उसमें पंद्रह सौ बच्चे हैं और यह बहुत बड़ा कॉलेज है। पंद्रह सौ बच्चों में विडंबना यह है कि छात्राओं का एनरोलमेंट लगभग 1050 है और छात्रों की संख्या 450 है। जब आप गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि लड़के डिग्री कॉलेज में नहीं जा रहे। जब पचास प्रतिशत आबादी डिग्री कॉलेज में जाना बंद कर देगी तो कॉलेज तो बंद ही होंगे। लड़के डिग्री कॉलेज में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि प्लस टू के बाद वे वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसे एड्रेस करने के लिए आज हमारे बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने पेश किया कि पचास डिग्री कॉलेजों में बी0वोक0 कोर्सेज, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ए0आई0 आदि कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। इससे छात्रों को बजट भी मिलेगा, प्रोफेसर भी मिलेंगे और क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी। ये सब बुनियादी बदलाव हैं और इस बजट में वे सभी बदलाव परिलक्षित हो रहे हैं। इन्हीं बदलावों से विपक्ष को डर लगता है और उसी डर के कारण वे कभी प्रोटेस्ट में बाहर चले जाते हैं, कभी वॉक-आउट कर जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने तो पूरी कोशिश की थी कि इनकी घिघी मोड़ दें। लेकिन वे भूल गए कि जज़्बात को जितना दबाओगे, उतना ही उभरकर आएंगे। जो व्यक्ति वहां बैठा है, वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वह एक जज़्बात है। आप जितना दबाओगे, उतना ही मज़बूत होकर सामने आएगा और आपको वैसा ही जवाब देगा। वर्ष 2027 में भी वे वहीं होंगे और आप भी वहीं होंगे। इसी के साथ स्वास्थ्य की

23.03.2026/1805/ए0एस0/ए0पी0/-02

बात रह गई थी। स्वास्थ्य दो-टियर ढांचा है। पहला हमारे मेडिकल कॉलेज हैं। मेडिकल कॉलेजों में जब भी रोबोटिक सर्जरी होती है, आप कहते हो कि हमारे यहां पट्टी नहीं है। मैं कहता हूं कि पट्टी तो पांच साल पहले भी नहीं थी। लेकिन तब रोबोटिक सर्जरी भी नहीं थी। जो काम हो रहा है वह चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। अब इसमें रोबोटिक सर्जरी और ई0सी0जी0, एक्स-रे मशीनें, कैंसर डिटेक्शन वाली मशीनें, पेट स्कैन आदि शामिल हैं। जब आप अन्य राज्यों में जाएंगे तो वहां ऐसी मशीनें नहीं दिखेंगी। इससे हर हिमाचली को गर्व होना चाहिए। अगर हम पंजाब जाएं और उन्हें बताएं कि हमारे मेडिकल कॉलेजों में पेट स्कैन की मशीनें लगी हैं तो यह हमारे लिए गर्व का विषय है। आप उस पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? जो चीज़ हमारा स्तर बढ़ाती है और हमारे लोगों को सुविधा देती है उसका हमें समर्थन करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेडिकल कॉलेजों में जो बदलाव आ रहे हैं, वे ऐतिहासिक बदलाव हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों का चाहे जितना मज़ाक उड़ाइए, मैंने अपने फतेहपुर में बहुत बदलाव देखा है। पहले वहां चार एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर थे, आज आठ स्पेशलिस्ट हैं। पहले ओ0पी0डी0 250 की होती थी, आज 600 से अधिक है। पहले वह रेफरल हॉस्पिटल था, आज लोग रेफर होकर वहां आ रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से यह बदलाव देखा है। तो मैं आपकी बात कैसे मान लूं कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में काम नहीं हो रहा। इसी के साथ यह बजट सीमित साधनों और संसाधनों में पेश हुआ है। यह उत्कृष्ट है। इसमें किसान, गरीब और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। एक लाख परिवारों का चयन किया गया है। एक लाख परिवारों का मतलब हमारे पांच लाख प्रदेशवासी होते हैं। इन्हें 1500 रुपये, 300 यूनिट बिजली, सस्ता राशन, सब्सिडाइज्ड राशन और जो भी सरकारी योजना होगी, उसका लाभ सबसे पहले मिलेगा। इन एक लाख लोगों को अगले दो सालों में पक्के मकान भी दिए जाएंगे। इसके साथ आशा वर्करों से लेकर सभी का वेतनमान 500-500 रुपये बढ़ाया गया है। सीमित संसाधनों में जो यह बजट दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और इस तरह

का बजट प्रस्तुत कर पाता। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

23.03.2026/1810/AT/DC/01

अध्यक्ष : अब चर्चा में आगे भाग लेंगे माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज हमारी कैबिनेट की बैठक थी और हमने उसमें कुछ सुधार किए। आपकी बात से मेरे ध्यान में आया इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आज से हमने सी0बी0एस0ई0 स्कूल के पूरे सिस्टम को लागू करने के लिए अप्रूवल दे दी है। एजुकेशन में एक और बड़ा सुधार किया गया है अंडरग्रेजुएट क्लासेस में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की हमने आज शुरुआत की है। आने वाले समय में आप इसका परिणाम देखेंगे। अभी हमने मेडिकल एजुकेशन में भी सुधार किया है। लगभग 270 पी0जी0 की सीटें इस वर्ष हम लेने जा रहे हैं। मैं अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठा हुआ था वहां से आज ही हम इसकी अप्रूवल लेकर इसे अपलोड करेंगे। हमारे जितने मेडिकल कॉलेज हैं और जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हैं, उनमें जहां-जहां स्पेशलिस्ट की कमी है उसे भी पूरा किया जाएगा चंबा, नाहन, हमीरपुर और नेर चौक के मेडिकल कॉलेज पहले ठीक से नहीं चल रहे थे, यह सिर्फ ट्रांसफर हो रहे थे तो हम उन्हें भी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं।

यही व्यवस्था परिवर्तन होता है जिसमें नितियों पर विधान सभा के सभा पटल पर चाहे विपक्ष के नेता विचार रखते है या सत्ता पक्ष के उन सभी को ध्यान में रखकर अमली जामा पहनाकर हम आगे बढ़ते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं।

23.03.2026/1810/AT/DC/02

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में भाग लेंगे श्री इन्द्र दत्त लखनपाल।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2026-27 का बजट यहां पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रस्तुत किया। आपने मुझे चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वर्ष 2023 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट इस सदन में पढ़ा था। उससे पहले श्री जय राम ठाकुर जी ने 3 घंटे का बजट पढ़ा था और उससे पहले राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे उन्होंने 3:30 घंटे का बजट पढ़ा था। हमारे जो वर्तमान मुख्य मंत्री हैं, वे मेरे साथ ही यहां बैठते थे। साथ वाली सीट में और वह कहते थे कि यह इतना लंबा भाषण क्यों देते हैं, इतना लंबा बजट पढ़ने की जरूरत क्या है? छोटा सा स्टेट है और इतने सारे पन्ने छाप देते हैं यह क्यों पढ़ते हैं? लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय खुद मुख्य मंत्री बने तो पहला बजट 66 पेज का था। फिर वर्ष 2024-25 में बजट 72 पेज का हो गया। वर्ष 2025-26 में दो पेज और बढ़ गए वह 74 पेज हो गए। और इस बार तो हद ही हो गई वर्ष 2026-27 में यह बजट 108 पेज तक पहुंच गया। यह बजट मेरी समझ से परे है। यह तो कोई (***) और इसे पढ़ने के लिए भी कम-से-कम एक महीना लगेगा ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : रामायण है ये, (***) तो छोटा सा होता है।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : इस बजट में कुछ ठीक भी है ऐसा नहीं कि हम इसकी सिर्फ आलोचना ही करेंगे। इसमें जो अच्छी बातें हैं उनको अच्छा ही कहेंगे। लेकिन भवानी जी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष इस प्रदेश में आपदा आई बरसात से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ी योजनाएं दे दी 7 लाख रुपए घर के लिए देंगे, 5000 रूपुए किराया देंगे। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः (***) There is no such opportunity for (***)

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

23.03.2026/1810/AT/DC/03

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : लेकिन वर्ष 2023 की जो आपदा हुई हैं उनके पैसे अभी तक लोगों को नहीं मिले हैं। घर बनाने के लिए किसी को एक किस्त मिली है, किसी को दो किस्त मिली हैं और किसी को किराया भी नहीं मिला है। और अब बजट में कहा गया है कि

हम बी0पी0एल0 के एक लाख लोगों को सहायता देंगे। यह बड़ी विचित्र बात है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 970 लोग बी0पी0एल0 परिवार में आते हैं। लेकिन जब सरकार ने दोबारा स्क्रूटनाइज किया तो उसमें सिर्फ 119 लोग ही रह गए। आप कहते हैं कि बी0पी0एल0 परिवारों को हम इतना पैसा देंगे, लेकिन देंगे कहां से? बी0पी0एल0 में अब रह कौन गया है? कभी गांव में जाकर देखो तब पता चलेगा कि गरीब कौन है? आपने तो इस बजट में हद कर दी।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

23.03.2026/1815/केएस/डीसी/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जारी ---

मैं इस बजट में पढ़ रहा था। माननीय मुख्य मंत्री ने पहले बजट में कहा था कि मैं विधवा, एकाकी तथा परित्यक्त महिलाओं को भवन बनाने के लिए 3 लाख रुपये दूंगा। साढ़े तीन साल में तो आपने दिए नहीं, फिर बजट में बोल रहे हैं कि हम विधवाओं तथा अपंगों का सम्मान करेंगे। कहां करेंगे, कब करेंगे? साढ़े तीन साल तो हो गए और अब तीन महीने आपके चुनावों में चले जाएंगे। उसके बाद कोई और चुनाव आ जाएंगे। आपका जो यह शिव पुराण है, लगता नहीं है कि आपकी यह योजना धरातल पर उतर पाएगी। कुछेक चीजें बजट में हैं जो करने लायक हैं जैसे कृषि के क्षेत्र में हल्दी की बात है। हल्दी तो लोग पैदा कर देंगे लेकिन उसको खरीदेगा कौन? अभी भवानी सिंह पठानिया जी बोल रहे थे कि मेरे चुनाव क्षेत्र में ढाई हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन कर दी। लेकिन ये ढाई हजार किसान हैं

कहां पर? कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर में तो इतनी लैंड होल्डिंग ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पानी ही नहीं है। मेरे अपने ही विधान सभा क्षेत्र में पानी की लगभग एक दर्जन स्कीमें बंद पड़ी हुईं हैं। ना तो लोगों को और ना सरकार को उनमें इंट्रस्ट है तो फिर ऐसी योजनाएं बनाने का फायदा क्या है।? कम से कम पहले धरातल पर सर्वे तो हो। टूरिज्म हब के बारे में बोल रहे हैं कि हमने कांगड़ा और चम्बा को टूरिज्म हब बना दिया लेकिन आप बताएं कि साढ़े तीन सालों में आपको कांगड़ा या चम्बा से इस क्षेत्र में कितना रेवन्यू आया? हमीरपुर का तो कभी नाम ही नहीं आता कि वहां पर भी टूरिज्म हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सर्वे ही नहीं करते, फील्ड में कोई जाता ही नहीं है। लगभग 10 साल से तो बाबा बालकनाथ में एक रोप-वे लग रही है। बार-बार उसके बारे में बजट में आ जाता है कि इतने करोड़ रुपये रख दिए लेकिन पता नहीं वह पैसा कहां चला जाता है? ऐसी झूठी और बड़ी-बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपने टोल टैक्स एंट्री बढ़ा दी। आपने यह नहीं सोचा कि हमारे बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर और कांगड़ा के सबसे ज्यादा लोग पंजाब में नौकरी करते हैं। हजारों के हिसाब से नौकरी करते हैं और उनका हर हफ्ते या 15 दिन में अपने घरों में आना-जाना होता है। गाड़ियों के उन्होंने पंजाब के नम्बर लिए हैं। उनको तो डबल एंट्री टैक्स पड़ जाएगा लेकिन आपने इस बारे में कोई सोच-विचार नहीं किया। हर जगह आपने जनता को चूसने का काम किया है। सबसे बड़ा काम आपने यह किया कि विधायक निधि को आधा कर दिया। मैं

23.03.2026/1815/केएस/डीसी/2

तो समझता हूं कि सत्ता पक्ष के विधायक भी इसके हक में नहीं होंगे। पिछले वर्ष जब आपदा आई थी, आपने घोषणा की, नोटिफिकेशन की कि 31 मार्च तक विधायक, जिनके घरों को नुकसान हुआ है, जिनके घरों के आगे-पीछे डंगा गिर गया, उनको लगाने के लिए विधायक निधि से पैसा दे सकते हैं। अब मुझे बताएं कि उस नोटिफिकेशन का क्या होगा? 6 महीने तो आपने विधायक निधि नहीं दी। अब आपने उसको भी आधा कर दिया। सरकार यह बताए कि जो आप हमें अप्रैल में पैसा देंगे उससे हम कितने डंगे लगाएंगे? मेरी 52 पंचायतें हैं। लगता है कि मुझे सभी को 10-10 हजार रुपये ही देने पड़ेंगे। 10 हजार में क्या डंगा लगेगा? बड़ी-बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। धरातल पर आम जनता के

लिए काम करने की जरूरत है, उसके बारे में इस बजट में कुछ नज़र नहीं आता। आपने माना है कि राज्य की कमाई 18 हजार करोड़ रुपये है और खर्चा 48 हजार करोड़ रुपये है। फिर ये जो आपने इस शिव पुराण में बड़ी-बड़ी बातें लिखी हुई हैं इनको आप धरातल पर कैसे उतारेंगे? ठीक है, व्यवस्था परिवर्तन और समय के साथ-साथ कई चीजें बजट में अच्छी भी हैं जैसे आपने सी0बी0एस0ई0 की बात की। परंतु पता नहीं अध्यापक कहां से लाएंगे? इनके अनुसार इन्होंने 12 हजार पद भर दिए परंतु पता नहीं वे कहां भरे गए? हमारे हमीरपुर में तो अभी भी कई स्कूल खाली पड़े हुए हैं। 12 हजार अध्यापकों की आप हमें सरकार की तरफ से कोई लिस्ट दे दें कि कहां भरे हैं? मैडिकल हैल्थ, रोबोटिक सर्जरी तथा पैट स्कैन की बात कर रहे हैं

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

23.03.2026/1820/av/hk/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपपाल------- जारी

वहां पर करोड़ों रुपये की मशीन्ज लगाई जाएंगी जबकि आपके पास डॉक्टर्ज और टैक्नीशियन्ज नहीं हैं। उसमें कितना समय लगेगा यह भी किसी को पता नहीं है। हमीरपुर में डायलिसिज होता है जिसके लिए वहां पर रोज़ 30 व्यक्तियों की रजिस्ट्रेशन होती है। जिन लोगों का डायलिसिज होता है वे लोग न चल सकते और न ही खड़े होने व बैठने लायक होते हैं। हमीरपुर कॉलेज में उनके लिए बैठने की जगह नहीं है। वे जब काउंटर पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं तो उनके साथ इतनी बद्तमीजी की जाती है कि वे न तो रो सकते हैं और न ही कुछ बोल सकते हैं। मुख्य मंत्री जी तो खुद जिला हमीरपुर से हैं। आप जब वहां की ही व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे प्रदेश की व्यवस्था कैसे ठीक कर पाएंगे। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में बिझड़ी-डढवाल में एक कम्युनिटी हैल्थ सेंटर हमारी 26 पंचायतों को फीड करता है। पिछले काफी समय से वहां

पर हमारी कम्युनिटी हैल्थ सेंटर की बिल्डिंग नहीं बन रही है। ...(व्यवधान) आप वहां पर डॉक्टर्ज तो भर देंगे लेकिन उन्होंने करना क्या, वहां पर उन्होंने ताश खेलने के लिए थोड़ी न बैठना। वहां उनको इक्वीपमैंट, ऑपरेशन थियेटर और गायनोकोलॉजिस्ट भी चाहिए। वहां पर आप डेंटल से संबंधित बड़ी-बड़ी मशीन्ज लगा देंगे परंतु अगर वहां पर डेंटल डॉक्टर नहीं होगा तो मशीन्ज लगाने से क्या होगा? आपके पास होस्पिटल्ज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वहां पर 8-8 या 10-10 डॉक्टर्ज बिठाने का क्या फायदा? आपके पास एम्बुलेंसिज भी नहीं हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 13-14 पी0एच0सीज0, एक सिविल होस्पिटल और एक सी0एच0सी0 के लिए वहां एक 108 नम्बर एम्बुलेंस है। लेकिन वह भी कभी खराब होती है और कभी मिलती ही नहीं है। सारे सिस्टम को चलाने के लिए हम वहां पर व्यक्तिगत स्तर पर एम्बुलेंसिज प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप वहां पर जो होस्पिटल बना रहे हैं उसमें कम-से-कम एम्बुलेंस तो दीजिए ताकि मरीज समय पर पहुंचाया जा सके। अब बड़सर से अगर किसी मरीज ने टांडा, चण्डीगढ़ या एम्ज बिलासपुर जाना है तो वह बिना एम्बुलेंस के थोड़ी न जाएगा। वहां पर जो एम्बुलेंसिज हैं वे खटारा हैं। उनको चलाने के लिए वहां पर ड्राइवर्ज भी नहीं है, उनको चलाने के लिए इधर-उधर से ड्राइवर का जुगाड़ करना पड़ता है। फिर आप यहां पर कह रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी की मशीन लगा दी

23.03.2026/1820/av/hk/1

या पैट स्कैन की मशीन लगा दी। जब वहां पर उस पैट स्कैन को चलाने वाला ही कोई नहीं होगा तो कोई व्यक्ति वहां उस मशीन को देखने थोड़ी न जाएगा? आपके पास डॉक्टर्ज व स्पेशलिस्ट्स नहीं है। ठीक है, आपने मशीन्ज लगाईं फिर आप रेट की बात भी कर रहे हैं। उनके रेट्स में बड़ी भारी कमियां हैं परंतु उस बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। उसके बारे में हमारे यहां पर बैठे वरिष्ठ नेता बताएंगे।

यह कोई बजट नहीं है अपितु भ्रम और प्रचार का दस्तावेज है कि जनता को भ्रम करके रखो और खूब प्रचार करो ताकि जनता भ्रमित होती रहे। लेकिन प्रदेश की जनता सरकार से बहुत परेशान है। यहां पर अभी बड़े जोर-जोर से कहा जा रहा था कि वर्ष 2027 में भी

हम आएंगे, वर्ष 2029 और वर्ष 2032 में भी आएंगे। शेख चिल्ली के सपने लेना कोई बुरी बात नहीं है परंतु सपने लेते-लेते मुख्य मंत्री जी ने यह पूरा 'शिव पुराण' लिख दिया। एक व्यक्ति ने तारादेवी तक जाना था क्योंकि उस समय दिवाली का सीजन लगा हुआ था। उसने पटाखे और मिठाइयां इत्यादि सामान खरीदा और बस में बैठकर सोचता रहा कि मैं इतने पटाखे अपने लड़के को दूंगा और इतनी फूलझड़ियां अपनी बच्ची को दूंगा। वह इस बात को सोचते-सोचते दिल्ली पहुंच गया जबकि उतरना उसने तारादेवी था। वही हाल इस बजट का है। मुख्य मंत्री जी को इस बजट को पढ़ते-पढ़ते 5 घण्टों में तीन बार नीचे बैठना पड़ा और साथ में 20 गिलास पानी के पिये। मैं तो उस दिन नहीं था परंतु आप लोगों ने यह सब देखा होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ी-बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है।

यहां पर माननीय उप-मुख्य मंत्री बैठे हैं। अब मैं जल शक्ति विभाग की बात करूंगा। मेरी दर्जनों सिंचाई की योजनाएं बंद पड़ी हैं। उनके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं उसके बावजूद भी वे नहीं चल रही हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वे क्यों नहीं चल रही हैं? वहां पर जो पम्प ऑपरेटर्ज, पैरा ऑपरेटर्ज और मल्टी टास्क वर्कर्ज रखने थे उसके लिए इंटरव्यू हो गए परंतु एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई तथा न ही वे भर्तियां हुईं। इसी प्रकार से मैंने एक प्रश्न लगाया था कि हमारे विद्युत विभाग में 180 पोस्ट्स खाली हैं। हाल ही में वहां पर 4-5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

टी सी द्वारा जारी

23.03.2026/1825/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल... जारी

कहने का तात्पर्य यह है कि बिजली विभाग में एल0एम0 नहीं है और न ही ए0एन0एम0 हैं तो ऐसे में कैसे काम चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ट्रांसपोर्ट की भी समस्या है। पिछले बजट में प्लानिंग की बैठक में इलैक्ट्रिकल बसों के 5 रूट दिए गए थे लेकिन अभी तक कोई बस नहीं आई है,

पता नहीं वे कब आएंगी। इस बजट में सी0एन0जी0 के बारे में भी जिक्र किया गया है लेकिन हमारे क्षेत्र में केवल एक-दो स्टेशनों पर ही सी0एन0जी0 की सुविधा उपलब्ध है। बाबा बालकनाथ में एक रोपवे लगाने की बात हर बार बजट में की जाती है लेकिन वह कब लगेगा, यह स्पष्ट नहीं है। जब लगेगा तब आप धन्यवाद करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं दिवांगजनों के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक सर्वे किया और बजट में उस योजना का नाम ही बदल दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से सहारा योजना बंद हुई तब से लोगों को तीन सालों से पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार ने कहा है कि अब दिव्यांगों को को 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी लेकिन पिछले जून से लेकर वर्तमान समय तक उन लोगों को ओल्ड पेंशन और विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। 80 प्रतिशत दिव्यांग लोगों को सूची से बाहर कर दिया गया है। इसका क्या कारण है, क्यों उन्हें बाहर किया गया, क्यों उन पर शर्तें लगाई गईं कि केवल इन-इन लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा? दिव्यांग व्यक्ति चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, बोझा नहीं उठा सकता, दिहाड़ी नहीं लगा सकता, यदि उसे 3,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहे थे तो उसे क्यों बंद किया गया। इस पर भी सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, नशा मुक्त हिमाचल को लेकर बड़ी-बड़ी बैठकें और कार्यक्रम हुए और आगे भी होंगे लेकिन जिस प्रकार से कुछ पुलिस कर्मी इसमें इंवॉल्व पाए गए, यह गंभीर विषय है। यह आज की बात नहीं है, लंबे समय से कुछ पुलिस कर्मियों और होम गार्ड के कर्मचारियों द्वारा नशे का व्यापार चलाया जा रहा है। इस पर माइक्रो लेवल पर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि सभी पुलिस कर्मी ऐसे हैं लेकिन जो इसमें शामिल हैं, उन पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

23.03.2026/1825/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

अध्यक्ष महोदय, मनरेगा को लेकर भी कहा जा रहा है कि इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है लेकिन दुष्प्रचार तो आप लोग कर रहे हैं। मनरेगा का नाम कई बार बदला गया। वर्ष 1961 से लेकर वर्ष 2004 तक और उससे भी पहले महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना

का इतिहास देखा जा सकता है। आज अगर इस योजना का नाम बदला गया तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मनरेगा के अंदर जितनी लीकेज थी उनको खत्म किया गया। एक अकाउंटेबिलिटी के तहत उसमें कानून बनाए गए और अब उसके अनुसार आगे काम होंगे। दुष्प्रचार तो आप कर रहे हैं क्योंकि इससे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं प्रदेश के वनों के संबंध में कहना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में चीड़ों के बहुत घने-घने जंगल थे जो अब जल गए या जला दिए गए और अब सूखे पेड़ों को गिराया जा रहा है। वनों को बचाने के लिए तो इसमें कोई ठोस योजना नहीं है और न ही आपने वन राखों की बात की है।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

23-3-2026/1830/एन0एस-वाई0के0-1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल-----जारी

आपने वनों को बचाने के लिए वन मित्र भरे थे और उनमें भी लड़कियां हैं तथा वे वन काटुओं से जंगलों को कैसे बचाएंगी और आग से भी जंगलों को कैसे बचाएंगी? जहां पर 20 आदमियों की आवश्यकता होगी वहां पर एक लड़की क्या कर सकती है? आपको लोअर लैवल पर मैन पॉवर बढ़ानी पड़ेगी, चाहे बिजली मित्र, वन मित्र, चाहे पशु मित्र हैं जो भी हैं वे पर्याप्त संख्या में होने चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो सके। इस बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया गया है। आप आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन 400 रुपये बढ़ा कर उनको खुश कर देते हैं लेकिन उनके लिए जो लंबे समय से पॉलिसी बनाने की बात की जा रहा है उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। कई स्वास्थ्य संस्थानों में लड़कियां सी0एच0ओ0 लगी हुई हैं और वे इन संस्थानों को चला रही हैं लेकिन उनके बारे में भी सरकार ने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। मेरा मानना है विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के ऊपर फिर से विचार होना चाहिए। आप भले ही हमें सैलरी न दें चाहे दो वर्षों तक सैलरी न दें, हम रह लेंगे लेकिन विकास के छोटे-छोटे कार्य

जैसे कहीं पर महिला मंडल बनना है, सामुदायिक भवन बनना है, श्मशानघाट बनने हैं और छोटे-छोटे रास्ते बनने हैं तो आप कम-से-कम विधायकों के अधिकार मत छीनें। आपने इस बजट बुक में कई तरह की बातें बता दी हैं लेकिन सच्चाई यह है कि इस बजट बुक को पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है जब से आपने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को आधा किया है। सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बात पर हंस रहे हैं। यह सच बात है कि आम जनता तो विधायक को पकड़ती है और वे मुख्य मंत्री जी व मंत्री जी के पास तो कभी-कभी आती है। हम विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से जो छोटे-छोटे काम करते थे वे तो सारे खत्म हो गए। सरकार के पास स्टेट बजट में पैसा नहीं है। सड़कों के रख-रखाव के लिए पैसा नहीं है। जब हम सड़कों के रख-रखाव के बारे में प्रश्न लगाते हैं तो उसका उत्तर कुछ और आता है और धरातल पर बातें कुछ और हैं। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के रख-रखाव के लिए नाबार्ड का जो पैसा बढ़ाया गया है अगर उसको 25 करोड़ रुपये और बढ़ा देते तो क्या फर्क पड़ना था? हमारी कई डी0पी0आर्ज0 पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मेरी 8 से 10 डी0पी0आर्ज0 पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिनमें 8 से 10 करोड़ रुपये और खर्च होने हैं तो उस

23-3-2026/1830/एन0एस-वाई0के0-2

हिसाब से 90 करोड़ रुपये उनको ही चाहिए फिर 25 करोड़ रुपये से क्या होगा? इस पर दोबारा से विचार होना चाहिए और इस राशि को और बढ़ाया जाना चाहिए। हमारी जो डी0पी0आर्ज0 बनी हुई हैं और पिछले 8 वर्षों से डी0पी0आर्ज0 बनी हुई हैं उनके अंदर भी पैसा नहीं है। प्लानिंग की बैठक में पहले हम तीन-तीन योजनाएं देते थे उनको भी काट दिया गया है कि अब एक से ज्यादा योजना नहीं दे सकते। अनुसूचित जाति के लिए हम विधायक प्राथमिकता में बजट मांगते थे और योजनाएं भेजते थे तो आपने उसको भी बंद कर दिया। अनुसूचित जाति के गांव की सबसे ज्यादा सड़कें बननी हैं, पानी की योजनाएं बननी हैं, कोई भवन बनना है तो वे सारे बंद हो गए और उसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार कैसे बोल सकती है कि यह बजट प्रदेश-हित का बजट है? मैंने पहले भी कहा कि यह बजट शिव पुराण की एक महिमा है, इसको पढ़ते रहो और इसमें कुछ नहीं होना है।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद लेकिन मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए असमर्थ हूं।

अध्यक्ष : अब लोक निर्माण मंत्री जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष वर्ष 2026-27 के बजट पर आज इस माननीय सदन में चर्चा हो रही है और विपक्ष के माननीय नेता और सत्ता पक्ष व विपक्ष के साथियों ने अपनी-अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ यहां पर रखा है, प्रदेश के मसलों को यहां पर रखा है और मैं उसी चर्चा को आगे ले जाना चाहता हूं। प्रदेश के अंदर वित्तीय वर्ष 2026-27 को मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। यह बजट प्रदेश के 75 लाख लोगों के लिए, प्रदेश के हर वर्ग के लिए एक मुश्किल घड़ी में और चुनौतीपूर्ण समय में इस बजट को यहां पर रखा गया है। हमने पहले जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा की थी तो उस समय भी यह बात कही थी कि these are unprecedented time and we are passing through very difficult waters. जिस तरीके से आज इंटरनेशनल मीडिया में ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है,

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

23.03.2026/1835/RKS/YK-1

लोक निर्माण मंत्री जारी....

उसी तरीके से हिमाचल की कश्ती भी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। मगर हम हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि हमारा आने वाला समय बेहतर होगा। मैं आज यह बात केवल एक मंत्री या विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक प्रदेश के युवा के रूप में कर रहा हूं क्योंकि हमें प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचना है। यह बजट केवल कांग्रेस पार्टी का बजट नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों का बजट है जिसे विपरीत समय में भी इतना अच्छा पारित किया गया है। हमें इसके बेहतर तरीकों को

देखना है। जो कार्य इस बजट के अंतर्गत होंगे, हमें उन्हें देखना है। आप विपक्ष में रहते हुए इसकी कमियों को उजागर करिए और यह आपका अधिकार है। मगर मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इन टोटेलिटी जो प्रदेश के मुद्दे हैं हमें उन पर नजर बनाकर आगे बढ़ना होगा। हमारे लिए सत्ता, पद, कुर्सी और भाषण की तालियां सब दूसरी बातें हैं। हमें सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश के हित और हिमाचलीयत को देखना है। हम हिमाचलीयत से छिपे नहीं हैं। हम उस हिमाचलीयत से अपने आपको बचा नहीं सकते। That is incumbent upon all of us, हिमाचलीयत का एक गौरवशाली नाम बनाए रखना हम सबका दायित्व है। हिमाचलीयत की असीमता और हर हिमाचली की इज्जत बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है। यह बजट किसी पार्टी का दस्तावेज भर नहीं है। इस बजट के माध्यम से हमको एक पहाड़ी समाज का स्वाभिमान और उनके संघर्ष के जीवित प्रमाण देखने को मिलते हैं। जो कहते हैं कि संसाधन कम हो सकते हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि हमारे इरादे कमजोर नहीं है बेशक इस समय हमारे संसाधन भले ही सीमित क्यों न हो। हम जिस दल से आते हैं, वह दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान की रचना और आज तक हमेशा एक बात पर डटा रहा है कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं है बल्कि जन कल्याण, न्याय, समाज सेवा और भाईचारे को मजबूत करने के लिए हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हमने कभी भी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं की है। हमने सरकार में हमेशा हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के आगे बढ़ने की बात की है। हमारी राजनीति की एक ही परिभाषा

23.03.2026/1835/RKS/YK-2

है और वह यह है कि पहाड़ का हित सबसे पहले है। कांग्रेस की विचारधारा का सार जन कल्याण, न्याय और भाईचारा है। जो हिमाचल के साथ है, वह हमारा सच्चा साथी है। यहां पर भवानी सिंह पठानिया जी ने बिल्कुल सही कहा कि RDG के मसले पर इतिहास याद रखेगा कि कौन व्यक्ति इसके साथ खड़ा रहा और कौन व्यक्ति इसके विरुद्ध। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है और आने वाले समय में इसका भुगतान प्रदेश के लोगों के

माध्यम से उन लोगों को करना पड़ेगा जिन्होंने इसका विरोध किया है। जो वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया है इसका कुल आकार 54,928 करोड़ रुपये रखा गया है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमारे बजट का आकार 58,514 करोड़ रुपये था। यानी हमें लगभग 3,500 करोड़ रुपये से 4,000 करोड़ रुपये का समग्र कट करना पड़ा है। यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है।

(श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए।)

यहां RDG के ऊपर काफी बात हुई है लेकिन मैं इन मसलों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें लिमिटिड रिसोर्सिज में maximum utilization कैसे करना है, उसके ऊपर चिंता करने और अपने विचार रखने की आवश्यकता है। यह फैसला किसी राजनीतिक शौक या प्रबंधन की कमी से नहीं है बल्कि हमारे ऊपर जो वित्तीय पाबंदियां थोपी गई हैं आज हम सब उनका परिणाम भुगत रहे हैं। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार हमें सालाना तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जिसे आज शून्य पर ला दिया गया है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

23.03.2025/1840/बी.एस./ए.जी.-1

लोक निर्माण मंत्री जारी...

फिर भी कांग्रेस की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बजट छोटा होगा। लेकिन हिमाचल का कद हिमाचल की रीढ़ और हिमाचल की सामाजिक प्रतिबद्धता हम कभी भी छोटी नहीं होने देंगे। यह बात में आज पूरी मजबूती से कहना चाहता हूं। किसी वर्ग की कमर नहीं टूटने दी जाएगी। न कर्मचारियों की, न दिहाड़ीदार मजदूरों की, न किसाननों की, न पशुपालकों की, न गरीब परिवारों की न छात्रों की और न ही बुजुर्गों की और यही इस

बजट में दिखाया गया है। हर वर्ग को लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बावजूद भी आगे बढ़ने का प्रयास इस बजट के माध्यम से मुख्य मंत्री जी ने किया है। हमें इस दृष्टि से आने वाले समय में सरकार को और प्रदेश को आगे ले जाने की आवश्यकता है। इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारा बजट छोटा किया। हमने अपना जमीर और बड़ा कर लिया। उन्होंने हमारे खाते में शून्य बढ़ाये। हमने हिमाचल के हिस्से से एक भी शून्य कम नहीं होने दिया। आर्थिक अन्याय बनाम संवैधानिक अधिकार की जो यह लड़ाई आज हिमाचल प्रदेश के अंदर पैदा हो गई है। यह हमारे लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज आदरणीय जय राम ठाकुर जी यहां पर कह रहे थे कि हमने बहुत से बजट देखें हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। वह प्रदेश के पूर्व में मुख्य मंत्री भी रहे हैं। कई बार के मंत्री भी रहे हैं। विधायक भी रहे हैं। मगर मैं यह कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि हिमाचल प्रदेश को कैसे हमने आगे लेकर जाना है? चाहे वह प्रदेश के रिसोर्सेज के साथ है। चाहे वह केंद्र के रिसोर्सेज के साथ जब भी यह चर्चा हिमाचल प्रदेश के विधान सभा में प्रदेश और राज्य और केंद्र के रिसोर्सेज के बारे में होती है न जाने क्यों एक दरार सी यहां पर विधान सभा के अंदर खींच जाती है। क्या यह हिमाचल प्रदेश के भविष्य के बारे में एक अच्छी चीज है। क्या यह दरार जो हर बार हर बजट के ऊपर हर सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के ऊपर हर आर0डी0जी0 के ऊपर हर सी0आर0एफ0 स्कीम के ऊपर 15वें वित्त आयोग के ऊपर डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स के ऊपर जो यह दरार बार-बार इस विधान सभा सत्र के अंदर आती है। यह दरार हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। यह बात मैं एक युवा के नाते आप लोगों से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं। हमको प्रदेश के देश के रिसोर्सेज के बारे में बात करनी है। उनके रिसोर्सेज के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के

23.03.2025/1840/बी.एस./ए.जी.-2

बारे में बात करनी है और उसी से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ सकता है। यह बात मैं केवल बात के लिए नहीं मगर आंकड़ों के साथ बार-बार यह सदन में कहता हूं और आज भी आंकड़ों के साथ यह बात आपके बीच में कर रहा हूं।

हिमाचल प्रदेश कोई साधारण राज्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश कैसे राजनीतिक अस्तित्व में आया। वह कहानी में पहले विधान सभा के सत्र में कह चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश का जो पॉलिटिकल बर्थ हुआ था that was because of the founder of Himachal Pradesh Dr. Yashwant Singh Parmar ji. जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश को बनाया। एक पॉलिटिकल विचारधारा को आगे ले जाने के लिए पंजाब से हिमाचल को काटकर एक अलग राज्य बनाया गया। एक फीजिबल स्टेट न होने के बावजूद भी, इकोनॉमिकली वायबल स्टेट न होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश को बनाया गया और उस पर रंग भरने का कार्य जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने किया। आदरणीय ठाकुर राम लाल जी ने किया, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने किया और आदरणीय धूमल साहब ने किया। आज हमें उसे और ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो सोच है वह हमेशा से संघीय ढांचे वाली रही है। मुझे इस बात का दुःख है कि हर बार मसला और हर बात हमेशा संघीय ढांचे के ऊपर फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता है। यह दुःख की बात है कि हिमाचल प्रदेश देश का एक अभिन्न अंग होने के बावजूद भी बार-बार संघीय ढांचे का जिक्र इस विधान सभा के सत्र में हो रहा है। हमारी विधान सभा के अंदर जो हो रहा है यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। We are all proud to be part of Union of India. मगर फिर भी जब भी कोई पैसा आता है। तो हमेशा हिमाचल के लोगों को यह एहसास दिलवाया जाता है कि यह आपको एक, मैं यह नहीं कहूंगा कि भीख के रूप में, मगर एक किस्म से एक उपहार प्रदेश के लोगों को दिया जा रहा है। यह क्यों नहीं कहा जाता कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का अधिकार है। जो हम बार-बार केंद्र से हिमाचल के लिए लेकर आते हैं। चाहे वह आर0डी0जी0 का मसला है, चाहे वह सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम्स हैं। किसी भी रूप में जो पैसा हिमाचल में लाया जाता है

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

23.03.2026/1845/DT/AG-1

लोक निर्माण मंत्री जारी...

वह हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई सरकार व प्रदेश के मुख्य मंत्री के कर कमलों से उनके सहयोग से सभी मंत्रीगण सभी विधायकगण यानी सभी लोग उसमें मदद करते हैं और प्रदेश में पैसा लाने की बात करते हैं। इसमें यह बात भी मैं कहना चाहूंगा की केंद्र और प्रदेश के बीच खींची विचारधारा की रेखा से संघीय ढांचा नहीं बनता है बल्कि संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण और छोटे कमजोर राज्यों को विशेष जरूरतों के समीकरण से संघीय ढांचा बनता है। जब यह संतुलन टूटता है तो केवल हिमाचल जैसे राज्य ही नहीं बल्कि पूरा संघीय ढांचा कमजोर हो जाता है।

स्पर्श योजना, वैसे यह योजना नहीं है बेसिक्ली जो फंडज का डेवलूशन हो रहा है उसको प्रदेश के बजट से अलग करके स्पर्श में डाला जा रहा है। यह भी आने वाले समय में प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है। आज आप बेसक भूल जाइए हो सकता है कि आने वाले किसी समय में आप लोग सत्ता में हों उस समय आप लोगों को हमारे यह कथन याद आयेंगे कि किस तरह से हर चीज में हर स्पेडिंग में स्टेट को डिवैल्यूवेट करके, स्टेट के संसाधनों को जकड़ कर, आर0बी0आई0 को सारा पैसा दिया जा रहा है। यह प्रदेश के फैडरल स्ट्रक्चर के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। इसके सही रिपरकशन्ज आने वाले समय में सामने आयेंगे कि इससे कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। हम राजनैतिक मतभेद के बावजूद यह मानते हैं कि पूर्व में जो प्रधान मंत्री, हालांकि उससे पहले भी प्रधान मंत्री रहे हैं लेकिन उस समय मैं इतना बड़ा नहीं था, अगर मैं स्वीर्गीय श्री अटल विहारी जी की बात करूं और डॉ0 मनमोहन सिंह जी की बात करूं तो ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा हिमाचल प्रदेश को खुले हाथों से सहयोग दिया है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की बात को रखने में विश्वास रखते हैं। सही का समर्थन और गलत का विरोध करने पर विश्वास रखते हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देने की बात हो, ओद्यौगिक पैकेज देने की बात हो, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योजनाओं को बढ़ावा देने की बात हो- ये कार्य पूर्व में हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र की सरकार के माध्यम से ही हुए हैं। अगर हम डॉ0 मनमोहन सिंह जी की बात करें तो उनके समय में मनरेगा जैसी ऐतिहासिक योजना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तारीकरण, एम्स और अलग-अलग मेडिकल कॉलेजिज हिमाचल प्रदेश को दिए गये। यह सभी चीजें उनके समय में ही हिमाचल प्रदेश को मिली हैं। यह बातें इस

विधान सभा के सत्र में मैं बार-बार करने का प्रयास करता हूं क्योंकि हमें कई ऐसे मसले हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश के हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हितों की

23.03.2026/1845/DT/AG-2

बात करनी पड़ती है क्योंकि यह बात कांग्रेस या भाजपा की नहीं है, यह बात हिमाचल प्रदेश की है। यह प्रदेश के अस्तित्व , प्रदेश के 75 लाख लोगों और हमारे भविष्य की बात है जिसके लिए हमें मुद्दा आधारित राजनीति और हिमाचल प्रदेश के फेक्चुअल प्लांइटस को आगे रखने की आवश्यकता है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने हमेशा सच का साथ दिया है। जहां किसी की सराहना बनती है वहां पर हमनें सराहना भी की है और जहां ताली बजानी है वहां पर ताली भी बजाई है। जहां पर सवाल बनते हैं वहां पर ठोक-बजाकर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस न अंध विरोधी है न अंध भक्ति में विश्वास रखती है।

सभापति महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहूंगा कि डिजास्टर की बात हिमाचल प्रदेश में लगातार की जा रही है। From the meagre resources that we had in the State during the entire disaster prone period in Himachal Pradesh, which unfortunately expanded for three financial years in Himachal Pradesh starting from 2023, 2024 and 2025 लगातार हिमाचल में डिजास्टर आया, हिमाचल में तबाही का मंजर लगभग 10000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मेरे विभाग को मात्र 4000 से 5000 रुपये तक का नुकसान हुआ। अभी बार-बार यहां पर सदस्यों ने बात कही की माननीय प्रधानमंत्री जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

23.03.2026/1850/ए.एस.-एन.जी./1

लोक निर्माण मंत्री..... जारी

जी हिमाचल आए और उन्होंने हिमाचल का हवाई निरीक्षण किया तथा 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी करी। मगर हम यह जानना चाहते हैं और यह आंकड़ों के आधार पर जानना चाहते हैं, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। I want to know whether this Budget

which was announced by the Hon'ble Prime Minister will it come as a relief package or will it be counted as part of the already on going CSS schemes for the state of Himachal Pradesh? क्या इसे घोलकर सी0एस0एस0 (सैंटर स्पोंसर्ड स्कीम्ज़) स्कीम में डालने की कोशिश की जाएगी? यह जवाब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी को देने की आवश्यकता है। वे बार-बार केंद्र की योजनाओं का ज़िक्र करते हैं मगर हिमाचल प्रदेश जानना चाहता है कि यह पैसा हिमाचल प्रदेश को कब मिलेगा? अगर आप कह रहे हैं कि यह पैसा पहले से ही स्कीमों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है तो उसके बारे में नेता प्रतिपक्ष जी और विपक्ष के माननीय सदस्यों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरी ओर जैसा मैंने आपको कहा कि from the meagre resources of the State that were there at the disposal of the Hon'ble Chief Minister, we gave a package of Rs. 4500 crores. 4500 करोड़ रुपये का पैकेज विपरीत परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए दिया गया। जिसका ज़िक्र श्री जगत सिंह नेगी जी और अन्य साथियों ने यहां पर किया कि डिजास्टर-प्रोन फैमिली को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मुश्किल समय में दी गई है। खासकर जो नुकसान हमारा बरसातों में हुआ, उसके साथ-साथ जो आगजनी की घटनाएं हुईं—बंजार के अंदर, रोहड़ू के अंदर, मंडी के अंदर—जो आग की दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें पूरे-के-पूरे गांव जल गए, उनको भी डिजास्टर एक्ट के अंदर लाकर, वहां पर भी 8 लाख रुपये की सहायता देने का कार्य इस सरकार ने किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें इन चीजों पर चिंतन व मंथन करने की आवश्यकता है।

23.03.2026/1850/ए.एस.-एन.जी./2

घोषणाएं टीवी पर अच्छी लगती हैं लेकिन पहाड़ पर घर तब बनता है, जब पैसा सच में खजाने से निकलकर मजदूर की हथेली तक पहुंचता है। हम पैकेज की राजनीति में विश्वास नहीं करते, हम प्रमाण (प्रत्यक्ष) सहायता की मांग कर रहे हैं। क्योंकि हिमाचल को

फोटो-ऑप की आवश्यकता नहीं है बल्कि हिमाचल को वास्तविक मदद की आवश्यकता है। मैं यह गुहार आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से लगाना चाहूंगा कि हिमाचल का हक हिमाचल को समय पर मिलना चाहिए। हिमाचल का अधिकार हिमाचल के लोगों को मिलना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। मैंने लगातार सार्वजनिक रूप से कई मंचों से कहा है और विधान सभा के बाहर भी कहा है कि Himachal's interest are supreme and no compromise will be tolerated with the interest of the State and the people of the State. मेरे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारी सरकार के लिए, हिमाचल प्रदेश के हित सर्वोपरि हैं। हमें जो भी पद मिला है—चाहे वह विधायक का पद हो, मंत्री का पद हो या संगठन का कोई भी दायित्व हो—यह सब जनता के भरोसे की देन है। इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान हमारे लिए सर्वोच्च है। संघीय ढांचे को मजबूत रखना है, छोटे पर्वतीय सीमांत राज्यों की विशेष चुनौतियों को स्वीकारना है और हर नीति के केंद्र में इंसान को रखना है, न कि किसी इवेंट को। इसी सोच से प्रेरित होकर हमने अधिकारियों के बारे में भी एक बात कही थी। मैं उसके बारे में भी इस सदन में कहना चाहूंगा। यह बात मैं केवल एक मंत्री के रूप में नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं हिमाचल प्रदेश के एक आमजन के रूप में कह रहा हूं, लोगों के प्रति कह रहा हूं कि गैर-स्थानीय अफसरों से कहा कि हिमाचल में आकर हिमाचल के सेवक के रूप में कार्य करना है। All the people sitting in the treasury benches or the officers of the State and the elected representatives of the State, we all are public servants. हम सभी जनता के सेवक हैं और हमें उसी सोच के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से हो, हम जनता के सेवक हैं और हमें उसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को उससे बड़ा समझने की कोशिश करेगा, चाहे वह किसी भी पद पर बैठा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह बात मैं हिमाचल प्रदेश के हित में कहना चाहता हूं

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

23.03.2026/1855/ए0एस0/ए0पी0/-01

लोक निर्माण मंत्री जारी .....

यही सोच के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से हो, हम जनता के सेवक हैं और हमें उसी सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करेगा वह चाहे किसी भी पद पर बैठा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। यह बात मैं हिमाचल प्रदेश के हित में कहना चाहता हूं। यह कोई बढ़िया बात नहीं है(विपक्ष के सदस्यों को बोलते हुए), यह हिमाचल प्रदेश के हित की बात है और हिमाचल प्रदेश के हितों की आवाज़ को हम हमेशा निष्पक्षता से उठाते रहेंगे। यह बात मैं आपको माननीय रणधीर जी पूरी मजबूती से कहना चाहता हूं। जहां तक कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है, जहां तक प्रदेश के अंदर आप विकास के मापदंडों को देखने की बात करते हैं। अभी माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने कहा कि हमारा पर-कैपिटा इनकम है एक यह मानदंड है। जिससे प्रदेश के विकास के मापदण्डों को मापा जाता है और दूसरी ओर प्रदेश में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। जिसमें सड़कों का निर्माण हो रहा है, ब्रिजेज़ का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है। That is one of the basic parameters of the development trajectory that is being written in the state. आज प्रदेश में जो आर्थिक विकास कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो रहा है उसके बारे में ज़िक्र करना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि पिछले चार वर्षों में, वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और लोक निर्माण विभाग ने 7,420 करोड़ रुपये का व्यय किया है, जिसमें ब्रिजेज़ और सड़कों का निर्माण प्रदेश के अंदर हुआ है। इस राशि से ग्रामीण सड़कों की, मध्यवर्ती मार्गों की, पुलों की, न्यायिक भवनों की, प्रशासनिक भवनों की, रेस्ट हाउस की और प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम हुआ है। इसी दौरान मैं केंद्रीय परियोजित और केंद्रीय समर्थित योजनाओं के माध्यम से केवल पी0डब्ल्यू0डी0 को पी0एम0जी0एस0वाई0, सी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0 के तहत लगभग 4,580 करोड़ रुपये हम लेकर आए हैं। आपको तालियां बजानी चाहिए, मगर यह मुख्य मंत्री जी के सहयोग से हम प्रदेश के

अंदर लेकर आए हैं। मैं आपको बार-बार यह कहता हूं। आप लोग हंसते रहिए ...(व्यवधान)

Chairman : No interruption please.

23.03.2026/1855/ए0एस0/ए0पी0/-02

लोक निर्माण मंत्री : आप लोग हंसते रहिए, आने वाले समय में आप पर जनता हंसेगी। हम जो कहते हैं, आंकड़ों के ऊपर बात करते हैं। हम जो बात कहते हैं, डी0पी0आर0 के ऊपर बात करते हैं। हम जो बात करते हैं, यहां से प्रोजेक्ट्स बेचकर, डी0पी0आर0 बेचकर, जो पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र से लाने की बात करते हैं, उसी आधार पर हम यह बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

Chairman : Please, don't disturb please.

लोक निर्माण मंत्री : सभापति महोदय, इसलिए हमको कोई इगो नहीं है। ...(व्यवधान)

Chairman : Please, don't disturb please.

लोक निर्माण मंत्री : हमको कोई इगो नहीं है। ...(व्यवधान) हम लगातार हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे और लगातार हिमाचल के लिए सहयोग लाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। ...(व्यवधान)

Chairman : Please, don't disturb please.

लोक निर्माण मंत्री : सभापति महोदय, हमने शपथ ली है। इस विषय की हमने शपथ ली है। हम हिमाचल प्रदेश के लिए लड़ाई प्रदेश के अंदर भी लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की लड़ाई केंद्र में जाकर भी लड़ेंगे और आंकड़ों के साथ लड़ेंगे। यह बात मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं। यह असाधारण नहीं है, यह साधारण बात नहीं है कि जो हमारी उपलब्धी है 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत कार्य हम कर पाए हैं। यह हिमाचल के इंजीनियरों, हमारे कर्मचारियों और हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है कि आज हम इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर तीन साल के कार्यकाल में कर पाए हैं। कई लोग एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में उड़कर विकास-विकास चिल्लाते है, हम रोज पहाड़ो की सड़कों पर धूल खाकर हिमाचल के लिए फाइल भी लाते हैं और उसी सड़क पर जाकर काम भी दिखाते हैं। यह हमारी हिमाचलियत है, यह हमारी राजनीति है।

सभापति : अभी माननीय लोक निर्माण मंत्री के अतिरिक्त सात माननीय सदस्य और है तो अगर माननीय सदन की इजाजत हो तो सदन के समय को बढ़ाया जाए।

23.03.2026/1855/ए0एस0/ए0पी0/-03

अब इस माननीय सदन की कार्यवाही को एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

लोक निर्माण मंत्री : सभापति महोदय, अगर हमारी हिमाचलियत की परिभाषा से आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो होती रहे। मगर हमारी हिमाचलियत हिमाचल के लोगों के लिए धड़कती रहेगी।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

23.03.2026/1900/AT/DC/01

लोक निर्माण मंत्री जारी...

मैं आपको यह कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में पीएमजीएसवाई-III के तहत हमने 3123 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों और 43 पुलों की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश के लिए ली, जिसके लिए 3340 करोड़ रुपये हमने पिछले वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश के अंदर खर्च किए और इस वित्तीय वर्ष में... (व्यवधान) धन्यवाद की बात नहीं है यह हिमाचल का अधिकार है, यह हिमाचल का अधिकार है।

Chairman: Please don't disturb.

लोक निर्माण मंत्री: और इस वित्तीय वर्ष में सभापति महोदय, हम 1563 किलोमीटर सड़कों के लिए पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह होने जा रहा है... (व्यवधान) First time in the recorded history of Himachal Pradesh we are going to construct

2244 kilometre roads in Himachal Pradesh. That is the development trajectory written by the people of Himachal Pradesh. ...(Interruption).

सभापतिः माननीय सदस्य, please don't disturb.

लोक निर्माण मंत्रीः अगर आपके अंदर इतना दम था, तो आप अपने समय में इतना पैसा हिमाचल के लिए क्यों नहीं ला पाए? यह बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके समय में यह सारा पैसा हिमाचल के लिए क्यों नहीं आया यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय हमने... (व्यवधान) बजट सारा रिकॉर्ड पर है। जितना हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाले समय में करना है....(व्यवधान) आप फिकर मत करो। आपके रोड भी बनेंगे... (व्यवधान)

सभापतिः माननीय सदस्य , please don't disturb. जब आपकी बारी आएगी तब आप बोल लेना।

23.03.2026/1900/AT/DC/02

लोक निर्माण मंत्रीः आपके ब्रिज भी बनेंगे, गांव-गांव तक सड़कें भी पहुंचेंगी। उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात मैं पूरी मजबूती से यहां पर कहना चाहता हूं और इसी के साथ हमने... (व्यवधान)

सभापतिः माननीय सदस्य, जब आपकी बारी आएगी तब आप अपनी स्पीच में बोल सकते हैं Please don't disturb. Let him complete.

लोक निर्माण मंत्रीः सभापति महोदय, इन्हीं अनुभवों के साथ हमने हिमाचल प्रदेश के लिए नई रोड ड्रेनेज पॉलिसी तैयार की है जिसमें वैज्ञानिक सर्वे, जल प्रभाव के सटीक आंकड़े, बायो-इंजीनियरिंग और अनिवार्य ड्रेनेज ऑडिट को इस बार नीति का हिस्सा बनाया गया है। ताकि we have to learn from the disaster, we have to learn from the mistakes ,we have to learn from the short falls of our predecessors and incorporate that in the present regime so that the problems that were faced during the previous

Governments are not repeated in the times to come. हमें सीखने की आवश्यकता है। हम इस उम्र में भी सबसे सीखते हैं। हमें कोई ईगो नहीं है। जो कमियां रही हैं उन्हें कैसे बेहतर किया जा सकता है और कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए इस दृष्टि से हम लगातार प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं।

Chairman: Hon'ble Minister, please wind-up.

लोक निर्माण मंत्री: और उसी तरीके से, माननीय सभापति महोदय, हिमाचल में जो हमारे शहर हैं उनके निर्माण कार्य के लिए शहरी विकास विभाग के माध्यम से जो बदलते चेहरे हैं हमारे बड़े शहरों के, चाहे शिमला हो, धर्मशाला हो, हमीरपुर हो या मंडी मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2022-23, वर्ष 2025-26 तक शहरी विकास विभाग के लिए हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रदेश के अंदर किया है वह करीब 3380 करोड़ रुपये है। जिसमें स्मार्ट सिटी का निर्माण प्रदेश के अंदर हुआ है अमृत योजनाएं, पेयजल योजनाएं और सीवरेज योजनाएं भी शामिल हैं। प्रदेश के अंदर विश्व बैंक के माध्यम से एसजेपीएनएल में लगातार कार्य हो रहा है अभी मैं सुन रहा था कि हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय श्री सुरेश

23.03.2026/1900/AT/DC/03

भारद्वाज जी कह रहे थे कि यह स्कीम जय राम जी और पूर्व सरकार की वजह से शिमला शहर के लिए आई है I want to set the record straight that the Shimla Water Supply Scheme was conceived by the previous Congress Government under Raja Virbadhar Singh Ji and Smt. Vidya Stokes as the IPH Minister. उस समय इसको कंसीव किया गया था। उस समय यह सोच रखी गई थी कि शिमला का जो पेयजल संकट है उसे कम से कम अगले 30 साल तक खत्म करना है तो चाहे पानी सतलुज से उठाया जाए या पब्बर से। अंततः यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक को भेजा गया और वहां से करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से इसे स्वीकृति मिली और मैं इस माननीय सदन को बधाई देना चाहता हूं कि यह पानी अब सतलुज से शिमला तक

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

23.03.2026/1905/केएस/डीसी/1

लोक निर्माण मंत्री जारी ---

पहुंच गया है और आने वाले सैकिण्ड फेज़ में इसका डिस्ट्रीब्यूश्न पूरे शिमला शहर के अंदर एक हाई प्रैशराइज़ वाटर स्कीम के तहत करवाया जाएगा। यह हमारी सरकार की सोच है जिसके माध्यम से ये कार्य हिमाचल के अंदर हुए। हमारे शहर कंकरीट के जंगल नहीं हैं। ये पहाड़ की सांसों के साथ चलते हुए कस्बे हैं। यहां विकास की परिभाषा मॉल की ऊंचाई से नहीं, गली की सफाई, पीने के पानी और बच्चे के स्कूल तक जाती सड़क से तय की जाती है। कर्मचारियों, दिहाड़ीदारों और मानदेय संकट से लोगों को निकालने में हम विश्वास रखते हैं।

सभापति महोदय, ज्यादा लम्बी बात ना कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी इस वित्तीय परिस्थिति के अंदर कार्य किए गए हैं और जैसा यहां पर आदरणीय भवानी सिंह पठानिया जी ने पहले ही विस्तार से बताया है कि प्रदेश का हर तबका उसमें चाहे मछुआरे हैं, पोल्ट्री सेक्टर या डेयरी सेक्टर है, सभी के अंदर रिफोर्म्ज़ लाए गए हैं। प्रदेश के हर वर्ग और जिला कांगड़ा, हमीरपुर या ऊना आदि हर क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करने के लिए, समाज के जो सबसे नीचे के तबके हैं, उनको मदद करने के लिए यह बजट एक प्रेरणादायक बजट है और आने वाले समय में हमें इसे और मज़बूती से आगे ले जाने की आवश्यकता है और त्याग करने की भी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, हमने तय किया है कि :-

बोझ मज़दूर के सिर से नहीं, मंत्री की कुर्सी से कम होगा,
अगर पहाड़ पर चढ़ना है तो पहले बैग हलका करना पड़ेगा।
कमज़ोर के कंधे पर बोझ बढ़ाकर हम आगे नहीं बढ़ना चाहते,
हम प्रदेश के हर वर्ग को आगे ले जाना चाहते हैं।

But not at the cost of the lowest segment of the society. आज उनको हर तरीके से सुरक्षित रखा गया है। उनके ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। आज जो बिल पास किया गया, जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर बहुत सी बातें कीं, मैं समझता हूं

23.03.2026/1905/केएस/डीसी/2

that is the noble cause for the destitute women of the State, for the orphan youth of the State जिनको कोई सुनने वाला नहीं है। जिनके दुख-दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। हर चीज़ में पैसे का एंगल देखने की आवश्यकता नहीं होती। We have to see the emotional angle also. प्रदेश केवल संसाधनों से नहीं चलता। मैं मानता हूं कि संसाधन बहुत महत्वपूर्ण हैं मगर उसके साथ-साथ आपकी भावनाएं और आपकी समाज के प्रति, दुर्गम क्षेत्र के लोगों के प्रति, प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के लोगों के प्रति तथा ऐसे लोगों के प्रति आपकी क्या सोच है जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है, यह जानना भी जरूरी है। अगर उनके लिए 2 या 5 रुपये का सैस लग भी गया तो मैं समझता हूं कि आपको उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, हमें निश्चित तौर पर आने वाले समय में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है और उसके लिए कड़े कदम भी उठाने हैं। उसके लिए प्रदेश में फिज़ूलखर्ची को कम करना होगा। सरकार निश्चित तौर पर इस दिशा में कदम उठा भी रही है। मैं समझता हूं कि हर चीज़ में अगर हम राजनीति करेंगे, विरोध करेंगे और हर चीज़ में यही देखेंगे कि कैसे हम सरकार को या अपने राजनीतिक विरोधी को गिरा सकते हैं तो यह प्रदेश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आप सब लोग इस सदन के अंदर समाज के एक पढ़े-लिखे तबके से आते हैं। आप सब जानते हैं कि हम प्रदेश के इस वित्तीय संकट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर अपने विचार रख सकते हैं that should be the idea of this House. उस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए जहां पर सभी अपने विचार दें, सभी सकारात्मक योजनाओं के बारे में यहां बात रखे। अगर कोई बजट में कमी भी रह गई है तो उसके बारे में भी जानकारी प्रदान की जाए ताकि आने वाले समय में हम उसको और बेहतर तरीके से आगे ले जाने का प्रयास करें।

अंत में सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा दिल बहुत खट्टा होता है, हमारे दिल में बहुत दर्द होता है जब हर मसले पर राजनीति होती है। हर मसले के ऊपर एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश होती है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी --

23.03.2026/1910/av/hk/1

लोक निर्माण मंत्री------- जारी

आखिर वह दिन आना चाहिए जब हम द्विदलीय रूप से इस प्रदेश के बारे में सोचें। हमारे प्रदेश के अंदर जितने रिसोर्सिज हैं और जितने हम केंद्र सरकार से लेकर आ रहे हैं; ये सारे न हमारे हैं और न ही आपके हैं। ये हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के हैं। इसलिए हर चीज पर राजनीति करना और हर चीज पर यह कहना कि यह आपको केंद्र सरकार द्वारा दी गई सौगात है; इस प्रकार की बातें हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिल को ठेस पहुंचाने वाली होती हैं। यह बात मैं एक राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं कह रहा हूं अपितु हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के एक सदस्य के रूप में कह रहा हूं कि बार-बार इस प्रकार की बात करके प्रदेश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सभी साथियों को एक बहुत लम्बा सफर, खासकर युवाओं को मिलकर तय करना है। हिमाचल के मसले एक ही रात में खत्म होने वाले नहीं है। यहां पर बहुत-सी सरकारें आई हैं और मसलें व मुश्किलें भी रही हैं जिसके लिए राजनीतिक व विचारधारक लड़ाइयां भी लड़ी गईं। परंतु अंत में हमें यह याद रखना है कि हमें हिमाचल प्रदेश के हितों की जीत करवानी है और उस सोच के साथ हमें निरंतर आगे चलना है।

यह बजट हिमाचल प्रदेश की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पेश किया गया है। इसमें हमारे किसी भी तबके को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देते हुए अपने भाषण पर विराम लगाता हूं। जय हिन्द, जय हिमाचल।

23.03.2026/1910/av/hk/2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी भाग लेंगे।

श्री सुरेन्द्र शौरी : सभापति महोदय, इस माननीय सदन में दिनांक 21 मार्च, 2026 को बजट अनुमान प्रस्तुत किए गए। उस पर चर्चा चल रही है और मैं भी उसके संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं इस बजट का केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से विरोध नहीं कर रहा हूं अपितु हिमाचल प्रदेश के आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर कर रहा हूं। मुख्य मंत्री जी ने यहां पर जो बजट रखा तो मैंने उसके साथ-साथ इनके द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पेश किए गए बजट का अध्ययन भी किया। मैं वर्ष 2023, 2024, 2025 और वर्ष 2026 के बजट के आधार पर यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार घोषणाओं की सरकार है। यह सरकार घोषणाओं का क्रियान्वयन करने में पूरी तरह से विफल रही है। इसको पढ़ने के लिए मुख्य मंत्री जी ने 4.09 घण्टे लिए। इस बजट को पढ़ने के लिए समय चाहिए परंतु इसमें काम ढूंढने के लिए दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी।

सभापति महोदय, अगर हम पिछले चार बजट्स का ट्रैंड देखें तो हर वर्ष नई घोषणाएं होती रही हैं। दूसरे-तीसरे बजट में पुरानी घोषणाएं फिर से दोहराई गईं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बजट में घोषणाओं की चमक में सच्चाई का अंधेरा साफ नज़र आ रहा है। मैं पिछले कल इस बजट का अध्ययन कर रहा था और यह बजट पूरे 108 पेजिज का है। ...(व्यवधान) बजट के 108 पेजिज हैं बाकी सारांश है। उसको पढ़ते हुए मुझे ध्यान आया क्योंकि सभापति महोदय, आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। हम जो माला जपते हैं उसमें भी 108 मनके होते हैं।

टी सी द्वारा जारी

23.03.2026/1915/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री सुरेन्द्र शौरी .. जारी

जब हम माला के 108 मनके जपते हैं तो मन को शांति मिलती है, लेकिन इस बजट के 108 पेज पढ़ने से निराशा ही मिल रही है। माला के 108 मनके जपने से फल मिलता है लेकिन यहां 108 पन्ने पलटने से केवल ऋण ही ऋण नजर आ रहा है। माला के 108 मनके जपने से आस्था बढ़ती है लेकिन यहां 108 पेज पलटने से विश्वास कम हो रहा है। माला के 108 मनके जपने से समाधान मिलता है लेकिन यहां 108 पेज पलटने से समस्या ही समस्या नजर आ रही है, समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट के प्रस्तुत होने के बाद हिमाचल की जनता जो अब तक भ्रम में थी उनके सामने सच्चाई उजागर हो गई है।

पिछले 3 वर्षों से लगातार कहा गया कि हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा था और आज भी कह रहे थे कि वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक देश का सबसे अमीर राज्य बनेगा। हिमाचल प्रदेश की जनता को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट का सपना दिखाया गया था लेकिन दिनांक 21 मार्च को जब यहां पर बजट प्रस्तुत किया गया तो जनता का यह भ्रम पूरी तरह टूटता हुआ नजर आया। सरकार कह रही है कि आर्थिक स्थिति सुधर रही है लेकिन इस बजट में 3,586 करोड़ रुपये की कटौती स्वयं नाकामी की गवाही दे रही है। हर वर्ष की तरह इस बार भी अस्थायी आंकड़ों के सहारे स्थायी सुधार का भ्रम पैदा किया जा रहा है। बजट के आंकड़े अत्यंत चिंताजनक स्थिति प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ कहा जाता रहा कि राज्य आर0डी0जी0 और जी0एस0टी0 पर निर्भर है और 50 प्रतिशत से अधिक खर्च कर्ज के माध्यम से चल रहा है। केन्द्र से जो स्पेशल असिस्टेंस कैपिटल इन्वेस्टमैंट के रूप में मिलती है, उसके बारे में भी इस बजट में स्पष्ट लिखा है कि वह भी ऋण आधारित है हालांकि उसे 50 वर्ष बाद चुकाना होगा। इसका सीधा अर्थ है कि सरकार विकास नहीं कर रही, बल्कि कर्ज लेकर खर्च चला रही है।आज प्रदेश की स्थिति यह हो गई है कि हिमाचल को डेब्ट ट्रैप की ओर धकेला जा रहा है यानी पुराने कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ई0एम0आई0 पर चल रही है। हम जानते हैं कि जी0एस0टी0 कम्पन्सेशन वर्ष 2022 में समाप्त हो चुका है। मेरा सरकार से सीधा प्रश्न है कि जब यह स्पष्ट था कि आगे चलकर आर0डी0जी0 बंद होगी और जी0एस0टी0

23.03.2026/1915/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

कम्पन्सेशन भी समाप्त हो जाएगा तो पिछले 3 वर्षों में सरकार ने वैकल्पिक रेवेन्यू मॉडल क्यों विकसित नहीं किया। इन 3 वर्षों में सरकार ने कौन से दूरगामी कदम उठाए, यह सरकार से सीधा प्रश्न है। दुर्भाग्य यह है कि राज्य अपनी आय बढ़ाने के बजाय आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता गया और केवल बाहरी सहायता, विशेषकर केंद्र की स्कीमों पर ही निर्भर रहा।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

23-3-2026/1920/एन0एस-वाई0के0-1

श्री सुरेन्द्र शौरी-----जारी

सभापति महोदय, यहां पर लोक निर्माण मंत्री जी डॉ0 मनमोहन सिंह जी की प्रदेश के लिए उपलब्धियां गिना रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जब डॉ0 मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय विशेष राज्य का दर्जा भी हिमाचल से वापिस लिया गया था। यहां पर उप-मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग आज पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कहा जा रहा था कि 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' व विभिन्न योजनाओं के तहत 4,580 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार से मिली है। जब केंद्र राशि देता है तो उसका श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं और जब कोई योजना बंद होती है तो केंद्र सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं। पी0एम0जी0एस0वाई0 की 4,580 करोड़ रुपये की स्कीमें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार पैसा देती है तभी यहां पर सड़कें निकल रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस बजट में स्टेट बजट से पी0डब्ल्यू0डी0 के लिए क्या रखा गया है? मैं देख रहा था कि इस बजट से 'मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना' भी गायब है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इतनी बड़ा डिजास्टर आया और मंत्री जी, डिजास्टर के बाद आज भी 20 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। उनमें बसें भी नहीं चल रही हैं। उन सड़कों की आज भी

रिपेयर नहीं हो रही है। मेरा आज भी प्रश्न लगा है जिसमें मैंने पूछा था कि बन्जार में किन-किन रूटों पर बसें नहीं चल रही हैं? उत्तर में बताया गया है कि 16 सड़कों पर बसें नहीं चल रही हैं। सभापति महोदय, 4-5 सड़कें और हैं जिन पर बसें नहीं चल रही हैं। इसका उत्तर अधूरा है। ये बड़ी सड़कें हैं जो बस योग्य हैं लेकिन इसके अलावा भी 150-200 सड़कें 'मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना' से बनी हैं या पंचायतों के अपने रोड्ज हैं वे सारे-के-सारे बंद पड़े हुए हैं। आज हालात बहुत खराब हैं। अगर मैं जल शक्ति विभाग की बात करूं तो हमारी जितनी भी निर्माणाधीन योजनाएं हैं वे सारी ठप पड़ी हुई हैं और आपदा के बाद उनमें कोई काम नहीं हो रहा है। जो योजनाएं आपदा के समय टूटी थीं वे अभी तक वैसी ही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत दिक्क्त है। आने वाले समय में गर्मियों के मौसम में बन्जार की जनता को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

23-3-2026/1920/एन0एस-वाई0के0-2

सभापति महोदय, लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों की करोड़ों की देनदारियां लंबित हैं। आज करोड़ों रुपये के बिल ट्रेजरी में फंसे हुए हैं। वे सब लोग आज संकट में हैं। इस बजट के अंदर घोषणाएं तो बहुत आकर्षक की हैं। 'राजीव गांधी स्टार्ट- अप योजना' का जिक्र हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा कि 'मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना' के तहत पूरे प्रदेश में बहुत सारी स्कीमों के लिए पैसा दिया गया था। उनमें नौजवान अपना रोजगार भी शुरू करते थे और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देते थे लेकिन उनकी सब्सिडी वर्ष 2022 से बंद पड़ी हुई है। इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है। वे लोग परेशान हैं। हमारे उद्यमी जिन्होंने होम स्टे बनाए हैं, मशीनें खरीदी हैं या कुछ और कारोबार शुरू किया है तो वे लगातार हमें फोन करते हैं और पूछते हैं कि हमारी सब्सिडी कब रिलीज होगी? आज तीन वर्ष हो गए हैं। सभापति महोदय,

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

23.03.2026/1925/RKS/YK-1

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी...

मार्च, 2023 में यहां जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की बात की गई थी। उसके दो महीने के बाद बंजार विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए जगह देखी गई। वन और राजस्व विभाग के अधिकारी वहां पर जगह चिन्हित करते हैं। आज तीन साल से ज्यादा का समय होने वाला है लेकिन इन तीन सालों में उस जमीन की ऑनलाइन FCA क्लीयरेंस नहीं हो पाई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अब यह स्कूल कब और किस चरण में खुलेगा? यानी कि इनकी हर योजना चरणबद्ध तरीके से ही चल रही है। FCA क्लीयरेंस के लिए तीन साल लगेंगे फिर उसके बाद बजट सैंक्शन होगा यानी इनकी सारी-की- सारी कोरी घोषणाएं हैं। इस बजट के अंदर घोषणाएं तो बड़ी-बड़ी की गई हैं लेकिन उसकी नींव हमें बहुत कमजोर दिख रही है। सहारा, हिमकेयर जैसी योजनाएं जो जन कल्याणकारी थीं, वे राजनीतिक द्वेष के कारण इस बजट के अंदर पूर्णतः खामोश पड़ी है। कृषि और बागवानी क्षेत्र में सरकार ने केवल घोषणाएं ही की हैं लेकिन उनको धरातल में उतारने के लिए सरकार ने कोई समाधान नहीं निकाला है। आज सब्सिडी की करोड़ों की देनदारियां लंबित पड़ी हैं लेकिन इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। उपकरणों की खरीद का भुगतान अटका पड़ा हुआ है लेकिन उसका भी कोई जिक्र नहीं है। किसानों को राहत देने का कोई स्पष्ट समाधान हमें इस बजट में नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे जब सरकार का समय कम होता जा रहा है तो इन्होंने जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। रोजगार के अवसर प्रदान करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए हमें दिशा का अभाव नजर आ रहा है। हमें औद्योगिक विकास भी कमजोर ही नजर आ रहा है। हमें रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस और स्पष्ट नीति नजर नहीं आ रही है। इस बजट में चरणबद्ध तरीके से लगभग 2000 सरकारी पदों की भर्ती की बात की गई है लेकिन पिछले बजट में घोषित एक वर्ष के अंदर 25000 सरकारी नौकरियों का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि जो चरणबद्ध तरीके से नौकरियां

देने की बात की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह चरण वर्ष 2027 के बाद ही इस प्रदेश के

23.03.2026/1925/RKS/YK-2

अंदर पड़ेंगे। मैं देख रहा था कि पिछले बजट के अंदर पंचायत सचिवों के 853 पद भरने की घोषणा की गई थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोबारा 300 पद भरने की घोषणा की गई लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ 150 पद ही भरे जा रहे हैं। यानी बजट में जो कहते हैं उसका सारा आंकड़ा धरातल में कम उतरता नजर आता है। इसी तरह से अगस्त, 2023 में पटवारियों के 873 पद भरने का निर्णय लिया गया लेकिन इन पदों की संख्या भी कम करके 645 कर दी गई। युवाओं को राज्य चयन आयोग के द्वारा इग्जामिनेशन फीस में किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई। चुनावों के समय युवाओं के लिए प्रत्येक जिला में सरकारी कोचिंग सेंटर्ज खोलने की बात कही गई थी लेकिन इस बात पर भी बजट में कोई विचार नहीं किया गया है। इस बजट में यह बात सामने आई है कि वेतन के लिए 100 रुपए में से 27 रुपये, पेंशन के लिए 21 रुपये, ब्याज की अदायगी के लिए 13 रुपये, ब्याज पर 13 रुपये, ऋण अदायगी पर 9 रुपये और स्वायत्त संस्थाओं की ग्रांट के लिए 10 रुपये का प्रबंध किया गया है लेकिन जो प्रदेश के विकासात्मक कार्य होने हैं उनके लिए सिर्फ 20 रुपये का ही प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष इन पूंजीगत कार्यों के लिए 100 में से 24 रुपये का प्रावधान किया गया था। मैं देख रहा हूं कि जब गत वष विकास कार्यों के लिए 100 में से 24 रुपये का प्रावधान किया गया था तब भी प्रदेश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

23.03.2025/1930/बी.एस./ए.जी.-1

श्री सुरेन्द्र शोरी जारी...

यही पूंजीगत कार्य 100 में से 24 पर था। मैं देख रहा हूं कि पिछले 1 वर्ष के अंदर जब 24 रुपये था तब भी प्रदेश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। यहां तक कि स्थिति यह बनी कि विभिन्न विभागों से पैसा वापस लिए गया। एस0डी0पी0 का पैसा, बैकवर्ड सबप्लान का पैसा, जो अलॉट भी हुआ था, विकास में जन सहयोग का पैसा जिला कार्यालय में पहुंच भी चुका था और वहां से डिस्पर्स होकर के ब्लॉकों में जा चुका था उस पैसा को भी सरकार ने वापस लिया।

मेरी विधान सभा में तो एक अजीब स्थिति हो गई। एक काम को शुरू भी कर लिया था। जैसे बी0डी0ओ0 को पता चला कि पैसा आ गया है, मस्ट्रोल निकाल कर काम शुरू किया। जब पेमेंट होनी थी तो पता चला कि वह पैसा वापस चला गया। जो वहां पर काम कर रहे थे, लेबर लगी थी, वह सारे हैरान हो गए। यानी कि इस तरह ब्लॉक स्तर तक पहुंचा हुआ पैसा भी पिछले वर्ष वापस लिया गया और यह मनरेगा का नहीं परंतु विकास के कार्य का पैसा था, एस0सी0डी0पी0 का पैसा था। बैकवर्ड सबप्लान का पैसा था।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस बार तो वह 20 रुपये है। अब आगे क्या हालत होगी। अभी मैंने कुल्लू के अंदर एक डिजास्टर के लिए डी0सी0 ऑफिस में फोन किया कि बहुत जगह पैसे की बहुत जरूरत है, यहां पर डिजास्टर हैड से एक लाख रुपये नहीं तो 75 हजार रुपये सैंक्शन कर दीजिए। तो मालूम पड़ा कि सारा पैसा जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में कुल्लू में पहुंचा था, वह भी वापस ले लिया गया है। यह बहुत हैरानी की बात है। अध्यक्ष महोदय, मिसमेनेजमैंट कैसे होती है? ...(घंटी)...बंजार के अंदर डिजास्टर आया परंतु सड़क और पुलिया ठीक करने के लिए पैसा नहीं है। परंतु कुल्लू के डी0सी0 ऑफिस में ही, हमारा डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिस आलीशान बना दिया गया। मैं 5 साल से देख रहा हूं वहां पर 32 लाख रुपये उसको सजाने-संवारने के लिए लगा दिए गया।

एक तरफ सरकार पैसे का रोना रो रही है और दूसरी तरफ ऐसी फिजूलखर्ची कर रही है। कितनी हैरानी की बात है? गांव का एक प्रधान डिजास्टर के मौके पर एक रास्ता

23.03.2025/1930/बी.एस./ए.जी.-2

ठीक करने के लिए एक लाख के लिए तरस रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरह की है कि एक छोटे से कार्यालय के रिनोवेशन पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं। ...(घंटी)... इसलिए मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, और बताना चाहता हूं कि अपने एक्सपेंडिचर को ठीक कीजिए। कहां जरूरत है पहले यह तय कीजिए। जो अफसर पैसे को ऐसे फिजूल खर्च करते हैं, उनकी जवाबदेही तय कीजिए। उनकी सैलरी से वह पैसा कटना चाहिए जो फिजूल जगह खर्च हो रहे हैं।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुरेन्द्र शौरी : सभापति महोदय, मुझे कुछ और विषय के ऊपर की अपनी बात कहनी है कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। आपके ससुराल भी वहीं पर तो मेरा विशेष ध्यान रखें। मैं सरकार की नीतियों को लेकर बहुत हैरान हूं कि बहुत सी झूठी गारंटिया दी गई थीं। उनको पूरा करने के लिए जहां-जहां मुख्य मंत्री के दौरे हुए वहां-वहां कहा गया कि 1500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। कुल्लू में बंजार के तीर्थन क्षेत्र में आए। वहां की 6-7 पंचायतों की महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की और वह भी एक बार मिले। बाघी पुल में गए वहां भी एक बार ही यह पैसे मिले, कुछ दो-चार पंचायतों की महिलाओं को ही यह राशि मिली। इसी प्रकार लाहौ-स्पीति और डोडराक्वार में भी मिले। क्या इतनी बड़ी सरकार कोई स्थायी नीति नहीं बना सकती है? इस बार चौथी साल में जाग गये और कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश का सर्वे होगा और पूरे प्रदेश के अंदर सबसे गरीब महिलायें होंगी उनको यह लाभ मिलेगा। अच्छी बात है, लेकिन मुझे यह भी बताना है कि जिन पंचायतों में यह पैसा दिया गया, वहां पंचायतों द्वारा दी गई सूची के आधार पर पैसे मिले और उन्हीं महिलाओं को पैसे मिले जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। यहां तक कि जिनके घर में सरकारी नौकरी पर भी हैं। उस परिवार की महिला को भी एक किश्त 4500 रुपये की मिल गई। पूरे प्रदेश की महिलाओं ने क्या गुनाह किया है? घोषणा तो पूरे प्रदेश के लिए की गई थी कि सभी महिलाओं को यह लाभ मिलेगा। लेकिन अगर पहले साल 2 लाख गरीब महिलाओं को चिन्हित करके दिया जाता, तो हम उसका स्वागत भी कर सकते थे।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

23.03.2026/1935/डीटी/एजी-1

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी...

तो हम आपका स्वागत भी कर सकते थे कि पूरे प्रदेश को एक क्राइटेरिया फिक्स किया। यानी जहां माननीय मुख्य मंत्री के चरण पड़ेंगे वहीं पर यह घोषणा लागू होगी, वहीं की महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे। यह कैसी नीति है? इसलिए सभापति महोदय, यहां पर लोक निर्माण मंत्री जी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा के अंदर विधायक प्राथमिकता के बजट की लिमिट बढ़ाई गई है लेकिन इसका फायदा क्या है? हमने तीन सालों में बड़ी मुश्किल से सड़कों की DPR बनाई। तीन तीन साल FCA क्लीयरेंस के लिए लगे उसके बाद इन योजनाओं को बड़ी मुश्किल से नबार्ड में पहुंचाया। जल शक्ति और 4-5 सड़कों की योजनाएं प्लानिंग को वापस कर दी गई और तीन सालों में एक भी सड़क हमारी विधान सभा की नहीं निकाली गई। वैसे तो विधायक प्राथमिकता की लिमिट में बंजार विधान सभा के लिए 100 करोड़ है लेकिन उस लिमिट का हम क्या करेंगे हम जब नबार्ड से उन योजनाओं की सैंक्शन नहीं होगी। वहां पर मुख्य मंत्री जी का आदेश चलता है कि सिर्फ इन-इन विधायकों की स्कीमें नाबार्ड को प्रेषित की जानी चाहिए। इस बजट के अंदर नदौन और देहरा विधान सभाओं का ही जिक्र किया गया है और बाकी पूरे प्रदेश को फेरा दिया गया है। यानी कि जो भी डवलपमेंट होगी वह दो विधान सभाओं में ही होगी। नदौन में Integrated Park, पर्यटन परिसर, multi purpose sports complex, sports harvesting management करोड़ों रुपयों की योजनाओं की झड़ी लगा दी गई है। वहां पर टूरिज्म क्षेत्र में भी काफी कामों की घोषण की गई है। मेरा विधान सभा क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है और हमारे जिले के अधिकतर लोग टूरिज्म पर आधारित है। लेकिन इस बजट में बंजार का कहीं जिक्र नहीं है। वहां पर टूरिज्म का काम बहुत अच्छा चलेगा, चाहे वह पैराग्लाइडिंग का स्कॉप हो, rock climbing का हो, चाहे fishing का हो

यानी कि हर दृष्टि से मेरी विधान सभा में टूरिज्म की काफी संभावना है लेकिन इस बजट के अंदर कोई भी जिक्र नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमने लारजी के पास वाटर स्पोर्ट्स का एक कैफेटेरिया बनाया था। वहां पर सड़क ठीक की गई

23.03.2026/1935/डीटी/एजी-2

थी। उस डेस्टिनेशन को विकसित करने के लिए 18 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर दी गई है। यह कैफेटेरिया वर्ष 2022 में बनकर तैयार हुआ लेकिन तीन साल से सरकार सोई पड़ी है और उस कैफेटेरिया की कोई सुध नहीं ली। जो कैफेटेरिया 6 करोड़ रुपये की लागत से वहां बनाया गया वह भी खंडहर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 18 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद एक टूरिज्म का डेस्टिनेशन हम तैयार कर रहे हैं और उसकी कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो फिर सरकार को रेवेन्यू कहां से आएगा? इसलिए आपको अपना आर्थिक प्रबंधन ठीक करना पड़ेगा। सभापति महोदय, अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो सरकार को वित्तीय अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। सरकार के वायदे चुनाव तक ही थे और इसकी सच्चाई इस बजट में सामने आ गई। जनता ने विकास मांगा था लेकिन सरकार बहाने लेकर आई है। इसलिए सभापति महोदय, मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। यह बजट विकास का नहीं बल्कि कर्ज भ्रम और खोखली घोषणाओं का बजट है। यह बजट केवल मात्र आंकड़ों का व्याख्यान और विश्व की कल्पना का चित्रण मात्र है। बजट में मुश्किलों का तो खूब जिक्र किया गया है पर उपचार की कोई बात नहीं की गई है। इसलिए मैं इस बजट का दृढ़तापूर्वक विरोध करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

23.03.2026/1935/डीटी/एजी-3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी भाग लेंगे।

श्री किशोरी लालः आदरणीय सभापति महोदय, दिनांक 21.03.2026 को हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा में अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि यह बजट प्रदेश की जनता के हित में है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनके हित में है। किसानों और नौजवानों के हित में है क्योंकि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी.....

23.03.2026/1940/ए.एस.-एन.जी./1

श्री किशोरी लाल..... जारी

ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, उनके हित में है और किसानों व नौजवानों के हित में है क्योंकि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है।

सभापति महोदय, 3 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी और उससे पहले जो सरकार थी यानी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वह प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज और 11,000 करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़कर गई थी। विपक्ष के लोग बार-बार कर्ज की बात करते हैं लेकिन अपने समय की बात नहीं करते। इन्हें 5 सालों में आर0डी0जी0 तथा जी0एस0टी0 कलेक्शन से 75,000 करोड़ रुपये से ऊपर का राजस्व मिला और ये उस वक्त चाहते तो प्रदेश के कर्ज को कम कर सकते थे लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और प्रदेश पर कर्ज बढ़ता चला गया। ये जो पिछले तीन साल निकले हैं, उसमें वर्ष 2023 में भारी वर्षा हुई जिससे भारी नुकसान हुआ। लगभग 500 जानें भी गईं, सड़कें टूटीं, पुल बह गए और लोगों के खेत/बगीचे बर्बाद हो गए। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपये का पैकेज दिया। उस वक्त प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपये से ऊपर का नुकसान हुआ था और केंद्र सरकार से कोई भी भरपाई नहीं हुई। उसके बाद वर्ष 2025 में भी भारी नुकसान हुआ। केंद्र से उम्मीद थी कि कुछ पैसे मिलेंगे लेकिन कोई पैसे नहीं मिले।

प्रदेश में जिन लोगों के घर चले गए, वे तबाह हो गए। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से मुआवजा राशि को बढ़ाया और 8-8 लाख रुपये तक जिनके घर तबाह हुए थे, उन्हें दिए गए। देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी प्रदेश के दौरे पर आए और 1500 करोड़ रुपये की घोषणा करके गए। आज तक हम इंतज़ार में हैं कि 1500 करोड़ रुपये कब मिलेंगे क्योंकि यह देश के प्रधान मंत्री जी के बोल थे। वह पैसा हिमाचल प्रदेश को आज तक पैसा नहीं मिला। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से प्रदेश को आगे बढ़ाया है।

23.03.2026/1940/ए.एस.-एन.जी./2

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1952 से लगातार मिलती आ रही आर0डी0जी0 को समाप्त कर दिया गया। आर0डी0जी0 को बंद करना स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 275(1) तथा 280(3) (बी0) की भावना के विपरीत है। सोलहवें वित्त आयोग ने राज्य की भौगोलिक स्थिति को नज़रअंदाज़ किया। उन्होंने यह नहीं देखा कि प्रदेश में नदियां हैं, वन हैं, पहाड़ हैं और कोई इंडस्ट्री नहीं है। आर0डी0जी0 राजस्व घाटे को पाटने के लिए एक निधि थी जिसे बंद कर दिया गया। यह तब बंद की गई जब सोलहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को पास किया गया। 16वें वित्तायोग ने अपनी सिफ़ारिशें महामहीम राष्ट्रपति महोदया को दी थीं और उन्होंने उन्हें देश की संसद में भेज दिया तथा संसद ने उनकी सिफ़ारिशों के अनुसार आर0डी0जी0 को बंद कर दिया। केवल आर0डी0जी0 ही बंद नहीं हुई है बल्कि इसके साथ जी0एस0टी0 कंपनसेशन से जो रेवेन्यू मिल रहा था, वह भी बंद हो गया। जी0एस0टी0 कंपनसेशन के बंद होने के बावजूद भी प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर प्रति वर्ष 8000 करोड़ रुपये से ऊपर की धनराशि मिलती थी। पिछले 4 वर्षों से जी0एस0टी0 कम्पेन्सेशन, जिसकी राशि 25,000 करोड़ से ऊपर बनती है, वह भी बंद हो गई और इससे प्रदेश को काफी नुकसान हुआ। इसके बावजूद प्रदेश सरकार और आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बजट में प्रावधान किया। प्रदेश के उन लोगों के लिए, जिन्हें आज तक

कोई प्रोत्साहन नहीं मिला था—दूध उत्पादक, गाय-भैंस पालने वाले और खेती-बाड़ी करने वाले लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री जी ने बजट में उन परिवारों के लिए, जो दूध बेचकर अपने रोजगार को चलाते हैं

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

23.03.2026/1945/ए0एस0/ए0पी0/-01

श्री किशोरी लाल जारी .....

जिन लोगों को आज तक कोई प्रोत्साहन नहीं मिला और वे दूध उत्पादक थे, गाय-भैंस पालते थे और खेतीबाड़ी का काम करते थे। उनका एक भी पैसा भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने नहीं दिया था। लेकिन वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने बजट में ऐसे परिवारों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जो दूध और पशुपालन के माध्यम से अपना रोज़गार चलाते हैं। गाय के दूध का समर्थन मूल्य 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये कर दिया गया और भैंस के दूध का मूल्य 71 रुपये तक पहुंचाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी सहकारी समितियां स्थापित की जा रही हैं, जिससे दूध का संग्रहण किया जाएगा। साथ ही डगवार में एक बहुत बड़ा मिल्क प्लांट प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश सरकार का बजट उन लोगों के लिए है जिन्हें आज से पहले कोई लाभ नहीं मिला। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूं, मक्का, पांगी घाटी में जौ की फसलें और हल्दी पर समर्थन मूल्य (एम0एस0पी0) दिया जा रहा है। गेहूं के एम0एस0पी0 को 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये, मक्का का समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर के 50 रुपये, पांगी क्षेत्र के जौ का समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये और हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये करना किसानों के हित के लिए प्रदेश सरकार का सीधा प्रयास है। इसके अलावा हिमाचल

प्रदेश किसान आयोग का गठन भी किया गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ, यह भी प्रदेश सरकार का सराहनीय काम है। कृषि सुरक्षा के लिए मुख्य मंत्री खेत बाड़बंदी योजना में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार किसानों के हितैषी है। बागबानी क्षेत्र में एच0पी0 शिवा योजना के तहत लगभग 1292 करोड़ रुपये की अनुमानत लागत से बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना जिलों के 52 विकास खण्ड़ों में करीब 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में 400 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। जिससे 15,000 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना में शत प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार वहन करती है और बागबानों को कोई आर्थिक बोझ नहीं उठाना

23.03.2026/1945/ए0एस0/ए0पी0/-02

पड़ता है। इसके अलावा, एच0पी0 शिवा योजना के अंतर्गत 102 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिनमें 99 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं शुरू हो चुकी हैं और 43 योजनाएं को वर्ष 2026-27 तक पूरा किया जाएगा। इन योजनाओं के लिए वर्ष 2026-27 में लगभग 325 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, प्रदेश में मत्स्य पालन का काम करने वाले 550 युवाओं को रोजगार दिया गया है और मछवारों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना शुरू की गई है। जलाशयों से पकड़ी जाने वाली मछलियों पर रॉयल्टी जोकि पहली सरकार के समय 15 प्रतिशत थी, उसे घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे मछुआरों को सीधा लाभ मिलेगा। ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में 5.5 करोड़ रुपये की लागत से 100 नई ट्राउट इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इससे नौजवान युवाकों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अंतर्गत उल्लेखनिय सफलता प्राप्त की है। इस योजना से 300 महिला मण्डल, 70 युवक मण्डल और 75 अन्य सहायता समूह द्वारा लगभग 1100 हेक्टयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। जिससे प्रत्येक सहायता समूह को प्रति हेक्टयर 1 लाख 20 हजार रुपये दिये जा रहे है। आय बढ़ाने के लिए मुख्य मंत्री वन विस्तार योजना से युवाओं को फायदा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी घोषित किया है तथा बनखंडी में एक बड़ा

जूलॉजिकल पार्क का निर्माण किया है जिससे पर्यटन आकर्षित होंगे और उन्हें बढ़ावा मिलेगा।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

23.03.2026/1950/AT/DC/01

श्री किशोरी लाल जारी...

अगर कांगड़ा विकसित होता है तो हमीरपुर भी साथ में विकसित होगा। कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण चल रहा है जिस पर 3349 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण लागत के रूप में व्यय किए जा रहे हैं।

सभापति महोदय, राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2023 से युवाओं को 50 प्रतिशत पर ई-टैक्सी खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार ने रखा हुआ है। गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन के कारण हिमाचल प्रदेश वर्ष 2021 में 21वें स्थान पर था जबकि वर्ष 2025 के सर्वे में हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर आ गया है। इसमें क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू किया गया है। इससे लोगों का सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ेगा और लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। इसके लिए भी सरकार प्रयासशील है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए 1000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जा रही है। प्रदेश सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। यह लोगों की चुनी हुई सरकार है और लोगों की जो भी समस्याएं सरकार के सामने आती हैं तो उनका पूरा ध्यान रखा जाता है तथा उनके कल्याण के काम किए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बजट लोगों के हित में है और इससे प्रदेश में तरक्की होगी, प्रदेश खुशहाल होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य पिछले 5 साल में रहे उन्होंने क्या काम किया? 5 साल में उन्होंने कर्ज लिया, किया तो कुछ भी नहीं। कर्ज का बोझ बढ़ता गया। सब एक ही हांडी के चट्टे-बट्टे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप मिलकर काम करें और प्रदेश हित में काम करें। जो अनुदान राशि बंद हुई है, उसे दोबारा दिलाने में मदद करें, ताकि प्रदेश आगे बढ़े। यह हमारा हक था जिस

पर कैंची चला दी गई। इस हक को आप दिलाइए तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। यह बिल्कुल साफ है कि 5 सालों में आपने जो काम किया वह हमारे सामने है। यहां आकर आप रोना रोते रहते थे कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। कोरोना में आपने क्या किया? जो मरीज बीमार होता था उसे कोविड सेंटर में ले जाते थे। वहां इलाज नहीं होता था, डॉक्टर दूर से दवाइयां फेंकते थे। कई लोग मर गए ... (व्यवधान)

23.03.2026/1950/AT/DC/02

Chairman : Please don't disturb.

श्री किशोरी लाल : कई लोगों के गहने उतर गए ऐसा हाल हमने देखा। लेकिन आप लोग घंटियां, शंख और थालियां बजाते रहे। क्या उससे कोरोना भाग जाना था? अपने कार्यकाल की बात करो। प्रदेश सरकार तो लगातार काम कर रही है और करती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश का बजट है और मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत बढ़िया बजट प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश की जनता को बहुत अच्छा बजट दिया है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

23.03.2026/1950/AT/DC/03

सभापति : अब चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री दीप राज जी।

श्री दीप राज : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2026-27 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इसकी शुरुआत शायरी से करता हूं

अंधेरों से कह दो अपनी हद में रहें,
मेरे हौसलों की लौ अभी बुझी नहीं है।

जो कहते हैं भविष्य अंधकार में है मेरा,
उन्हें बता दो सूरज की किस्मत मेंए
अभी रात लिखी नहीं है।

सभापति महोदय, इस वर्ष का बजट कल्पनाओं का बजट है, कहानियों का बजट है, अहंकार का बजट है और चमत्कार का बजट है। यह आत्मनिर्भर बनाने के बजाय कंगाल बनाने वाला बजट है। यह आम आदमी की जेब काटने वाला बजट है। और सबसे बड़ी बात यह अनुसूचित जाति के लोगों के विरोध का बजट है। यह टैक्स पर टैक्स लगाने वाला बजट है। सभापति महोदय, टैक्स दो प्रकार के होते हैं एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जहां टैक्स पर टैक्स लगाया जाता है उसे सेस कहा जाता है। सबसे पहले, सत्ता पक्ष बार-बार कहता है कि इन्होंने मिल्क सेस लगाया और दूध का रेट 61 रुपये बढ़ाने की बात की।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी....

23.03.2026/1955/केएस/डीसी/1

श्री दीप राज जारी ---

मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश की पिछले वर्ष की मिल्क प्रोडक्शन है, उसमें -4.10 परसेंट की डिक्रीज़ आई है यह आपके बजट में लिखा है। 17.50 मीट्रिक टन दूध का आंकड़ा इस वर्ष का आपका इसमें है। वर्ष 2022 में 70 प्रतिशत गाय का दूध, 27 प्रतिशत भैंस का दूध और 3 प्रतिशत बकरी का दूध होता था लेकिन आज इतनी सुविधाएं, इतनी कीमत बढ़ाने के बावजूद भी 71 प्रतिशत गाय, 26 प्रतिशत भैंस और मात्र 3 प्रतिशत बकरी का दूध एकत्रित किया जाता है जो कि पेज न0 23 में लिखा है। गांव में मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज भी 30 से 35 रुपये प्रति लीटर खरीदा जा रहा है। आपने रेट तो बढ़ाया लेकिन क्या आपने सर्वे किया कि हमारे दुग्ध पालकों को उचित मूल्य मिल भी रहा है या नहीं? यह फैट और एस0एन0एफ0 की वजह से नहीं मिल रहा है। सर्वे होना चाहिए था और डाटा

प्रोसैसिंग मिल्क कलैक्शन यूनिट्स स्थापित किए जाने चाहिए थे। दूध की गुणवत्ता, वजन की गुणवत्ता जानकर उसी समय पर्ची दे देते ताकि लोगों के मन में कोई संशय नहीं रहता। इसके अलावा पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक मिल्क एनालाइज़र भी गांव में फैट और एस0एन0एफ0 की तुरंत जांच करता है। इसके लिए आपने काई कदम नहीं उठाए। क्या रेट बढ़ाने के अलावा लोगों की गुणवत्ता किस तरह से बढ़े यह देखा? मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुफरीधार, तेब्बण, छंड्यारा आदि क्षेत्र के लोगों को 31-32 रुपये किलो दूध के मिल रहे हैं।

सभापति महोदय, मछुआरों की बड़ी बात की जाती है। वर्ष 2025-26 में मच्छली पालन में -35.60 प्रतिशत डाउनफॉल हुआ है और यह भी इसी बजट में लिखा है। मैं ट्राउट फिश की अगर बात करुं तो वर्ष 2025-26 में माइनस 70.49 परसेंट का ग्रोथ डाउन हुआ है। सभापति महोदय, ट्राउट फिश के लिए प्योर पानी चाहिए लेकिन भारी बारिश के कारण वह साफ पानी उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से लोग आपकी स्कीमों का लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं।

सभापति महोदय, ये योजनाएं ऐसी हैं जैसे केजरीवाल जी ने सभी बस स्टेंड्ज़ में वाई फाई दिया। वहां सिग्नल तो था परंतु स्पीड नहीं थी। स्पीड गायब और वैसा ही हाल इन योजनाओं का है। बजट में बार-बार हिमाचल प्रदेश के संसाधनों की बात की

23.03.2026/1955/केएस/डीसी/2

जाती है। बार-बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि पिछली सरकार ने बिजली के संसाधन बेचे। जब पहली बार एस0जे0वी0एन0एल0 प्रदेश में आया, यह वर्ष 1994 की बात है जब झाकड़ी में एन0जे0पी0सी0 हुआ करता था। वर्ष 1994 में प्रदेश में किसकी सरकार थी? 12.1 प्रतिशत का रेवन्यू जनरेट होगा, यह किसने निर्धारित किया था? यह कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि लागू करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो भी हमारे बिजली बोर्ड के प्रोजैक्ट्स हैं, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि एक तो डिपार्टमेंटली ट्रांसफर हो जाती हैं। फंड डाइवर्ट कर देते हैं इसके साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेटर्ज़ की कमी, मैनेजमैंट की भारी कमी

और बैंक का ट्रस्ट इशू सबसे ज्यादा रहता है। अगर मान लो हमने हाइड्रो का 1 हजार मैगावाट का प्रोजैक्ट लगाना है तो उसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये की लागत आती है जिसमें से 3 हजार प्रदेश सरकार करती है और 7 हजार बैंक देता है लेकिन बैंक की स्टेट्स की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। रेट हिमाचल में 2.50 रुपये दिया जाता है। बल्कि जम्मू कश्मीर में 6 रुपये, उत्तराखंड में 7 रुपये और लेह में 6 रुपये है। वर्ष 2024 में सरकार ने हाइड्रो प्रोजैक्ट को ले कर उआदरणीय जगत सिंह नेगी और सुन्दर सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी सका क्या हुआ? उसके तथ्य भी विधान सभा में रखे जाने चाहिए। मैं आपको बताऊं अगर हमें एस0जे0वी0एन0एल0 से कुछ लेना ही है तो हम उनका अनुभव, क्वालिटी कंट्रोल तथा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज़ का अनुभव लेते कि किस तरह से एस0जे0वी0एन0एल0 केंद्र सरकार की एक योजना है और उसकी वजह से आज वह इतनी बड़ा योजना पूरे देश में बन कर उभरी है।

सभापति : माननीय सदस्य,एक मिनट रुकिए। आप कितना समय लेंगे?

श्री दीप राज : सर, 15 मिनट का समय दे दीजिए।

सभापति : अब इस माननीय सदन की बैठक 15 मिनट और बढ़ाई जाती है।

श्री दीप राज : सभापति महोदय, एस0जे0वी0एन0एल0 में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत कम है। वहां किसी नेता का फोन करवाकर आप गलत काम नहीं करवा सकते। दूसरी बात, जहां-जहां ये प्रोजैक्ट लगे, रामपुर में झाकड़ी में लगा तो उस जगह में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, रोड बने, पार्क बने लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब यह प्रोजैक्ट

लगा तो करसोग में शाकरा पंचायत में, बिंदला, तलैन, मांजू-मंगान, सरत्योला, और शाउट आदि क्षेत्रों में ना सड़क बनी, ना सी0एस0आर0 फंड मिला ना कोई पार्क मिला ना स्कूल मिला।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

23.03.2026/2000/av/hk/1

श्री दीप राज------- जारी

न कोई पार्क मिला और न ही हमें कोई स्कूल मिला। ये सिर्फ और सिर्फ भेदभाव वाली राजनीति का कमाल है। हिमाचल प्रदेश ने शौंग-थौंग प्रोजैक्ट चलाया, सदन के अंदर बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं कि हमने यह प्रोजैक्ट चलाया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपको क्या आज भी उस प्रोजैक्ट से आय आ रही है? उस शौंग-थौंग प्रोजैक्ट को पूरी तरह से चलाने के लिए वहां पर एस0जे0बी0एन0एल0 के दो अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ा। जोगिन्द्रनगर के प्रोजैक्ट को बनाने के लिए आप लोगों को 22 वर्ष का समय लगा, हम लोगों को यह समझने की आवश्यकता भी है। हमें उनसे अनुभव और मैनेजमैंट सीखने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी की बातों से तो ऐसा लगता है कि वे मल्टी टास्क में एक्सपर्ट हैं। वे एक ही समय पर काम को टालना और चिंता न करना, इन दोनों कार्यों को कर सकते हैं। इस प्रदेश में अधिकतर संख्या युवाओं की है और आज हमारे प्रदेश में युवाओं का क्या हाल है वह आप खुद देख सकते हैं। यहां पर 4 प्रतिशत बेरोज़गारी अब 6 प्रतिशत तक पहुंच गई है यानी दो प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यहां पर 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के युवाओं में से 30 प्रतिशत युवा बेरोज़गार हैं यानी तीन में से हरेक युवा बेरोज़गार है। आपने बेरोज़गार भत्ता दिया है और उसके बारे में बजट में लिखा है। आपने इसमें लिखा है कि 5,18,807 युवा रजिस्टर्ड हैं और ये वे युवा हैं जोकि लेबर डिपार्टमैंट में रजिस्टर्ड होते हैं। मैं तथ्य के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी अपने आपको कभी रजिस्टर नहीं करवाया। हिमाचल प्रदेश के कम-से-कम 10 लाख बेरोज़गार युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपने आपको इस विभाग में रजिस्टर ही नहीं करवाया है। आपने क्या किया? आपने केवलमात्र 3717 युवाओं को बेरोज़गार भत्ता दिया। आपने लेबर सैस लगाकर 70 करोड़ रुपये की आय इण्डस्ट्रीयल एरिया से अर्जित की है। लेकिन उसके बावजूद जो पैसा आया उसको आप प्रदेश के युवाओं के बीच में सही रूप से वितरित नहीं कर पाए। आपने

राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना की बात कही है। आपने 4 करोड़ रुपये की राशि 56 भार्थियों को बांटी। सभापति महोदय, ये एक-एक विधान सभा क्षेत्र के खाते में एक युवा

23.03.2026/2000/av/hk/2

तो डाल देते ताकि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक युवा भी टैक्सी चला लेता। उसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि

हमारी केंद्र सरकार की एक योजना आर0ए0एम0पी0 है। यह भी बजट बुक में लिखा है कि यह केंद्र सरकार की स्कीम है तथा वर्ल्ड बैंक से इसकी फण्डिंग आती है। इसके तहत 1.80 करोड़ रुपये की राशि 700 महिलाओं को उद्योग हेतु वितरित की गई। उस हिसाब से प्रति महिला को 25 हजार रुपये की राशि मिली। अब आप ही बताइए क्योंकि 25 हजार रुपये से तो एक वर्ष के लिए एक कमरा भी किराये पर नहीं मिलता और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि इससे हमारे प्रदेश की महिलाएं सशक्त होंगी। यह किस प्रकार का सशक्तिकरण है? ये यहीं तक नहीं रुके, इसके अतिरिक्त आपने कहा है कि आपने मजदूरों की दिहाड़ी 750 रुपये कर दी है। अच्छी बात है लेकिन आपके वन मित्र, पशु मित्र आदि की सैलरी केवल 5 से 10 हजार रुपये ही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह लेबर लॉ का उल्लंघन नहीं है? सदन में बड़े जोर-जोर से कहा जा रहा है कि इनको इतनी-इतनी तनख्वाह दे दी गई।

आगे आने वाला समय ए0आई0 का है। ए0आई0 के समय में टैक्निकल और वोकेशनल जॉब्ज का टाइम पीरियड होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 की बिल्डिंग है। मैं कम-से-कम तीन वर्षों से यह बोल-बोलकर थक गया कि वहां का लोहा बिकने वाला है और उसके लिए पैसा दे दीजिए। परंतु इस बजट में उसके लिए कुछ नहीं मिला है। पिछली सरकार ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पॉलीटैक्नीक के लिए 4.16 बीघे और 40 लाख रुपये का प्रावधान किया था। परंतु इस बजट में उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि :-

कल्पनाओं और नींद के बवंडर में फंसे हैं प्रदेश के मसीहा,

प्रदेश के युवाओं को जो आपने सपने दिखाए थे,

उनको सच करने के लिए आपने क्या-क्या किया।

3.03.2026/2000/av/hk/3

सभापति महोदय, इन्होंने कुछ नहीं किया है। यहां पर बार-बार टूरिज्म की बात की जाती है। आज हमारे हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म की हालत देखिए। मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में 1.44 करोड़ लोग घूमने आए हैं जबकि उत्तराखण्ड में 6 करोड़ लोग आए। कोविड को छोड़कर अभी तक का यह -25.26 प्रतिशत सबसे ज्यादा डिक्रीज है। इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि होटल इण्डस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ऑन ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडिड 8.41 प्रतिशत है जोकि बजट बुक के पेज नम्बर 62 पेज पर लिखा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने होटल इण्डस्ट्री के लिए क्या कोई नयी योजना लाई जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में होटल चला रहे हैं? पहले यहां पर फोरेन टूरिस्ट्स बहुत आता था। पहले यहां पर 5 लाख विदेशी पर्यटक आते थे जबकि अब 85 हजार तक ही आते हैं। वे यहां पर कंक्रीट का शहर देखने के लिए नहीं आते थे, वे यहां यह देखने आते थे कि अंग्रेजों ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी क्यों बनाया था। उसके अलावा डायरैक्ट रूट से 46795 इण्डीविजुअल परिवार इसी से चलते हैं और यह आंकड़ा भी बजट बुक में ही दिया गया है। लेकिन मेरा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश में होटल इण्डस्ट्री और टूरिज्म से 10 लाख रोज़गार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पैदा होते हैं। लेकिन आपने क्या क्या? आपने टुरिज्म और एच0पी0टी0डी0सी0 के होटल्ज भी लीज़ पर दे दिए तथा दूसरी तरफ आपने टूरिज्म इण्डस्ट्री में अदर इन्कम के अंतर्गत यह इन्कम दिखाई है।

टी सी द्वारा जारी

23.03.2026/2005/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री दीप राज .. जारी

और दूसरी तरफ उसके संसाधन कम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, तत्तापानी हमारे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्थल है, जहां वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं और यह शिमला के नजदीक है। चंडीगढ़ से आने वाला पर्यटक सीधे शिमला पहुंचता है और वहां से तत्तापानी भी जा सकता है। लेकिन इस बजट में वॉटर स्पोर्ट्स के लिए एक रुपये का भी प्रावधान नहीं किया गया। हम सभी यहां बैठे हैं और अधिकांश लोग हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से शिक्षित हैं। सबसे अधिक बजट एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया जाता है। एच0पी0 स्कूल शिक्षा बोर्ड में 450 रिटायर्ड कर्मचारी हैं और 350 वर्किंग कर्मचारी हैं। वर्ष 2023 से जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से हर वर्ष एच0पी0 स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रदेश के स्कूलों को किताबें निःशुल्क देता है। पहली से आठवीं तक की किताबें सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाती हैं और नौवीं-दसवीं के लिए प्रदेश सरकार पैसा देती है लेकिन पिछले 3 वर्षों से आपने एच0पी0 शिक्षा बोर्ड की लगभग 80 करोड़ रुपये की पेमेंट नहीं की तो यह 18 प्रतिशत बजट एजुकेशन का आखिर कहां जा रहा है? आपने सी0बी0एस0ई0 की बात की, सी0बी0एस0ई0 स्कूल बदलने से कुछ नहीं होगा। बच्चों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासिस, प्ले ग्राउंड्स का क्या होगा?

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के घरमौड, काओ, सेरी, भंथल और महोग ऐसे स्कूल हैं जिनकी छतों से पानी टपक रहा है। हम स्कूलों की छतें तो ठीक नहीं कर पा रहे और स्मार्ट क्लासिस की बात कर रहे हैं। केरल में 18 प्रतिशत बजट एजुकेशन पर खर्च किया जाता है जबकि दिल्ली में 20 प्रतिशत बजट एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। प्रश्न यह है कि एच0पी0 स्कूल शिक्षा बोर्ड में ऐसा क्यो हो रहा है? हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड को सुधारने के लिए विजन और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज की आवश्यकता है। यह मैनेजमेंट की कमी है। यहां बैठे कई माननीय सदस्यों ने एच0पी0 स्कूल शिक्षा बोर्ड से शिक्षा ग्रहण की हैं। सी0बी0एस0ई0 और एच0पी0 बोर्ड में क्या फर्क है जबकि ये दोनों

एन0सी0ई0आर0टी0 को फॉलो करते हैं। आपको कुछ करना ही था तो इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए था।

23.03.2026/2005/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

आपने बजट में पानी की बात की और बजट में आर0ओ0 लगाने की बात कही गई लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में 163 पेयजल योजनाएं हैं जिनमें से केवल 60 वर्किंग हैं और 113 नॉट वर्किंग हैं। जुज्जर, शाकरा, सोरता सलाना, चैरा खड्ड -तमून, तुमण-चखाना और थली जैसी योजनाएं प्रभावित हैं।

सभापति महोदय, मैं एक शेर बोलना चाहूंगा :

अंधेरों के सौदागर उजाले की बात करते हैं।
नल से पानी तो ला नहीं सकते है और
हमें दिन में तारे दिखाने की बात की जा रही है।

सभापति महोदय, एच0आर0टी0सी0 की बात करें तो पिछले वर्ष इसकी इन्कम 912 करोड़ रुपये थी और इस वर्ष दिसंबर तक 752 करोड़ रुपये रही। आपने मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के 35 रूट बंद कर दिए। इन रूटों पर गरीब और जिन अंतिम व्यक्ति की यहां पर बात की जा रही थी, वे यात्रा करते थे। इससे चौरीधार, कटोल, स्याज, माहूनाग-करसोग वाया शैंथल, चैरा-करसोग, चैरा-परलोद जैसे रूट प्रभावित हुए। करसोग में एच0आर0टी0सी0 की मासिक इन्कम लगभग 10 लाख रुपये है लेकिन वहां बस स्टैंड पर शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। जो शौचालय बनाया गया है उसका गड्ढा तक नहीं बनाया गया। हर 15 दिन में टैंकर लाकर सफाई करनी पड़ती है और कई बार लोग इसके लिए मेरे पास पैसे मांगने आ जाते हैं। यदि सरकारी योजनाओं के लिए भी हमें अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े तो यह उचित नहीं है। मंत्री जी यहां 75 लाख लोगों के हित की बात करते है तो क्या करसोग की जनता उसमें शामिल नहीं है? ये आपके ही आंकड़ें है कि 75 लाख लोगों में से 24,86,066 वाहन हिमाचल प्रदेश के लोगों के है। इतने अधिक वाहनों के कारण ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही है। इस दिशा में भी निर्णय लेने की जरूरत है क्योंकि यहां अधिकतर गाड़ियां टूरिस्टों की नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की है।

अब सड़कों की बात करें तो सड़कों के लिए अधिकतर पैसा केंद्र सरकार की योजनाओं से आता है। यदि 40 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर सही ढंग से किया जाता तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिक प्रोजैक्ट जमीन पर उतर सकते थे। लेकिन समस्या यह है

23.03.2026/2005/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

कि गिफ्ट डीड देनी होती जिसमें उनके अपने पैसे लगते हैं और बैंकों से एन0ओ0सी0 नहीं मिल पाती है। इसलिए पी0एम0जी0एस0वाई सड़कों की अप्रूव्ल कम आती हैं। इस दिशा में मंत्री जी ने क्या कार्य किया और

एन0एस0 द्वारा ... जारी

23-3-2026/2010/एन0एस-वाई0के0-1

श्री दीप राज -----जारी

यहां हमें बड़ा पाठ पढ़ा रहे थे कि हमने 7500 करोड़ रुपये का बिल्कुल सही तरीके से आबंटन किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का रास्ता उनके विधान सभा क्षेत्र से ही जाता है। उनके अपने विधान सभा क्षेत्र जहां से वे जीत कर आते हैं वहां तो ये डंगे ही नहीं लगा पाए और हिमाचल प्रदेश में एक समानता की बात करते हैं। ये कैसा सम्मान है जो वे खुद के साथ सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह बजट उन्होंने खुद बनाया। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में अनुभव की कमी है। वे अपने साथ उप-मुख्य मंत्री जी, शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों को साथ लेते तथा इनसे राय-मशबिरा करते तो और अच्छा बजट बनता। इन्होंने इसको खुद ही बना दिया है। इसमें अनुभव की कमी, एक्सपीरियंस की कमी और मेनेजमैंट की कमी है और इसमें जनता के हित की कोई बात ही नहीं है। आप लोग भी सच्चे हैं और हम आपको क्या बोलें? मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सड़कें हैं जैसे पांगणा से चण्डयारा, शाना से वही-सरही, काण्डा से जननो, चिटा धारटू से खनेरी, नान से चौआ, शकेलड़ से नावीधार, बेल्लर से रेष्टाधार ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जिनके लिए बजट नहीं दिया गया है। मांजु-मजाण सड़क के लिए कोई बजट नहीं दिया गया है जहां आज तक भी सड़क नहीं पहुंची है।

सभापति महोदय, इस बजट में सबसे बड़ा अन्याय अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुआ है। मैं आपको बतना चाहता हूं कि वैल्फेयर योजना के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में 500 से 1000 फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं और लोगों को पिछले 3 वर्षों में 50 घर तक नहीं मिले हैं। रूप चंद जी, राम दास जी, हुकम चन्द, कमला देवी को घर नहीं मिले हैं। ये लोग मुझे कहते हैं कि विधायक जी, गरीबों की कोई नहीं सुनता है। सभापति महोदय, ये लोग सच कहते हैं। इस सरकार में गरीबों की कोई नहीं सुनता है। इस बजट में एक अच्छी बात हुई कि विधवा महिलाओं व अनाथ बच्चों के लिए पेट्रोल व डीजल में सैस लगाने की बात कही गई है। यह अच्छी बात है और आपकी मंशा अच्छी है। आपकी मंशा तो अच्छी है लेकिन हमें सरकार की कार्य प्रणाली पर संदेह होता है। आपको दान चाहिए तो वह भी स्वेच्छा से होता है किसी से जबरदस्ती दान नहीं लिया जाता है।

सभापति महोदय, अभिनय की दुनिया में एक बहुत बेहतरीन किरदार चतुररामालिंगम जी हुए हैं। मुझे लगता है कि उनकी कार्यप्रणाली से मुख्य मंत्री जी बहुत

23-3-2026/2010/एन0एस-वाई0के0-2

प्रभावित हैं क्योंकि वे बोलने में स्ट्रोंग हैं, प्लानिंग में हैवी हैं, एग्जीक्यूशन में जीरो हैं। यही हाल प्रदेश सरकार का है।

सभापति महोदय, यहां किसान आयोग की बात की गई। अच्छा लगा कि किसानों के हित के लिए कुछ तो आया। लेकिन जिन किसानों से पिछली बार 60 प्रतिशत सेब खरीदे गए थे उनको अभी तक पैसे नहीं मिले, उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया गया। आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि सेब का एम0एस0पी0 40 रुपये होगा। सभापति महोदय, बाहर के सेब का रेट 75 रुपये मिनीमम है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी 5,500 करोड़ रुपये की है तो पूरे देश की 26 लाख मीट्रिक टन की डिमांड है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 21 लाख मीट्रिक टन डिमांड है।

सभापति महोदय, आपने चिट्टे के उन्मूलन के लिए बहुत अच्छा काम किया कि एक एस0आई0यू0 का गठन किया। एस0आई0यू0 के गठन के बाद उसमें निरंतर बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि लगातार एक ही अधिकारी रहने से भ्रष्टाचार के कई मामले सामने

आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस टीम को सर्कुलेट किया जाए और अच्छे अधिकारियों/कर्मचारियों को इसमें लगाया जाए। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूंः-

पर्वतों को काटकर राह बनाने का दम रखते हैं हम,
घिर के तूफानों से उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं हम,
ये तो तरस आ जाता है हमें आसमान की खामोशी पे
वरना उसका भी सीना चीर कर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं हम।

सभापति महोदय, मैं इस बजट की कतई सराहना नहीं कर सकता हूं। यह बजट बरगलाने वाला, गुमराह करने वाला और दलित विरोधी है। मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

सभापति : अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, 24 मार्च, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांकः 23 मार्च, 2026 **सचिव।**